आवरण आलेख
सम-सामयिक
विचार
वैचारिक आलेखों का स्तम्भ

जीएसएलवी मार्क-III9 पहली विकासात्मक उड़ान

– सौरभ मेहरोत्रा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कामयाबियां लगातार देशवासियों के लिए फख्र का मौका बनी हैं। हाल में ऐसे गर्व के अवसर इतनी बार आए हैं कि अब इसरो की असाधारण सफलताओं पर किसी को आश्चर्य नहीं होता। वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 के बाद वर्ष 2013 में मंगलयान का प्रक्षेपण हो या जून, 2016 में एकल मिशन में 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के अपने ही रिकॉर्ड को एक वर्ष के अंदर ही ध्वस्त कर फरवरी, 2017 में 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाने की घटना या फिर अधिकतम 2.5 टन वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण की मौजूदा क्षमता में वृद्धि कर जीएसएलवी मार्क-III के द्वारा अब 4 टन तक के संचार उपग्रहों को लांच करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सफलता। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि इसरो की परियोजनाएं बीते कुछ समय में लगातार बड़ी और महत्वाकांक्षी होती गई हैं। कहावत है कि 'हर एक सफलता पहले से बड़ा लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षा भी देती है', दरअसल इसरो के साथ भी यही हुआ है। हालांकि सफलताओं के इस क्रम में इसरो के समक्ष कई चुनौतियां भी रहीं। उदाहरण के लिए मंगलयान मिशन। जब इसरो ने इस मिशन की घोषणा की थी तब किसी को इसकी सफलता पर पक्का यकीन नहीं था। तब तक एशिया में ही तकनीकी रूप से भारत से कहीं ज्यादा उन्नत माने जाने वाले चीन और जापान जैसे देश कोशिश करने के बावजूद मंगल अभियान में सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे। चीन का पहला मंगल मिशन 'यिंगहुओ-I' (Yinghuo-I) नवंबर, 2011 में असफल हो गया था। इसी तरह वर्ष 1998 में जापान का मंगल अभियान भी ईंधन खत्म हो जाने के कारण नाकाम हो चुका था। भारत के पहले विश्व में सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ही कई कोशिशों के बाद मंगल पर कामयाब मिशन भेज पाए थे। लेकिन इसरो ने सभी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए नवंबर, 2013 में प्रक्षेपित मंगलयान को पहले ही प्रयास में सितंबर, 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया।

इसी तरह भू-तुल्यकालिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम जीएसएलवी (GSLV : Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) के विकास हेतु 'क्रायोजेनिक तकनीक' में महारत हासिल करने की दिशा में इसरो को न केवल तकनीकी चुनौतियों बल्कि भू-राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन तमाम अवरोधों एवं चिंताओं से उबरते हुए इसरो ने न केवल स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में सफलता प्राप्त की, बल्कि इस इंजन से लैस जीएसएलवी मार्क-III द्वारा अब भारत को 4 टन वजनी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बना दिया है।

❑ क्या है क्रायोजेनिक तकनीक?

क्रायोजेनिक्स (Cryogenics) भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में, क्रायोजेनिक्स शब्द का उद्‌भव यूनानी शब्दों क्रायोस (Kryos) तथा जेनिक से हुआ है। क्रायोस का अर्थ है–'बर्फ जैसा ठंडा' जबकि जेनिक का अर्थ है–'पैदा करना' (To produce)। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नीदरलैंड्स के प्रोफेसर 'केमर्लिंग ओन्नस' (Kamerlingh Onnes) ने 1894 ई. में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी स्थायी गैसों के शीतलन द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया था। दरअसल, क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। क्रायोजेनिक तकनीक शून्य से 238 डिग्री फॉरेनहाइट कम ताप पर कार्य करती है। -238^{o}F (-150^{o}C) से नीचे के तापमानों के संदर्भ में ही सामान्यतः क्रायोजेनिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है।

क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहां गैसीय ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। रॉकेटों के क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों (Liquefied Gases) को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रायः इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। रॉकेट के ठोस एवं द्रव प्रणोदक संचालित चरणों की तुलना में क्रायोजेनिक चरण कई गुना अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते हैं और रॉकेट को अधिक ठेल (Thrust) प्रदान करते हैं।

हालांकि अत्यधिक निम्न तापमानों पर प्रणोदकों (Propellants) के प्रयोग तथा संबद्ध तापीय एवं संरचनात्मक समस्याओं के चलते क्रायोजेनिक चरण, ठोस या द्रव प्रणोदक संचालित चरणों की तुलना में तकनीकी रूप से एक बहुत जटिल प्रणाली है। ऑक्सीजन -183^{o}C तथा हाइड्रोजन -253^{o}C पर द्रवीभूत होती है। इतने कम तापमान पर इन प्रणोदकों का प्रयोग आसान नहीं होता। इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि ये बहुत जल्दी वाष्प बन जाते हैं। इन्हें अन्य प्रणोदकों की तरह रॉकेट खंडों में नहीं भरा जा सकता। इन्हें क्रायोजेनिक इंजन के दहन कक्ष में पहुंचाने के लिए टर्बो पंप (Turbo Pumps) का प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को दहन कक्ष तक पहुंचाने में जरा-सी भी गलती होने पर करोड़ों रुपये की लागत से बना रॉकेट रास्ते में जल सकता है। इसके अलावा दहन के पूर्व प्रणोदकों (हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन) को सही अनुपात में मिश्रित करना, सही समय पर दहन प्रारंभ करना, उनके दबावों को नियंत्रित करना, पूरे तंत्र को गर्म होने से रोकना आदि सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं।

PSLV-XL, GSLV मार्क-II एवं GSLV मार्क-III : एक तुलनात्मक अध्ययन

	PSLV-XL	GSLV मार्क-II	GSLV मार्क-III
ऊंचाई	44 मीटर	49 मीटर	43.43 मीटर
लिफ्ट-ऑफ भार	320 टन	414 टन	640 टन
प्रणोदन	ठोस एवं तरल	ठोस, तरल एवं क्रायोजेनिक	ठोस, तरल एवं क्रायोजेनिक
पेलोड द्रव्यमान	1860 किग्रा.	2200 किग्रा.	4000 किग्रा.
कक्षा	475 किमी. की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा (1300 किग्रा. वजनी उपग्रह को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित करने में सक्षम)	भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा	भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा

❑ भारत : क्रायोजेनिक तकनीक में आत्मनिर्भर

क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनों के विकास में सफलता प्राप्त करने वाला अमेरिका पहला देश था। अमेरिका ने वर्ष 1963 में सर्वप्रथम ऊपरी चरण में RL-10 क्रायोजेनिक इंजनों से लैस एटलस रॉकेट की सफल उड़ान आयोजित की थी। इसके बाद जापान ने वर्ष 1977 में LE-5 क्रायोजेनिक इंजन, फ्रांस ने वर्ष 1979 में HM-7 इंजन तथा चीन ने वर्ष 1984 में YF-73 इंजन से लैस रॉकेट का प्रक्षेपण किया। हालांकि रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) क्रायोजेनिक तकनीक के विकास में थोड़ा पीछे रह गया और उसने वर्ष 1987 में इस क्षेत्र में महारत हासिल की।

भारत ने काफी पहले ही क्रायोजेनिक तकनीक की महत्ता को पहचान लिया था। पीएसएलवी परियोजना को मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद ही दिसंबर, 1982 में इसरो ने एक 'क्रायोजेनिक अध्ययन दल' (Cryogenic Study Team) का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे क्रायोजेनिक इंजन के विकास की सिफारिश की जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए 10 टन तक का ठेल उत्पन्न कर सके। हालांकि यह परियोजना तब उड़ान नहीं भर सकी। कई दौर की मंत्रणा के बाद इसरो को यह अहसास हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने के लिए उन्हें बहुत-सी तकनीकी चुनौतियों को पार करना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा समय और धन खर्च होगा। अतः क्रायोजेनिक तकनीक को खुद विकसित करने के स्थान पर रूस से क्रायोजेनिक इंजनों का आयात करके जीएसएलवी कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। अंततः जनवरी, 1991 में इसरो एवं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 'ग्लावकॉसमॉस' (Glavkosmos) के मध्य रूस द्वारा भारत को दो क्रायोजेनिक इंजन और इसके निर्माण की तकनीक मुहैया कराने हेतु 120 मिलियन डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता साकार हो पाता, उससे पहले ही अमेरिका ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अमेरिका ने इस समझौते को 'एमटीसीआर' (MTCR : Missile Technology Control Regime) के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका को आशंका थी कि भारत, रूस से मिलने वाली क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित करने में कर सकता है। अमेरिकी दबाव में रूस ने वर्ष 1993 में भारत के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रूस बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मूल समझौते में उल्लिखित 2 की बजाए 7 क्रायोजेनिक इंजन भारत को सौंपने हेतु राजी हो गया। रूस से क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण की तकनीक हासिल न होने के बाद इसरो ने इस क्षेत्र में स्वावलंबी बनने की ठानी और अप्रैल, 1994 में 'क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना' (CUSP : Cryogenic Upper Stage Project) को लांच किया गया। इसके बाद तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित 'द्रव नोदन प्रणाली केंद्र' (वर्तमान में इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स) में फास्ट-ट्रैक मोड में क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया। वर्षों के अथक प्रयास के बाद भारत ने पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-7.5 के विकास में सफलता प्राप्त की। यह इंजन 720 सेकंड तक जलकर 7.5 टन ठेल प्रदान करने में सक्षम है। इस इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम अप्रैल, 2010 में जीएसएलवी की छठीं उड़ान (मिशन : जीएसएलवी-डी3/जीसैट-4) में किया गया। हालांकि क्रायोजेनिक चरण में तकनीकी त्रुटियों की वजह से यह मिशन असफल रहा, लेकिन इसरो ने इससे विचलित न होते हुए अपने प्रयास जारी रखे।

अंततः इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और जनवरी, 2014 में सबसे ऊपरी (तीसरे) चरण में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस जीएसएलवी डी-5 ने 1982 किग्रा. वजनी संचार उपग्रह जीसैट-14 को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस जीएसएलवी की पहली सफल उड़ान थी। इसके बाद तो इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस जीएसएलवी मार्क-II द्वारा वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में लगातार तीन सफल उड़ानों के माध्यम से क्रमशः जीसैट-6 (2117 किग्रा.), इनसैट-3डीआर (2211 किग्रा.) और दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट-9 (2230 किग्रा.) को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस प्रकार अब भारत क्रायोजेनिक तकनीक में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया है।

जीसैट-19 : प्रमुख विशेषताएं

कक्षा	भूस्थिर/48° पूर्व देशांतर
भार	1394 किग्रा. (शुष्क भार) 3136 किग्रा. (उत्थापन के समय भार)
भौतिक आयाम	2.0 मी. × 1.77 मी. × 3.1 मी. घनाभ (Cuboid)
विद्युत उत्पादन	4500 वॉट उत्पन्न करने वाले सोलर ऐरे, एक 100 Ah की लीथियम आयन बैटरी
प्रणोदन प्रणाली	440 न्यूटन की द्रव अपभू मोटर, आठ 10 न्यूटन और आठ 22 न्यूटन के रासायनिक थ्रस्टर्स
पेलोड	Ka/Ku-बैंड के उच्च प्रवाह क्षमता के संचार प्रेषानुकर (Transponders), भूस्थिर विकिरण स्पेक्ट्रोमापी (GRASP)
मिशन कालावधि	10 वर्ष

❑ जीएसएलवी मार्क-III का विकास

भारत ने अपने पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-7.5 को जीएसएलवी मार्क-II में संलग्न करके 2-2.5 टन वजनी संचार उपग्रहों को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में स्थापित करने की क्षमता तो विकसित कर ली, लेकिन इससे अधिक वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उसे अभी भी विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की शरण में जाना पड़ता है। दरअसल, दूरसंचार के 'दिन दूने रात चौगुने' विकास ने दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में 3500 किग्रा. से अधिक वजन वाले उपग्रहों की मांग अचानक बढ़ा दी है। अगर वर्ष 2005-2015 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपित किए गए संचार उपग्रहों का अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि इस दौरान प्रक्षेपित मात्र 12 प्रतिशत उपग्रह ही 2500 किग्रा. से कम वजन के थे, जबकि 30 प्रतिशत उपग्रह 2500-4200 किग्रा. वजन श्रेणी में, 27 प्रतिशत उपग्रह 4200-5400 किग्रा. श्रेणी में तथा 31 प्रतिशत उपग्रह अत्यधिक वजनी 5400 किग्रा. से अधिक वजन श्रेणी में शामिल थे।

यह प्रवृत्ति इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों में भी देखने को मिलती है। वर्ष 2010 से अब तक प्रक्षेपित 13 जीसैट उपग्रहों में से 6 उपग्रह 3000 किग्रा. से अधिक वजन के थे। इसके अतिरिक्त अगले डेढ़ वर्षों के अंदर भारत द्वारा दो और संचार उपग्रहों यथा जीसैट-11 एवं जीसैट-20 को भी अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इनमें से जीसैट-11 तो लगभग 5700 किग्रा. वजनी है और अभी भारत स्वयं इतना विशाल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम नहीं है, अतः इसे प्रक्षेपित करने के लिए यूरोपीय एरियन-5 रॉकेट का सहारा लिया जाएगा।

भारत ने 2.5 टन से अधिक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 36000 किमी. की ऊंचाई पर स्थित भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वर्ष 2002 में अत्यधिक ठेल प्रदान करने वाले क्रायोजेनिक इंजन (High Thrust Cryogenic Engine) CE-20 का विकास आरंभ किया था। उल्लेखनीय है कि भारत के पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-7.5 की डिजाइन पर रूस से आयातित क्रायोजेनिक इंजनों का गहरा प्रभाव था, जबकि CE-20 पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। CE-7.5 में एससीसी (SCC : Staged Combustion Cycle) का प्रयोग किया गया था जबकि CE-20 गैस जेनरेटर चक्र पर आधारित है। CE-20 लगभग 20 टन तक का ठेल प्रदान करने में सक्षम है जो इसके पूर्ववर्ती CE-7.5 की तुलना में कहीं अधिक है। इसी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III के सबसे ऊपरी तीसरे चरण में संलग्न करके भारत को 4 टन वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है।

फैट ब्वॉय (Fat Boy)

भारत के अत्याधुनिक एवं सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III का नामकरण काफी दिलचस्प तरीके से किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका वजन पांच पूरी तरह से भरे बोइंग जम्बो विमान या 200 वयस्क हाथियों के बराबर है, इसलिए इसे उन्होंने फैट ब्वॉय (मोटा लड़का) उपनाम दिया है। उल्लेखनीय है कि, इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने PSLV को 'वर्क हॉर्स' (मेहनती घोड़ा), तो जीएसएलवी मार्क-II को उसकी अस्थिरता की वजह से 'नॉटी ब्वॉय' (शैतान लड़का) की संज्ञा दी थी।

उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी मार्क-III एक तीन खंडों वाला रॉकेट है। इसके प्रथम चरण में दो ठोस रॉकेट बूस्टर (S200) संलग्न हैं जो लिफ्ट-ऑफ के लिए आवश्यक ठेल प्रदान करते हैं। प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक एचटीपीबी (HTPB : Hydroxyl-Terminated Polybutadiene) भरा जाता है। दो विकास इंजनों द्वारा संचालित दूसरे चरण (L110) में द्रव प्रणोदक [(UDMH : Unsymmetrical Di-Methyl Hydrazine) एवं N_2O_4 (Nitrogen Tetra Oxide)] इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है। तीसरा चरण ही रॉकेट को सर्वाधिक ठेल प्रदान करता है।

❑ पहली विकासात्मक उड़ान

तेरह मंजिला इमारत जितना ऊंचा और लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से बना देश का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III 5 जून, 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक

प्रक्षेपित कर दिया गया। लगभग साढ़े पच्चीस घंटे की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद 640 टन वजनी जीएसएलवी मार्क-III ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा के द्वितीय लांच पैड से अपराह्न 5:28 बजे उड़ान भरी और लिफ्ट-ऑफ के 16 मिनट बाद संचार उपग्रह जीसैट-19 को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में स्थापित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह जीएसएलवी मार्क-III की पहली विकासात्मक उड़ान (GSLV-MK III-D1) थी। जीएसएलवी मार्क-III भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में 4 टन तक तथा 600 किमी. की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 8-10 टन तक पेलोड या उपग्रह को ले जाने की क्षमता रखता है। हालांकि सद्यः उड़ान में यह जिस जीसैट-19 को अपने साथ ले गया है, उसका वजन मात्र 3136 किग्रा. है, फिर भी जीसैट-19 भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है। जीएसएलवी मार्क-III से इस उपग्रह के अलग होने के पश्चात कर्नाटक के हासन स्थित इसरो की मास्टर कंट्रोल फसिलिटी ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तत्पश्चात, चार चरणों में उपग्रह की 'द्रव अपभू मोटर' (LAM : Liquid Apogee Motor) को दाग कर इसके कक्षोन्नयन की प्रक्रियाएं संपन्न की गईं और जीसैट-19 भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) से अंतिम वृत्ताकार भूस्थिर कक्षा (GSO) में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसी उम्मीद व्यक्त की गई है कि एक और सफल विकासात्मक उड़ान के बाद जीएसएलवी मार्क-III का परिचालन पूर्णतः प्रारंभ हो जाएगा। जीएसएलवी मार्क-III के कामकाज शुरू करने के बाद भारत अपने ही रॉकेट से 4 टन तक वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम हो जाएगा, जिससे न केवल विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों को इस काम के लिए दिए जाने वाले पैसे को बचाया जा सकेगा, बल्कि यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के नए दरवाजे भी खोल देगा। जीएसएलवी मार्क-III को पीएसएलवी जैसी स्वीकार्यता मिलने पर निश्चय ही उपग्रह प्रक्षेपण के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

जीएसएलवी मार्क-III के तौर पर भारत न केवल अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के प्रक्षेपण में कामयाब रहा है, बल्कि इसके साथ गया उपग्रह जीसैट-19 संचार के लिहाज से एक गेमचेंजर (Game Changer) माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में देश में दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इसमें Ka एवं Ku बैंड के संचार ट्रांसपोंडर लगे हैं। इसके अलावा इसमें 'भूस्थैतिक विकिरण स्पेक्ट्रोमीटर' भी लगा है जो आवेशित कणों की प्रकृति का अध्ययन एवं निगरानी के साथ-साथ उपग्रहों एवं उनमें लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पड़ने वाले अंतरिक्षीय विकिरण के प्रभावों का अध्ययन भी करेगा।

जीएसएलवी मार्क-III की शानदार कामयाबी के बाद इसरो खामोश नहीं बैठ गया है, बल्कि आसमां के ऊपर और भी जहां तलाश रहा है। अब इसरो ने अंतरिक्ष में यात्री भेजने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ योजना के अनुरूप ठीक से चला तो एक दशक या लगभग आधा दर्जन सफल लांचिंग के बाद जीएसएलवी मार्क-III के जरिए पृथ्वी से मनुष्यों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा तक 8-10 टन वजन ले जाने में सक्षम है जो भारत के चालक दल को ले जाने के लिहाज से पर्याप्त है। यदि भारत अपने इस अभियान में सफल हो जाता है, तो वह अमेरिका, रूस एवं चीन जैसे चुनिंदा देशों के उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिनका एक मानवीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।

सारांश

- देश का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III 5 जून, 2017 को प्रक्षेपित।
- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी मार्क-III की यह पहली उड़ान।
- भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में 4 टन तक तथा 600 किमी. की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 8-10 टन तक पेलोड या उपग्रह को ले जाने की क्षमता।
- भारतीय धरती से अब तक का सबसे वजनी (3136 किग्रा.) उपग्रह जीसैट-19, GTO (36,000 किमी. ऊंचाई) में स्थापित।
- जीएसएलवी मार्क-III के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन लगा है।
- क्रायोजेनिक तकनीक शून्य से 238 डिग्री फारेनहाइट कम ताप (-238^{o}F या -150^{o}C) पर कार्य करती है।
- क्रायोजेनिक इंजन में प्रायः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन व ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं।

■■■

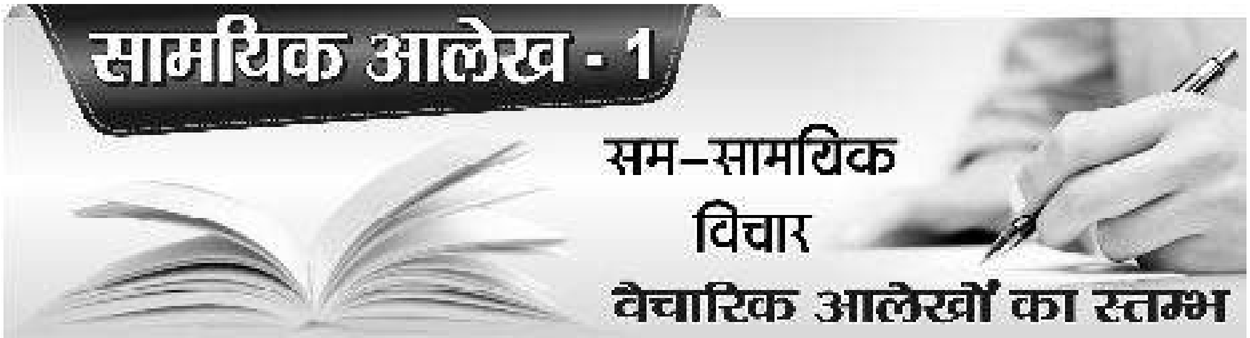

प्रधानमंत्री की चार यूरोपीय देशों की यात्रा

– अम्बरीश कुमार तिवारी

इतिहास साक्षी है कि जो चलते रहे, यात्री बने, उन्होंने इतिहास बनाया, जबकि जो ठहर गए, वे समाप्त हो गए। वैसे तो यात्राओं के विविध प्रयोजन होते हैं, लेकिन जब किसी देश का नेतृत्वकर्ता, अन्य देशों की यात्राओं पर जाता है तो उसका प्रयोजन एक ही होता है, राष्ट्रहित। विभिन्न देशों के मध्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने में सबसे सशक्त साधन विदेशी यात्राएं हैं। वैश्विक गांव (Global Village) की संकल्पना के मूल में भी ये यात्राएं ही हैं। वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही विदेशी यात्राओं को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी विदेश नीति के तहत विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों को भी अपने विदेशी यात्राओं में पर्याप्त तरजीह दी है।

अपनी इसी नीति के तहत यूरोपीय देशों से आर्थिक, सामरिक, राजनयिक एवं सांस्कृतिक सहयोग प्राप्त कर भारत के चहुंमुखी विकास हेतु संसाधन जुटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 29 मई से 2 जून, 2017 के मध्य यूरोप के चार देशों जर्मनी, स्पेन, रूस तथा फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा संपन्न की। प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर भी गए थे।

❑ प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप की चार देशीय यात्रा के क्रम में 29-30 मई, 2017 के मध्य सर्वप्रथम जर्मनी की यात्रा संपन्न की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बर्लिन से 80 किलोमीटर दूर 18वीं सदी के मेसेबर्ग महल में प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

● आर्थिक संबंध

जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे का प्रमुख उद्देश्य वहां के सरकारी निवेश, निजी उद्यमियों व कारोबारियों को भारत में निवेश हेतु आकर्षित करना था। जर्मनी जहां यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार है, तो वहीं भारत, जर्मनी के व्यावसायिक साझेदारों की सूची में अभी बहुत पीछे (24वां स्थान) है।

भारत में लगभग 1700 से अधिक जर्मन कंपनियां कारोबार कर रही हैं तथा भारत व जर्मनी के मध्य लगभग 1600 से अधिक इंडो-जर्मन सहयोग तथा 600 संयुक्त उद्यम हैं। भारत के लिए जर्मनी सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। जर्मनी ने वर्ष 2000 से मार्च, 2017 के मध्य भारत में 9.69 बिलियन डॉलर का निवेश किया और वर्ष 2016 में दोनों देशों के मध्य 17.42 बिलियन यूरो का कारोबार हुआ। लेकिन यह निवेश और कारोबार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार के हिसाब से बहुत कम है और इसका कारण यह है कि भारत निवेश की दृष्टि से अब तक जर्मन कारोबारियों के पसंदीदा देशों की सूची में अपनी जगह नहीं बना पाया है। यद्यपि दोनों देशों ने सितंबर, 2015 में निवेश सुविधा कार्यक्रम भी लागू किया है, इसे एमआईआईएम (मेक इन इंडिया मिटिलस्टैंड) कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए जर्मन कंपनियों की सहायता करना है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों के विशाल भारतीय बाजार से होने वाले आर्थिक लाभ भारत की तरफ जर्मनी के बढ़ते हुए हाथों के पीछे मुख्य प्रेरक हैं। यही वजह है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2007 से ही जर्मन प्रयासों के माध्यम से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ताओं के लिए प्रयासरत है। चूंकि जर्मनी एक निर्यात प्रधान देश है, इसलिए मुक्त व्यापार समझौता होने की स्थिति में सर्वाधिक लाभ भी उसी को होगा।

दूसरी ओर यूरोपीय देशों द्वारा भारत की इस मांग को अभी तक अनसुना किया गया है कि यूरोपीय देश भी भारत के श्रमिकों, कुशल कर्मिकों एवं कंप्यूटर विशेषज्ञों के लिए अपने श्रम बाजार खोलें। जर्मनी के आर्थिक शोध संस्थान (IFO) ने हिसाब लगाया है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की स्थिति में जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्रति वर्ष 4 अरब 60 करोड़ यूरो के बराबर वृद्धि होगी। यह वृद्धि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के चले जाने से होने वाली कमी की भरपाई कर देगी।

● भारत-जर्मनी सहयोग के क्षेत्र

प्रधानमंत्री मोदी व चांसलर मर्केल की उपस्थिति में दोनों देशों के मध्य साइबर सुरक्षा, राजनीतिक संबंधों के विकास, सतत शहरी विकास, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, रेल सुरक्षा, व्यावसायिक

शिक्षा, क्लस्टर प्रबंधन व भारत-जर्मन केंद्र पर सहयोग से संबंधित संयुक्त आशय घोषणा-पत्र के साथ-साथ 12 समझौतों/समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

शिक्षा क्षेत्र में सहयोग

अकादमिक आदान-प्रदान एवं शोध कार्यों में सहयोग को सरल बनाने हेतु दोनों देशों के 10 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य साझेदारी विकसित की जाएगी। संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि जर्मन स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। हिंदी के अतिरिक्त दूसरी आधुनिक भारतीय भाषाएं भी जर्मनी में पढ़ाई जाएंगी। भारत में पहले से ही कई केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही है। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की डिग्रियों को भी मान्यता देने पर विचार करने हेतु सहमति बनी है। शहरी विकास हेतु जर्मनी वर्ष 2022 तक भारत में 1 अरब यूरो तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है। सतत शहरी विकास हेतु संयुक्त कार्यदल ने कोच्चि, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर को द्विपक्षीय सहयोग हेतु चिह्नित किया है।

रणनीतिक सहयोग

वर्ष 2015 में द्विवार्षिक अंतर्सरकारी शिखर बैठक की शुरुआत के साथ भारत व जर्मनी ने आपसी रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का इरादा जताया था। मौजूदा वैश्विक हालात में इसके लिए कहीं ज्यादा अनुकूल अवसर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से निराश मर्केल का यह कथन महत्वपूर्ण है कि जर्मनी ब्रेक्जिट और ट्रंप के जमाने में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे परंपरागत सहयोगियों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए आश्चर्य नहीं कि भारत अब जर्मनी को न केवल बाजार के दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक एवं भू-राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम लगने लगा है एवं भारत के प्रति उसकी दिलचस्पी जगी है। शायद इसलिए भी कि इस समय दुनिया की बड़ी ताकतों के रिश्तों में अस्थिरता दिख रही है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है तथा डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जी-7 की बैठक में पेरिस जलवायु संधि का विरोध करने के साथ ही जर्मनी की व्यापार नीति की खुलेआम आलोचना की थी।

चीन के साथ जर्मनी की विपुल व्यापारिक संभावनाएं दिखती हैं किंतु चीन की राजनीतिक व्यवस्था यूरोपीय मिजाज़ से मेल नहीं खाती। चीन की महत्वाकांक्षी योजना 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) के प्रति भी कई यूरोपीय देशों के मन में संशय व्याप्त है। ऐसे में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत के प्रति रुझान बढ़ना स्वाभाविक है।

सामरिक क्षेत्र में सहयोग

इस बार के भारत-जर्मन संवाद की एक नई विशेषता यह रही कि अमेरिका की तरह जर्मनी भी भारत को एशिया में, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक ऐसी स्थिरताकारी शक्ति के रूप में देखता है जिससे चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिल सकती है। जर्मनी भारत के साथ उच्च कोटि के हथियार बनाने में तकनीकी सहयोग और कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तैयार है। इससे रक्षा सामग्री के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता घटाने में भारत के प्रयासों को बल मिलेगा। भारत में रक्षा सामग्री के निर्माण एवं मेक इन इंडिया अभियान की सफलता हेतु आवश्यक उच्च तकनीक के लिए उच्च तकनीक साझेदारी ग्रुप (HTPG) का गठन भी किया गया है।

❑ स्पेन यात्रा

अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो राजॉए के निमंत्रण पर 30-31 मई, 2017 के मध्य स्पेन की यात्रा की। यह लगभग 30 वर्षों के अंतराल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्पेन यात्रा थी। इसके पूर्व वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्पेन की यात्रा संपन्न की थी।

आर्थिक संबंध

स्पेन के साथ भारत की संबद्धता में आर्थिक सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में स्पेन की लगभग 200 कंपनियां कारोबार कर रही हैं। अनेक भारतीय कंपनियां भी स्पेन में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यूरोपीय संघ में स्पेन भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016 में लगभग 5.22 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2000 से 2016 तक 2.32 बिलियन डॉलर का निवेश स्पेन की तरफ से भारत में हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति राजॉए के साथ 31 मई, 2017 को मैड्रिड में भारत-स्पेन सीईओ फोरम की प्रथम बैठक में भाग लिया। द्वितीय स्पेन-भारत सीईओ फोरम का आयोजन नवंबर, 2017 में मैड्रिड में किया जाएगा। यह फोरम स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह फोरम निवेश, व्यापारिक संबंधों आदि को बढ़ावा देने हेतु एक मंच है।

सांस्कृतिक सहयोग

दोनों देश सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने हेतु प्रयासरत हैं। इस हेतु दोनों देशों की सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। स्पेन के वैलडॉलिड (Valladolid) तथा भारत के अहमदाबाद शहरों के मध्य जल्द ही ट्विनिंग समझौता (Twining Agreement) होने की संभावना है। संबंधों में विस्तार के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बार्सिलोना में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। स्पेन के राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 में भारत में स्पेन का वर्ष आयोजित करने के इरादे की घोषणा की। भारतीय मूल के समुदाय के अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने कैनरी द्वीपसमूह में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा की स्थापना करने की घोषणा की।

प्रमुख समझौते

इस यात्रा के दौरान भारत व स्पेन के मध्य नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा, सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण, विदेश सेवा संस्थान व स्पेन की डिप्लोमैटिक अकादमी के मध्य सहयोग एवं राजनयिक पासपोर्ट धारकों हेतु वीजा छूट आदि से संबंधित कुल 7 समझौते/समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। पर्यटन क्षेत्र में सहयोग हेतु एक उच्चस्तरीय पैनल गठित किया जाएगा जो वर्ष

2018 तक अपनी रिपोर्ट देगा। सीमा शुल्क सहयोग पर दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते हेतु वार्ता के वर्ष 2017 के अंत तक समाप्त होने की संभावना है।

❑ प्रधानमंत्री की रूस यात्रा

चार देशीय यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 1-2 जून, 2017 के मध्य रूस की यात्रा की। यात्रा की शुरुआत में मोदी लेनिनग्राद युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पिस्कारयोवस्कोए स्मारक गए। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हर्मिटेज म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट का भी दौरा किया।

● रणनीतिक साझेदारी

भारत व रूस के मध्य रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी जिसे वर्ष 2010 में विशेष व विशेषाधिकृत रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। तभी से रूस के साथ भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एवं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में अठारहवें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह पहला अवसर था जब रूस में भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मास्को में न होकर कहीं और हुआ। 2 जून, 2017 को मोदी और पुतिन 'सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच' (SPIEF) में शामिल हुए जहां भारत मेहमान देश था। यह पहली बार था जब भारत ने इस आर्थिक मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ऐसे समय पर हुई जब पाकिस्तान और चीन के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं जिसके चलते भारत के पारंपरिक दोस्त रूस के साथ आर्थिक रिश्ते जटिल हुए हैं। ऐसे में भारत-रूस के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर मोदी की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी। पाकिस्तान व रूस के मध्य बढ़ रही दोस्ती को लेकर उत्पन्न भारतीय चिंताओं पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा ''रूस के लिए भारत से संबंध अधिक महत्वपूर्ण हैं।'' दोनों नेताओं के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग में अकेले में खुलकर वार्ता हुई जिससे आपसी संबंधों में आए तनाव और भ्रांतियां समाप्त हो गईं। 1 जून, 2017 को दोनों देशों के मध्य 21वीं सदी में आपसी सहयोग हेतु सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र जारी किया गया।

● प्रमुख समझौते

भारत-रूस शिखर बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति में दोनों देशों के मध्य वैश्विक संपदा अधिकार समझौता, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में पांचवीं एवं छठीं इकाई के निर्माण की बृहद योजना पर समझौता, वर्ष 2017-19 के लिए दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान का द्विपक्षीय समझौता, नागपुर-सिकंदराबाद के मध्य एक उच्च गति की संपर्क लाइन की व्यवहारिकता पर अध्ययन और संयुक्त स्टॉक कंपनी एएलआरओएसए (ALROSA) और भारत की रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 5 और 6 के निर्माण के लिए हुआ समझौता काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रूस को वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला दोस्त बताते हुए इस समझौते पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और बढ़ेगा।

संयंत्र की सभी इकाइयों का निर्माण 'भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड' (एनपीसीआईएल) और रूसी परमाणु संयंत्रों की नियामक संस्था रोसाटॉम की सहायक कंपनी एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह करार हो जाने पर 1-1 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली दोनों इकाइयां देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगी। वर्तमान में भारत के सभी 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावॉट है।

रूस एवं भारत के मध्य बहुआयामी आपसी संबंध अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से इन संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। भारत व रूस का मजबूती से साथ रहना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोग जारी रखने का भी वचन दिया है। निश्चित रूप से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को न केवल नई ऊंचाई दी है बल्कि इससे विश्व को एक संदेश भी मिला है।

❑ प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा

प्रधानमंत्री ने अपनी चार देशीय यात्रा का समापन 2-3 जून, 2017 के मध्य फ्रांस की यात्रा से किया। फ्रांस की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत-फ्रांस रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ-साथ आपसी हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।

फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास तथा रेलवे जैसे क्षेत्रों में भारत का एक अहम साझेदार है। यह भारत का नौवां सबसे बड़ा निवेश साझेदार है।

प्रधानमंत्री ने फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की चुनावी जीत पर उन्हें बधाई दी। उल्लेखनीय है कि 39 वर्षीय मैक्रों फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। भारत व फ्रांस आतंकवाद और चरमपंथ की चुनौतियों से निपटने हेतु आपसी सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत व फ्रांस के संबंधों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-''चाहे यह व्यापार हो या प्रौद्योगिकी नवोन्मेष या फिर निवेश, ऊर्जा, शिक्षा और उद्यम, हम हर क्षेत्र में भारत-फ्रांस संबंधों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।'' प्रधानमंत्री ने पेरिस में 'आर्क दे ट्रायोम्फ' (Arc de Triomphe) का भी दौरा किया तथा विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मैक्रों ने विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की आजादी के लिए बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में प्रेसीडेंशियल एलसी पैलेस (Elysee Palace) में बैठक व भोज का आयोजन किया।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय तथा परस्पर हितों के मुद्दों पर चर्चा के साथ ही रणनीतिक संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के अलग होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता दुनिया की साझा विरासत है और भारत जलवायु संरक्षण के लिए अपेक्षाओं से भी आगे बढ़कर काम करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पेरिस जलवायु करार धरती और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के हमारे कर्तव्य को झलकाता है। हमारे लिए यह आस्था का मामला है। मोदी व मैक्रों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पेरिस जलवायु समझौता दुनिया की साझा विरासत है। यह भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभान्वित करेगा।

❑ विश्लेषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा जहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच नए रिश्तों की तलाश थी, वहीं यूरोप को भी भारत से एक व्यापारिक और रणनीतिक सहयोगी के रूप में गहरे संबंधों की उम्मीद है। मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हुई जब यूरोपीय संघ वर्षों से सहयोगी रहे देशों से निराश है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इटली में हुई जी-7 देशों की शिखर बैठक के बाद कहा कि अब यूरोप को अमेरिका और ब्रिटेन पर भरोसा छोड़कर अपने पर विश्वास करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आवश्यक आर्थिक योगदान लिए बिना न तो नाटो संधि के तहत यूरोप को सुरक्षा देने को तैयार हैं और न ही अपने देश में उन्हें व्यावसायिक अवसर देने के इच्छुक हैं। अमेरिका के संरक्षणवादी असहयोगपूर्ण रवैये, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का 'एकला चलो' का मार्ग और चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' नीति से नब्बे के दशक में उभरी विश्व व्यापार व्यवस्था खतरे में है। ऐसे में जर्मन चांसलर मर्केल और फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चाहेंगे कि वैश्विक व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की मनमर्जी के लिहाज से चलने की बजाय नियमों के मुताबिक चले। इस काम में भारत उन्हें महत्वपूर्ण सहयोगी मालूम पड़ता है। अभी भी भारत का सबसे ज्यादा व्यापार यूरोपीय संघ से ही होता है और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक परिमाण के लिहाज से भारत का नौवां स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का मकसद यूरोपीय निवेशकों को भारत में सुरक्षा का भरोसा देकर भारत की ओर आकर्षित करना था। मोदी ने रूस के साथ संबंधों में बढ़ती दरार को भी पाटने की कोशिश की तथा उसे यह समझाया कि चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती भारत की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से यह यात्रा आर्थिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के साथ-साथ उन उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भी सहायक हो सकती है, जो बढ़ते आतंकवाद और राष्ट्रवादी कट्टरता के कारण अपनी जन्मस्थली यूरोप में ही सबसे ज्यादा खतरे में हैं।

सारांश

- ◆ प्रधानमंत्री की चार देशों (जर्मनी, स्पेन,रूस तथा फ्रांस) की यात्रा 29 मई से 2 जून, 2017 के मध्य संपन्न।
- ◆ यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जर्मनी की चांसलर, एंजेला मर्केल।
- ◆ वर्ष 2016 में भारत व जर्मनी के मध्य 17.42 बिलियन यूरो का कारोबार।
- ◆ जर्मन स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत की घोषणा।
- ◆ शहरी विकास हेतु जर्मनी, वर्ष 2022 तक भारत में 1 अरब यूरो तक की वित्तीय सहायता का इच्छुक।
- ◆ स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो राजॉए के निमंत्रण पर 30 वर्षों के अंतराल में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्पेन यात्रा।
- ◆ कैनरी द्वीपसमूह, स्पेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा।
- ◆ रूस यात्रा (1-2 जून) के दौरान सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में अठारहवां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन।
- ◆ 'सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच' (SPIEF) में भारत मेहमान देश।
- ◆ तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 5 व 6 के निर्माण के लिए समझौता।
- ◆ दोनों इकाइयां 1-1 हजार मेगावॉट क्षमता वाली।
- ◆ 2-3 जून के मध्य फ्रांस की यात्रा।
- ◆ इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति।

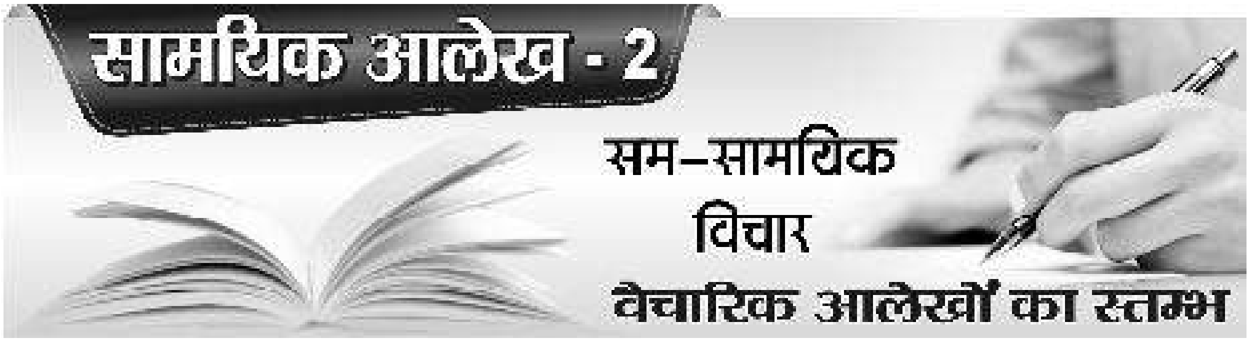

कुलभूषण जाधव मामला : भारत बनाम पाकिस्तान

— काली शंकर 'शारदेय'

भारतीय दर्शन में कार्य-कारण संबंधों की चर्चा की गई है, जिसके अनुसार, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है अर्थात् कारण की प्रतिक्रिया स्वरूप ही कार्य संपन्न होता है और फिर कार्य या क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है फिर इसकी श्रृंखला निर्मित होती जाती है।

भौतिक शास्त्री न्यूटन ने जब भौतिकी के इस सिद्धांत की खोज की होगी कि 'प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है', तब उनके जेहन में शायद ही यह बात आई हो कि यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में, बल्कि मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उतना ही सत्य और प्रामाणिक होगा।

वास्तव में मानव लगभग प्रत्येक क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसे आसानी से देखा-समझा जा सकता है। यह दीगर बात है कि प्रतिक्रिया कभी भावों में, कभी शारीरिक या मानसिक, तो कभी मौखिक या लिखित रूप में प्रदर्शित होती है। कभी-कभी किसी मनुष्य में यह निष्क्रिय समझी जाती है, मगर वास्तव में यह किसी और रूप में प्रकट हो रही होती है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी क्रिया पर प्रतिक्रिया को आसानी से देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में आज देशों के संबंध इतने जटिल हो गए हैं कि एक देश द्वारा उठाया गया कोई कदम किसी न किसी रूप में अन्य देशों को भी प्रभावित करता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य देशों द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का अंतहीन दौर।

अतीत की वैश्विक घटनाओं पर गौर किया जाए, तो वे भी किसी न किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में घटित हुई जान पड़ती हैं। उदाहरणार्थ-प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, जापान पर परमाणु बम से हमला, शीत युद्ध, सोवियत संघ का विघटन आदि। भारत के संबंध में बात की जाए, तो चीन द्वारा बार-बार भारतीय सीमा के उल्लंघन करने की क्रिया की प्रतिक्रिया भारत द्वारा दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, जापान तथा अमेरिका जैसे देशों से संबंधों की प्रगाढ़ता में दिखती है। फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चीन, पाकिस्तान को राजनयिक, आर्थिक तथा सैन्य समर्थन देता हुआ दिखता है। उड़ी (जम्मू एवं कश्मीर) हमले की प्रतिक्रिया में भारत द्वारा किया गया 'सर्जिकल स्ट्राइक' भी इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है।

इसी संदर्भ में भारत-पाकिस्तान के संबंध में कुलभूषण सुधीर जाधव मामले को भी देखा जा सकता है। कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर तथा उनको भारतीय जासूस बताकर पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा लगातार इस बात का प्रमाण दिया जाता रहा है कि भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे न केवल पाकिस्तान का हाथ है, बल्कि वह आतंकवाद को पोषित भी करता रहा है। इसीलिए वैश्विक मंच पर भारत द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कवायद के कारण बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव की प्रतिक्रिया स्वरूप ही पाकिस्तान द्वारा यह कदम उठाया गया मालूम पड़ता है।

किसी भी देश की विदेश नीति का लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय राजनय का समस्त क्रिया-कलाप राष्ट्रहित की रक्षा के लिए ही होता है। इसी कवायद में भारत और पाकिस्तान लगभग 18 वर्षों बाद एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आमने-सामने हैं।

❑ कौन हैं कुलभूषण जाधव?

कुलभूषण सुधीर जाधव भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। इनका जन्म वर्ष 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधीर जाधव है। इन्होंने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश लिया तथा वर्ष 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। सेवानिवृत्ति के बाद जाधव ने ईरान में अपना व्यापार शुरू किया। वे ईरान में कार्गो व्यवसाय के मालिक हैं। पाकिस्तान द्वारा ईरान से इनका अपहरण करवाया गया तथा बाद में ऐसी जानकारी दी गई कि उनको 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। ये अभी भी पाकिस्तान की कैद में ही हैं।

क्या है मामला?

पाकिस्तान द्वारा अपहृत भारतीय नागरिक तथा पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में 10 अप्रैल, 2017 को फांसी की सजा सुनाई। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे थे तथा ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) के कर्मचारी हैं।

वहीं भारत ने जाधव की भारतीय नागरिकता और पूर्व नौसेना अधिकारी होने की ही पुष्टि की है। इनका ईरान में निजी व्यापार था। तालिबान द्वारा इनका ईरान से ही अपहरण कर पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा आई.एस.आई. द्वारा इनके नकली दस्तावेज बनाए गए हैं।

पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी से हुसैन मुबारक पटेल नामक कोड नेम प्राप्त हुआ था। अप्रैल, 2016 में पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न देशों के राजनयिकों को आतंकवादी गतिविधियों में जाधव की भागीदारी की जानकारी दी थी। सितंबर, 2016 में पाकिस्तान ने भारत प्रायोजित आतंकवाद का एक दस्तावेज तैयार करके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को प्रस्तुत किया था, जिसमें जाधव का विवरण भी शामिल था।

पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जाधव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। हालांकि भारत ने वीडियो के कबूलनामे को अस्वीकार कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने दावा किया कि यह पाकिस्तान द्वारा बनाया गया पूरी तरह जाली वीडियो है। पाकिस्तान द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। वहीं भारतीय एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया वीडियो अत्यधिक मात्रा में संपादित (Edit) किया गया है और ऑडियो को कई स्थानों पर काट कर दिखाया गया है।

जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत द्वारा लगभग 16 बार जाधव से राजनयिक संपर्क करने तथा पूरी न्यायिक कार्यवाही के विवरण की मांग की गई। लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत की मांग को ठुकरा दिया गया। परिणामस्वरूप भारत द्वारा वियना कन्वेंशन तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दाखिल की गई।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत-पाकिस्तान

8 मई, 2017 को भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के संबंध में एक याचिका दाखिल की गई। तदनुसार, भारत की निम्नलिखित मुद्दों पर राहत की अपेक्षा है–

(i) आरोपी (कुलभूषण सुधीर जाधव) को दिए गए मृत्युदंड के तत्काल निलंबन के जरिए राहत।

(ii) सैन्य अदालत के निर्णय को, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 तथा 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (1966 International Covenant on Civil & Political Rights) के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करते हुए राहत।

(iii) सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को क्रियान्वित करने से पाकिस्तान को रोकना तथा पाकिस्तान में कानून के तहत सैन्य अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाने हेतु निर्देश देना।

(iv) यदि पाकिस्तान सैन्य अदालत के निर्णय को रद्द करने में असमर्थ है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस निर्णय को अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि अधिकारों तथा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के कारण अवैध घोषित करते हुए पाकिस्तान को यह निर्देश दे कि वह आरोपी भारतीय नागरिक को तत्काल रिहा करे।

हालांकि इस मामले में पाकिस्तान का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है।

जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सदस्यता लेने से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान या दूसरे राष्ट्रमंडल देशों के साथ द्विपक्षीय मामलों में वह शामिल नहीं होगा। अब तक का भारत का पक्ष यही रहा था कि वह द्विपक्षीय मामलों पर अंतरराष्ट्रीय अदालत को मान्यता नहीं देता। कारगिल युद्ध (1999) के बाद जब पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक केस दर्ज किया था कि भारत ने उसके सैनिक विमान को मार गिराया, तब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई से साफ मना कर दिया था। अब पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि जाधव मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है।

हालांकि वियना कन्वेंशन पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार, अगर देश के किसी नागरिक के साथ किसी दूसरे देश में कोई नाइंसाफी होती है या बुरा व्यवहार होता है, तो वह देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसी मुद्दे पर भारत इस बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया है। पाकिस्तान में अगर सैनिक अदालत की बजाए कुलभूषण जाधव को नागरिक अदालत के समक्ष पेश किया जाता, तो शायद भारत को इतनी आपत्ति नहीं होती। सैनिक अदालत ने जो रुख अपनाया, वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। जाधव से न तो मिलने दिया गया और न ही कानूनी सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई। यह भी नहीं बताया गया कि जाधव के खिलाफ किन-किन मामलों में कार्यवाही

की गई है? हालांकि पाकिस्तान ने शुरू से ही इस बात को नहीं माना है कि इस मामले में वियना कन्वेंशन लागू होता है, क्योंकि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी के कार्यरत अधिकारी हैं तथा यह पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अतः इस मामले में कांसुलर सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। जबकि भारत ने कहा है कि जाधव ईरान व्यापार के लिए गए थे। उनका किसी खुफिया एजेंसी से कोई संपर्क नहीं है। इस तरह के मुद्दों पर इतना स्पष्ट वक्तव्य भारत की ओर से शायद पहली बार आया है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई की शुरुआत इसी मुद्दे से हुई कि क्या न्यायालय को जाधव मामले पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का मानना है कि वियना कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुच्छेद I इस मामले में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आधार प्रदान करता है। इसके अनुसार, वियना कन्वेंशन के प्रयोग अथवा निर्वचन से संबंधित विवादों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है।

इस संबंध में न्यायालय ने यह नोटिस किया है कि वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण जाधव को कांसुलर सहायता के भारत के प्रश्न पर दोनों पक्षों में वास्तव में मतभेद है। भारत द्वारा आरोप लगाया गया है कि जाधव की गिरफ्तारी और नजरबंदी के संबंध में आवश्यक राजनयिक सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा उन तक भारत की पहुंच प्रदान करने में पाकिस्तान की विफलता वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। न्यायालय के विचार में वैकल्पिक प्रोटोकॉल के अनुच्छेद I के प्रावधान इस बात के प्रमाण हैं कि प्रथम दृष्ट्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का इस मामले पर क्षेत्राधिकार है। न्यायालय ने आगे कहा कि भारत-पाकिस्तान के मध्य वर्ष 2008 में हुए कांसुलर संबंधों पर द्विपक्षीय समझौते का न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

❑ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अंतरिम निर्णय

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 'जाधव केस : भारत बनाम पाकिस्तान' पर सुनवाई अभी जारी है। न्यायालय के 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को देख रही है। इसमें शामिल न्यायाधीशों में रॉनी अब्राहम (अध्यक्ष), हिसाशी ओवाडा, कानकाडो ट्रिनडेड, शू हैनकिन, जोआन डोनोघुई, जॉर्जियो गाजा, जूलिया सेबुटिंडे, दलबीर भंडारी, पैट्रिक रॉबिन्सन, जेम्स क्राफोर्ड तथा किरिल जेवार्जियन हैं। ध्यातव्य है कि इसमें शामिल दलबीर भंडारी का संबंध भारत से है।

15 मई, 2017 को भारत तथा पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने, तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद फैजल ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। उस दौरान ही भारतीय वकील हरीश साल्वे ने यह आशंका जताई कि पाकिस्तान सुनवाई पूरी होने से पहले ही कहीं जाधव को फांसी न दे दे। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। अपने अंतरिम आदेश में न्यायालय ने कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता तब तक जाधव को दी गई फांसी की सजा को निष्पादित नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए की जा रही कार्यवाही की सूचना न्यायालय को देनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा जून, 1945 में की गई थी तथा इसने अप्रैल, 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। यह 'द हेग' (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस (Peace Palace) में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से यही एकमात्र अंग ऐसा है, जो न्यूयॉर्क (सं.रा. अमेरिका) में स्थित नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, राज्यों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करता है तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी सवालों पर सलाह देने का कार्य करता है।

इस प्रकार न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने तक जाधव की फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में भारत को 13 सितंबर, 2017 तक जवाब दाखिल करने को कहा है, जबकि पाकिस्तान को 13 दिसंबर, 2017 तक जवाब दाखिल करना है।

❑ पाकिस्तान द्वारा निर्णय की अवहेलना पर क्या होगा?

पाकिस्तान द्वारा लगातार इस बात की दलील दी जाती रही है कि जाधव मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फैसला भारत के पक्ष में जाने पर अगर पाकिस्तान न्यायालय के निर्णय का पालन न करे तो? क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अधिकार है कि वह निर्णय का पालन करवा सके? आगे क्या हो सकता है?

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को उन मामलों में न्यायालय के फैसले का पालन करना होगा जिसमें वे एक पक्ष हैं। भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इसकी पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन का एक 'वैकल्पिक प्रोटोकॉल' भी है जो विवादों के अनिवार्य समाधान की बात करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इस प्रोटोकॉल के एक पक्ष हैं।

विवादास्पद मामलों में न्यायालय का निर्णय अंतिम और अपील रहित होता है, यद्यपि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपने निर्णय को

लागू करवाने का कोई उपकरण नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही है जो राज्यों पर न्यायालय के निर्णय को मानने को लेकर दबाव बना सकता है। लेकिन इसमें भी कई समस्याएं हैं–

(i) निर्णय अगर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के खिलाफ हो, तो वे वीटो कर सकते हैं। अमेरिका बनाम निकारागुआ मामले में ऐसा हो चुका है, जब निर्णय अमेरिका के खिलाफ आया था। इसके अलावा चीन, जो कि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, वह पाकिस्तान के पक्ष में जाधव केस मामले में वीटो कर सकता है।

(ii) सुरक्षा परिषद इस मामले में हस्तक्षेप से मना कर सकती है और तब फैसले को लागू कराने का कोई और तरीका नहीं होगा।

(iii) अगर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दांव पर लगी हो, तो सुरक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा परिषद ने कभी ऐसा किया नहीं है।

कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन

यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य कांसुलर संबंधों के लिए ढांचे को परिभाषित करता है। इस समझौते पर 24 अप्रैल, 1963 को वियना में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 19 मार्च, 1967 से प्रभावी हुआ। अब तक कुल 179 देश इस समझौते में पार्टियां हैं, जबकि 48 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने 28 नवंबर, 1977 को इस समझौते का परिग्रहण (Accession) किया था, जबकि पाकिस्तान द्वारा इसका 14 अप्रैल, 1969 को परिग्रहण किया गया। इस समझौते के अनुच्छेद 36 के तहत राज्यों को दूसरे राज्यों में गिरफ्तार किए गए अपने नागरिकों से संचार और संपर्क स्थापित करने का अधिकार है।

❑ निष्कर्ष

महाकवि रबींद्रनाथ टैगोर का कथन है ''तथ्य कई होते हैं जबकि सत्य एक ही होता है''। यह अलग बात है कि प्रत्येक तथ्य अपनी सत्यता का दावा अवश्य करता है। यह तथ्य ही है कि भारत और पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस दृष्टि से भारत में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान एक कमजोर एवं विफल राष्ट्र की श्रेणी में शामिल किए जाने की कगार पर खड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का साया न केवल वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, बल्कि निर्वाचित सरकार पर भी मंडराता रहता है। आज पाकिस्तान में शक्ति के कई केंद्र विकसित हो गए हैं जिनमें आपसी खींचतान लगी रहती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी संबंधों को सुधारने की बात शुरू होती है, तो पाकिस्तानी सेना द्वारा तुरंत किसी न किसी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश होती है जिससे संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया ठप हो जाए। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा भारत से संबंधों को सुधारने के संबंध में वक्तव्य दिया गया था, संभवतः प्रतिक्रिया में ही वहां की सेना द्वारा कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर एक बार फिर माहौल में तल्खी को बढ़ावा दे दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि सेना, जाधव मामले पर पाकिस्तानी सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख को गिराकर सत्ता को खुद हस्तगत करने की सोच रही हो। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर दोनों देश (भारत-पाकिस्तान) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हैं।

भारत की पहली जीत हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई हेतु न केवल स्वीकार किया, बल्कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत के निर्णय पर अंतरिम रोक भी लगा दी। भारत कांसुलर सहायता तथा मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे पर न्यायालय गया है। पाकिस्तान भी अपने पक्ष में तथ्यों का पुलिंदा लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि इन तथ्यों में सत्यता कितनी है। यह सही है कि कुलभूषण जाधव के लिए भारत को अभी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन यह संभवतः पहली बार हुआ कि भारत सरकार अपने नागरिक को बचाने के लिए इस सीमा तक गई तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसका कारण शायद यह भी था कि मामला पाकिस्तान से जुड़ा था और जनभावनाएं यह मांग कर रहीं थीं कि सरकार जाधव को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए। भले ही भारत को शुरुआती सफलता प्राप्त हुई हो, लेकिन आगे की राह बहुत कठिन है। फिलहाल मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में है और करोड़ों भारतवासियों को न्याय की अपेक्षा है।

सारांश

- ◆ कुलभूषण सुधीर जाधव भारतीय नागरिक एवं पूर्व नौसेना अधिकारी हैं।
- ◆ पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में 10 अप्रैल, 2017 को फांसी की सजा सुनाई।
- ◆ 8 मई, 2017 को भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दाखिल।
- ◆ 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ में रॉनी अब्राहम अध्यक्ष तथा दलबीर भंडारी (भारत) शामिल।
- ◆ कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन 19 मार्च, 1967 से प्रभावी हुआ।
- ◆ भारत ने 28 नवंबर, 1977 को इस समझौते का परिग्रहण (Assession) किया।
- ◆ जून, 1945 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अप्रैल, 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- ◆ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 'द हेग' (नीदरलैंड्स) में स्थित है।

■■■

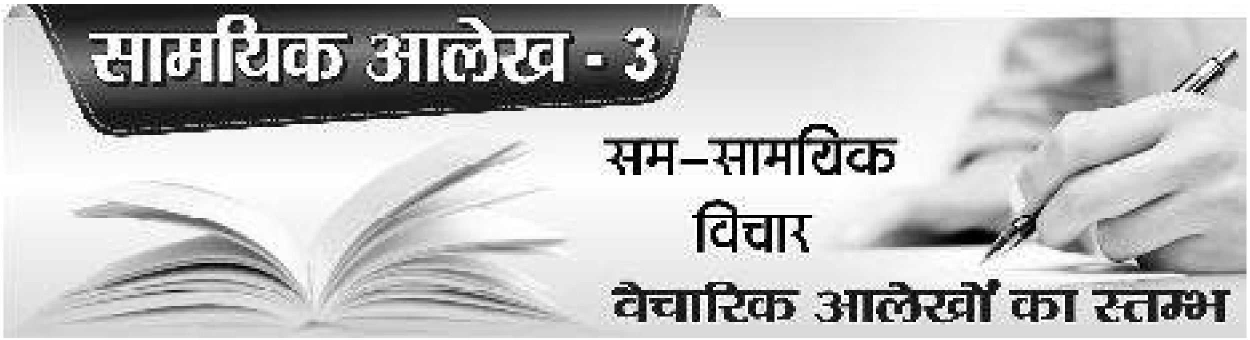

जी-7 का ताओरमिना सम्मेलन

— विकास कुमार शुक्ल

“त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे
द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलौयुगे।’’

ऋग्वेद में वर्णित इस श्लोक में युग विशेष में शक्ति के प्रमुख स्रोत की व्याख्या की गई है। श्लोक के अनुसार, सतयुग में ज्ञान, त्रेता में मंत्र, द्वापर में युद्ध तथा कलियुग में संगठन शक्ति का मूल स्रोत होगा। ऋग्वेद की यह भविष्यवाणी आधुनिक संदर्भ में काफी हद तक प्रासंगिक भी प्रतीत हो रही है। आधुनिक वैश्विक युग में जहां संभावनाएं एवं चुनौतियां दोनों काफी व्यापक हो गई हों, अवसरों का दोहन एवं चुनौतियों (आतंकवाद, अतिवाद, पर्यावरणीय असंतुलन, आर्थिक अस्थिरता, खाद्य असुरक्षा आदि) का सामना स्वयं ही कर लेने का सामर्थ्य शायद ही किसी देश के पास है। ऐसे में सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हो गया है। आज वैश्विक व्यवस्था को स्थिर, प्रगतिशील एवं समावेशी बनाने तथा लोगों के अधिकतम कल्याण हेतु अनेक वैश्विक एवं क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से प्रयास किए भी जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास समूह-7 (जी-7) भी है। इस मंच के माध्यम से सात अग्रणी औद्योगिक देशों, प्रमुख आर्थिक संगठनों तथा विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि विश्व व्यवस्था में सुधार हेतु विचार-विमर्श करते हैं। इटली के द्वीपीय शहर ताओरमिना में 26-27 मई, 2017 के मध्य आयोजित जी-7 का 43वां सम्मेलन इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

❑ जी-7 : एक परिचय

जी-7 विश्व के सात सर्वाधिक विकसित एवं औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। इस संगठन का न तो कोई मुख्यालय/सचिवालय है, न ही कोई चार्टर। इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रति वर्ष क्रमिक आधार पर किया जाता है। जी-7 का गठन वैश्विक आर्थिक मंदी एवं तेल संकट की पृष्ठभूमि में, वर्ष 1975 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वेलेरी जिस्कार्ड डी ‘एस्टेइंग के आह्वान पर विश्व के सर्वाधिक औद्योगीकृत, लोकतांत्रिक एवं गैर-समाजवादी 6 राष्ट्रों यथा- फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी एवं जापान द्वारा जी-6 के रूप में किया गया था। वर्ष 1976 में कनाडा के सम्मिलन से इसे जी-7 जबकि वर्ष 1997 में रूस के सम्मिलन के उपरांत इसे जी-8 की संज्ञा दी गई। परंतु वर्ष 2014 में यूक्रेन की संप्रभुता के अतिक्रमण के आरोप में जी-8 समूह से रूस के निलंबन के पश्चात इसे पुनः जी-7 के नाम से पुकारा जाने लगा।

यद्यपि वैश्विक मंदी के दौर में वर्ष 2009 में जी-20 के पिट्सबर्ग सम्मेलन में जी-20 (जी-7 तथा 13 अन्य विशाल अर्थव्यवस्थाएं) को वैश्विक आर्थिक मामलों का मुख्य आधिकारिक मंच घोषित किए जाने के बाद जी-7 के महत्व में कुछ कमी आई तथापि, आज भी यह मंच विश्व व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व जीडीपी, सकल विश्व निर्यात तथा आयात में एक-तिहाई की हिस्सेदारी रखने वाले जी-7 के तीन राष्ट्र (सं.रा. अमेरिका, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा एवं सहयोगात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक वर्ष जी-7 की शिखर बैठक आयोजित की जाती है। इटली की अध्यक्षता में ताओरमिना शहर में 26-27 मई, 2017 के मध्य आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन, 2017 इन्हीं बैठकों की श्रृंखला की 43वीं कड़ी है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी ने की।

ताओरमिना सम्मेलन के प्रतिभागी

देश	प्रतिनिधि	पद
कनाडा	जस्टिन ट्रूडे	प्रधानमंत्री
फ्रांस	इमैनुएल मैक्रों	राष्ट्रपति
जर्मनी	एंजेला मर्केल	चांसलर
इटली	पाओलो जेंटिलोनी	प्रधानमंत्री
जापान	शिंजो अबे	प्रधानमंत्री
सं.रा. अमेरिका	डोनाल्ड ट्रंप	राष्ट्रपति
यूके	थेरेसा मे	प्रधानमंत्री
यूरोपियन यूनियन	जीन-क्लाड जंकर	यूरोपीय कमीशन अध्यक्ष
	डोनाल्ड टस्क	यूरोपीय काउंसिल अध्यक्ष

देश/अं. संगठन	आमंत्रित अतिथि	पद
इथिओपिया	हैले मरियम दीसालेग्न	प्रधानमंत्री
केन्या	उहूरू केन्याटा	राष्ट्रपति
नाइजर	महामेदु इसोफू	राष्ट्रपति
नाइजीरिया	येमी ओसिंबाजो	उप प्रधानमंत्री
ट्यूनीशिया	बेजी कैद इसेब्जि	राष्ट्रपति
संयुक्त राष्ट्र संघ	ऐंटोनियो गुटेरेस	महासचिव
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	क्रिस्टीन लैगार्डे	प्रबंध निदेशक
विश्व बैंक	जिम योंग किम	अध्यक्ष
OECD	एंजेल गुरिया	महासचिव
अफ्रीकन यूनियन कमीशन	मउसा फाकी	अध्यक्ष
अफ्रीकी विकास बैंक	अकिंवुमी अडेसिना	अध्यक्ष
अफ्रीकन यूनियन	अल्फा कोंडे	अध्यक्ष (राष्ट्रपति गिनी)

जी-7 एवं रूस

- विघटन के पश्चात रूस ने आर्थिक उदारीकरण एवं बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाकर जी-7 राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित किया।
- वर्ष 1994 से रूस जी-7 के साथ अलग से बैठकों में सम्मिलित होने लगा।
- वर्ष 1997 में डेनेवर (कोलोराडो, अमेरिका) में आयोजित 23वीं शिखर बैठक में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के आमंत्रण पर तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने जी-7 की वार्षिक शिखर बैठक में प्रतिभाग किया था। तभी से यह समूह जी-8 के नाम से जाना जाने लगा।
- रूस की सहभागिता वर्ष 2013 तक ही रही। 40वीं शिखर बैठक जून, 2014 में रूसी शहर सोची में प्रस्तावित थी, किंतु यूक्रेन के संबंध में रूसी नीति के विरोध में न केवल इस बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया अपितु रूस को अस्थायी तौर पर समूह से निलंबित भी कर दिया गया।

जी-7 की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति

(आंकड़े प्रतिशत में)

देश	विश्व GDP में हिस्सेदारी (2016)	संवृद्धि दर 2016	जनसंख्या में हिस्सेदारी (2016)	वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी (2016)
सं.रा. अमेरिका	15.5	1.6	4.4	10.8
जर्मनी	3.3	1.8	1.1	7.8
फ्रांस	2.3	1.2	0.9	3.5
इटली	1.9	0.9	0.8	2.7
जापान	4.4	1.0	1.7	3.9
यूके	2.3	1.8	0.9	3.6
कनाडा	1.4	1.4	0.5	2.3
जी-7 देश	**31.1**	–	**10.3**	**34.6**
विश्व	**100**	**3.1**	**100**	**100**

स्रोत - विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल, 2017 (IMF)

❑ सम्मेलन के आधार स्तंभ

वर्ष 2017 के शिखर सम्मेलन का प्रमुख मिशन है–''नए विश्वास के आधार का निर्माण'' (Building the Foundation of Renewed Trust)। जी-7 का यह एजेंडा तीन आधार स्तंभों पर आधारित है–(i) नागरिक सुरक्षा; (ii) आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक धारणीयता तथा असमानता में कमी तथा (iii) भावी उत्पादन क्रांति के युग में नवप्रवर्तन, कौशल एवं श्रम।

प्रथम स्तंभ आज की भौगोलिक अस्थिरता, मध्य-पूर्व तथा उत्तरी एवं उपसहारा अफ्रीका में संकट, वैश्विक आतंकवाद, शरणार्थी समस्या आदि की पृष्ठभूमि में नागरिकों की चिंताओं पर केंद्रित है।

द्वितीय स्तंभ एजेंडा-2030 के तहत धारणीय विकास पर केंद्रित है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुपालन, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, स्वास्थ्य, लैंगिक समता, महिलाओं एवं बालिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण तथा उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें समानता पर विशेष जोर दिया गया है। आय एवं परिसंपत्ति की समानता के साथ-साथ इसके तहत लिंग अथवा नृजातीयता के आधार पर होने वाले सभी विभेदों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच के संदर्भ में भी समस्त विभेदों को समाप्त करना भी सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य है।

तीसरा आधार स्तंभ अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा नवप्रवर्तन के माध्यम से वैश्विक समावेशी संवृद्धि की प्राप्ति हेतु समर्पित है। यह भावी उत्पादन क्रांति (चौथी औद्योगिक क्रांति) के अनुरूप नीति-निर्माण, नवप्रवर्तन, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण आदि जैसे कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कि सभी के हितों का संरक्षण किया जा सके।

❑ सम्मेलन की उपलब्धियां

26-27 मई, 2017 के मध्य संपन्न हुए सम्मेलन के उपरांत ताओरमिना घोषणा-पत्र जारी किया गया जिसमें कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना तथा धारणीय वैश्विक विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। सभी प्रतिभागियों ने स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र, शांति, सुरक्षा तथा मानवाधिकारों के सम्मान पर जोर देते हुए 'शून्य भुखमरी' (Zero Hunger) के लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया। इस मंच के माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि जनता की आकांक्षा ही सरकारों की नीति के केंद्र में है जिसे सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम जनता के सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया जाएगा। सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

● वैश्विक अर्थव्यवस्था

जी-7 के मंच से ऐसी वैश्विक संवृद्धि को अधिमान दिया गया है जो सभी के लिए उच्चतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन भी करे। ऐसी सुदृढ़, धारणीय संतुलित एवं समावेशी संवृद्धि की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर मिश्रित नीति (मौद्रिक, राजकोषीय तथा संरचनात्मक नीति का समन्वयन) की रणनीति अपनाने पर बल दिया गया है।

● व्यापार

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं परस्पर लाभ प्रदान करने वाले व्यापार एवं निवेश को विकास एवं रोजगार का इंजन मानते हुए सदस्य देशों ने अपने बाजारों को खोलने, संरक्षणवाद का विरोध करने तथा सभी प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं (डंपिंग, गैर-प्रशुल्क बाधाएं, बाध्यकारी तकनीकी हस्तांतरण, अनुचित सहायिकी आदि) के खिलाफ खड़े होने का संकल्प जताया है।

जी-7 एवं अफ्रीका

जी-7 सम्मेलन में अफ्रीकी विकास की गति को तीव्र करने तथा अफ्रीका में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को सुनिश्चित कर इसे भावी निवेश गंतव्य बनाने हेतु व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जी-7 देशों द्वारा अफ्रीकी विकास को अपनी उच्च प्राथमिकता करार देते हुए अफ्रीका में सतत विकास लक्ष्यों (एजेंडा-2030) तथा अफ्रीकी यूनियन के एजेंडा-2063 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आश्वासन दिया गया। अफ्रीकी विकास हेतु चार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इस प्रकार हैं– (i) एक शांत, सुरक्षित एवं स्थिर अफ्रीका का निर्माण, (ii) नवप्रवर्तन एवं मानव पूंजी के विकास द्वारा अफ्रीकी क्षमता में वृद्धि करना, (iii) अफ्रीका को सकारात्मक रूप से गतिशील करना तथा (iv) अफ्रीका में नई पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहन देना।

● वैदेशिक मुद्दे

सम्मेलन में कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण पर जोर दिया गया है जिससे सभी राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित की जा सके तथा उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। सम्मेलन में वैश्विक आतंकी गतिविधियों तथा मानवाधिकारों के हनन के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसके समाधान हेतु राजनीतिक निदान को सर्वाधिक महत्व दिया गया तथा सभी देशों से संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इस दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया गया । जी-7 के मंच से परमाणु अप्रसार एवं निःशस्त्रीकरण के संकल्प को पुनः दोहराया गया तथा इसका परिपालन न करने हेतु उत्तर कोरिया की निंदा की गई। इसके अतिरिक्त समुद्री विवादों के असैन्यीकरण का भी आह्वान किया गया तथा इन पर विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ने का आह्वान किया गया।

मंच से साइबर हमले की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया हेतु प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई।

● असमानता एवं लैंगिक विभेद

असमानता को आत्मविश्वास एवं संवृद्धि क्षमता को सीमित करने वाला मानते हुए जी-7 के मंच से इसके सभी रूपों की समाप्ति की घोषणा की गई। इसे व्यापक संदर्भ में लेते हुए न केवल आय की असमानता अपितु इसके सभी सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप की समाप्ति को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। सम्मेलन में बालिकाओं एवं महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु **''जी-7 लिंग-उत्तरदायी आर्थिक पर्यावरण के लिए रोडमैप'** (G-7 Roadmap for a Gender-Responsive Economic Environment) को भी अपनाया गया।

● स्वास्थ्य

स्वस्थ एवं अच्छे जीवन को सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सभी के लिए सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक नीतिगत प्रयास की रणनीति पर चर्चा की गई।

● मानव गतिशीलता

इस मंच से प्रवासियों एवं शरणार्थियों में अंतर कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों दृष्टिकोण से उचित प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया। शरणार्थियों हेतु यथासंभव उनके देश के नजदीक सहायता एवं सहयोग उपलब्ध करवाना तथा उन्हें सुरक्षित वापस भेजने एवं उन्हें अपना घरेलू समुदाय बनाने हेतु उचित सहायता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

● खाद्य सुरक्षा एवं पोषण

भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति, पोषण स्तर में सुधार एवं धारणीय कृषि को प्रोत्साहन देना जी-7 देशों की प्राथमिकता में है। इसी के दृष्टिगत जी-7 देशों द्वारा वर्ष 2030 तक विकासशील देशों के

500 मिलियन लोगों को भुखमरी एवं कुपोषण से बाहर निकालने का सामूहिक लक्ष्य रखा गया है। जी-7 के मंच से वर्तमान एवं भविष्य के भुखमरी संकट से निपटने हेतु एवं प्रभावी, सुदृढ़ एवं लोचशील अंतरराष्ट्रीय तंत्र के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। सम्मेलन में अफ्रीका की दयनीय स्थिति के मद्देनजर अफ्रीका पर विशेष ध्यान देने तथा सहायता में वृद्धि की बात भी कही गई है।

● पर्यावरण एवं ऊर्जा

सम्मेलन में सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए ऊर्जा संसाधनों एवं तकनीकी हेतु एक खुले, पारदर्शी एवं सुरक्षित वैश्विक बाजार की स्थापना को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र के रूपांतरण एवं स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने से संवृद्धि एवं रोजगार सृजन की संभावना को देखते हुए भावी रणनीति पर भी विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस दृष्टि से विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करने पर भी सहमति बनी।

● नवप्रवर्तन, कौशल एवं श्रम

इस सम्मेलन में आगामी उत्पादन क्रांति (Next Production Revolution : NPR) पर व्यापक विमर्श किया गया। आटोमैटिक उत्पादन आधारित नवीन उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न असाधारण अवसरों एवं भावी रोजगार चुनौतियों के दृष्टिगत शिक्षा, कौशल एवं नवप्रवर्तन में सुधार तथा श्रम बाजार की नीतियों को लोचशील बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस दृष्टि से **'जी-7 नवप्रवर्तन, कौशल एवं श्रम पर व्यक्ति-केंद्रित कार्य-योजना'** (G-7 People-Centered Action Plan on Innovation, Skill and Labour) को भी अपनाया गया।

❑ समीक्षा

जी-7 के 43वें शिखर सम्मेलन का केंद्रबिंदु 'विश्वास बहाली' रहा। सम्मेलन में नागरिकों एवं सरकार के मध्य विश्वास तथा सरकारों के मध्य विश्वास को बढ़ाकर एक कानून आधारित वैश्विक प्रणाली की परिकल्पना की गई। यह सम्मेलन व्यक्तियों की सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित कराने, उन्हें भावी चुनौतियों हेतु तैयार करने तथा उन्हें एक बेहतर कल उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। असमानता के सभी रूपों की समाप्ति तथा लैंगिक समता की प्राप्ति का संकल्प सराहनीय है। सम्मेलन में अफ्रीका पर विशेष ध्यान देना सम्मेलन के मानवीय स्वरूप को भी उजागर करता है। पेरिस समझौते के परिपालन हेतु विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। समग्र रूप से यह सम्मेलन विकसित देशों के वैश्विक उत्तरदायित्व की दिशा में एक सार्थक कदम नजर आता है। अब आवश्यकता इन घोषणाओं के परिपालन को सुनिश्चित कराने की है। सभी देशों को अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर एक न्याय आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण हेतु आगे आना होगा तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगामी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना होगा, तभी सम्मेलन सार्थक होगा अन्यथा यह सम्मेलन भी एक चाय पार्टी मात्र बन कर रह जाएगा। आशा है कि वर्ष 2018 में कनाडा में होने वाले आगामी सम्मेलन तक इन घोषणाओं के सार्थक परिणाम प्राप्त हो चुके होंगे।

सारांश

- ◆ इटली के द्वीपीय शहर ताओरमिना में 26-27 मई, 2017 के मध्य जी-7 का 43वां सम्मेलन आयोजित।
- ◆ जी-7 में सम्मिलित देश हैं-फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, जापान तथा कनाडा।
- ◆ शिखर सम्मेलन का प्रमुख मिशन, ''नए विश्वास के आधार का निर्माण।
- ◆ सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी द्वारा।
- ◆ ताओरमिना घोषणा-पत्र जारी।
- ◆ वर्ष 2030 तक विकासशील देशों के 500 मिलियन लोगों को भुखमरी व कुपोषण से बाहर निकालने का लक्ष्य।
- ◆ जी-7 देशों की हिस्सेदारी–
  - (i) विश्व जनसंख्या में - 10.3 प्रतिशत
  - (ii) विश्व जीडीपी में - 31.1 प्रतिशत ■■■■■■■■■■■■

■■■

फोकस

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे

दक्षिण एशिया उपग्रह का प्रक्षेपण

● पृष्ठभूमि

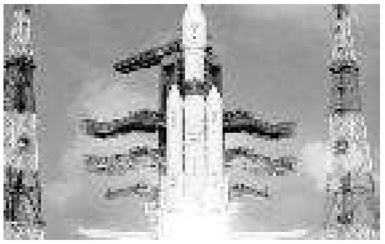

26 मई, 2014 को अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों/प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित कर इन देशों के साथ भारत के संबंधों के एक नए दृष्टिकोण का संकेत दिया था। जून, 2014 में इसरो द्वारा फ्रांस के स्पॉट-7 (SPOT-7) समेत पांच उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के अवसर पर भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसरो को एक 'सार्क उपग्रह' (Saarc Satellite) विकसित करने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री की उपर्युक्त आकांक्षा के दृष्टिगत इसरो ने जीसैट-9 उपग्रह का विकास एवं प्रक्षेपण किया है। जीसैट-9 उपग्रह परियोजना में शामिल होने से पाकिस्तान द्वारा इंकार किए जाने के कारण इस उपग्रह को सार्क उपग्रह के बजाय 'दक्षिण एशिया उपग्रह' नाम दिया गया।

● प्रक्षेपण

➡ 5 मई, 2017 का दिन दक्षिण एशियाई देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 'जीसैट-9' (GSAT-9) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया।

➡ जीसैट-9 उपग्रह को 'दक्षिण एशिया उपग्रह' नाम दिया गया है।

- ➲ उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान 'जीएसएलवी-एफ09' (GSLV-F09) द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा के द्वितीय लांच पैड से किया गया।
- ➲ यह जीएसएलवी की कुल 11वीं जबकि स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ लगातार चौथी सफल उड़ान थी।

सारांश

◆ 5 मई, 2017 को जीसैट-9 का प्रक्षेपण जीएसएलवी-F09 द्वारा।

◆ जीसैट-9 का अन्य नाम दक्षिण एशिया उपग्रह।

◆ जीसैट-9 है : एक संचार उपग्रह

◆ जीसैट-9 के माध्यम से भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं श्रीलंका को दूरसंचार एवं प्रसारण अनुप्रयोग सेवाएं प्राप्त होंगी।

● जीसैट-9 (दक्षिण एशिया उपग्रह)

➡ दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) इसरो द्वारा निर्मित एक भूस्थिर संचार उपग्रह है।

➡ उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को केयू बैंड (Ku-Band) में विभिन्न संचार अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है।

- ➲ जीसैट-9 उपग्रह इसरो के मानक 'आई-2 के बस' (I-2K Bus) के समनुरूप है।
- ➲ 2230 किग्रा. उत्थापन द्रव्यमान (Lift-off Mass) वाला यह उपग्रह आकार में घनाभ (Cuboid) है जो एक केंद्रीय सिलेंडर के चारों ओर निर्मित है।
- ➲ उपग्रह में केयू-बैंड में परिचालित होने वाले संचार ट्रांसपोंडर लगे हैं।
- ➲ अल्ट्रा ट्रिपल जंक्शन सोलर सेल (Ultra Triple Junction Solar Cells) से युक्त उपग्रह के दो सौर ऐरे (SolarArrays) 3500 वॉट बिजली उत्पन्न करते हैं।

➡ जीसैट-9 उपग्रह में 'एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम' (AOCS), मोमेंटम व्हील्स, मैग्नेटिक टार्कर्स एंड थ्रस्टर्स, लिक्विड एपोजी मोटर (LAM), प्लाज्मा थ्रस्टर्स आदि उपकरण संलग्न हैं।

दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) की प्रमुख विशेषताएं	
मिशन	संचार उपग्रह
कक्षा	भूस्थिर
द्रव्यमान	शुष्क द्रव्यमान - 976 किग्रा. उत्थापन द्रव्यमान - 2230 किग्रा.
भौतिक आयाम	1.53 मी. × 1.65 मीटर × 2.40 मीटर
ऊर्जा उत्पादन	3500 वॉट, दो 90 एएच लिथियम आयन बैट्री
नीतभार	केयू - बैंड ट्रांसपोंडर
मिशन अवधि	12 वर्ष
कवरेज क्षेत्र	दक्षिण एशियाई देश

● जीएसएलवी-एफ09

➡ भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एफ-09 द्वारा दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट-9 को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit : GTO) में प्रक्षेपित किया गया।

- ➲ जिसके बाद कई चरणों में उपग्रह के लैम (LAM) को दागकर उसे अंतिम वृत्ताकार भूस्थिर कक्षा (GSO) में पहुंचा दिया गया।

➡ जीएसएलवी के इस संस्करण (मार्क II) को 2 से 2.50 टन भार वर्ग के उपग्रहों को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

➡ जीएसएलवी-एफ09 की कुल लंबाई 49.1 मीटर है।

➡ जीएसएलवी-एफ09 का अभिविन्यास (Configuration) जनवरी, 2014, अगस्त, 2015 और सितंबर, 2016 में प्रक्षेपित क्रमशः जीएसएलवी-डी5, जीएसएलवी-डी 6 एवं जीएसएलवी-एफ05 के समनुरूप है।

- ➲ विगत प्रक्षेपणों में जीएसएलवी-डी5 एवं जीएसएलवी-डी6 के द्वारा भारत के 2 संचार उपग्रहों क्रमशः जीसैट-14 तथा जीसैट-6 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था।
- ➲ जबकि भारत के मौसम उपग्रह इनसैट-3डीआर को जीएसएलवी-एफ05 द्वारा भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया था।

● दक्षिण एशिया उपग्रह के अनुप्रयोग

➡ दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) विभिन्न दूरसंचार एवं प्रसारण अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

- ➲ उपग्रह का उपयोग आपदा प्रबंधन सहायता, मौसम विज्ञान-संबंधी आंकड़ों के प्रसारण और शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों को जोड़ने (नेटवर्किंग) जैसे अनुप्रयोगों में किया जाएगा।
- ➲ उपग्रह के माध्यम से सदस्य देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका के मध्य क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा।
- ➲ दक्षिण एशिया उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत के इन छः पड़ोसी देशों के मध्य संचार प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा और आपदा संपर्क में सुधार होगा।

● दक्षिण एशियाई देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम

➡ पाकिस्तान ने भारत के दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना में यह कहते हुए शामिल होने से इंकार कर दिया था कि उसका एक स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम है।

➡ पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी 'सुपार्को' (SUPARCO : Space and Upper Atmosphere Research Commission) ने 7 जून, 1962 को द्विचरणीय रॉकेट 'रहबर-1' (REHBAR-1) का प्रक्षेपण किया था।

- ➲ इस प्रक्षेपण के साथ पाकिस्तान बाहरी अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाला एशिया का तीसरा एवं विश्व का 10वां देश बन गया था।
- ➲ पाकिस्तानी अंतरिक्ष संस्था द्वारा 9 जून, 1962 को 'रहबर-II' रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया।
- ➲ पाकिस्तान ने अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह 'बद्र-1' (BADR-I) का प्रक्षेपण 16 जुलाई, 1990 को चीन के प्रक्षेपण यान लांग मार्च 2ई से किया था।
- ➲ पाकिस्तान के दूसरे प्रायोगिक उपग्रह 'बद्र-बी (BADR-B) का प्रक्षेपण 10 दिसंबर, 2001 को बाइकोनूर (Baikonur), कजाख्स्तान से किया गया।
- ➲ 11 अगस्त, 2011 को पाकिस्तान के पहले संचार उपग्रह 'पाकसैट-1 आर' का प्रक्षेपण किया गया।
- ➲ इस उपग्रह का विकास एवं प्रक्षेपण 'चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन' (CGWIC) द्वारा किया गया।

➡ नवंबर, 2012 में श्रीलंका के पहले संचार उपग्रह सुप्रीम सैट-1 का प्रक्षेपण चीन के 'झिचांग' (Xichang) उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया।

➡ बांग्लादेश द्वारा अपने पहले संचार उपग्रह 'बंगबंधु-1' का प्रक्षेपण किए जाने की योजना है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क में शामिल 8 देश हैं- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। इसका सचिवालय जनवरी, 1987 में काठमांडू में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना आदि है।

● निष्कर्ष

भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के उपयोग के लिए 'दक्षिण एशिया उपग्रह' के प्रक्षेपण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'उपग्रह कूटनीति' के तौर पर देखा जा रहा है। उपग्रह प्रक्षेपण के बाद आह्लादित भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा ''इस उपग्रह के प्रक्षेपण किए जाने से हमने अपने सहयोग को अत्याधुनिक बनाने की यात्रा शुरू की है। दक्षिण एशिया सहयोग का यह प्रतीक क्षेत्र के 1.5 बिलियन लोगों की आर्थिक प्रगति की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और अंतरिक्ष में हमारे घनिष्ठ संबंधों का विस्तार करेगा।'' इस उपग्रह के प्रक्षेपण से दक्षिण एशियाई देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं श्रीलंका को आपदा सूचना, बेहतर शासन संचालन, टेलीएजुकेशन, टेलीमेडिसिन, मौसम का पूर्वानुमान आदि के साथ एक-दूसरे देश के लोगों के मध्य संपर्क की सुविधा प्राप्त होगी।

सं. नीरज ओझा

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017

● लोक सभा में पारित

➡ 5 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा लोक सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया।

➲ इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिया गया।

➲ वर्तमान में यह विधेयक राज्य सभा में विचाराधीन है।

● उद्देश्य

➡ इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि यह और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।

➲ वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का भी परीक्षण करता है।

➲ विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

● राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

➡ इस आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है।

➲ इस आयोग को किसी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है।

➲ प्रस्तावित विधेयक में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और उनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों का परीक्षण करने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

➡ उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 भी पेश किया गया था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 को निरस्त किया जाना है।

● आयोग की संरचना

इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। इन सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा नियमों के माध्यम से किया जाएगा।

● आयोग के कार्य

इस विधेयक के तहत आयोग के निम्न कार्य प्रस्तावित हैं–

(i) संविधान तथा अन्य क्रियान्वित कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का किस प्रकार कार्यान्वयन हो रहा है, इसकी जांच एवं निगरानी करना।

(ii) अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों में पूछताछ

(iii) ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सलाह देना तथा सिफारिश करना।

➡ केंद्र और राज्य सरकारें, ऐसे सभी मुद्दों, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करते हों, पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेंगी।

➡ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा, जिसे संसद तथा संबंधित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

● सिविल कोर्ट के अधिकार

इस विधेयक के तहत एनसीबीसी के पास किसी भी शिकायत की छानबीन या जांच के लिए सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। इसमें (i) लोगों को समन करना और शपथ दिलवाकर उनसे पूछताछ करना, (ii) किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहना और (iii) साक्ष्य प्राप्त करना, शामिल है।

● पिछड़े वर्गों का निर्धारण

विधेयक के अनुसार, भारतीय संविधान में नए अनुच्छेद 342 (क) को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह ले सकते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करना हो, तो संसद द्वारा विधि निर्माण की जरूरत होगी।

● निष्कर्ष

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की, और अधिक प्रभावी रूप में सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। आयोग बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338(ख) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है, जिसके तहत ही नया आयोग स्थापित किया जाना है। इसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

सारांश

- ◆ 10 अप्रैल, 2017 को संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 लोक सभा में पारित।
- ◆ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव।
- ◆ आयोग में पांच सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- ◆ नए अनुच्छेद 338 (ख) व 342 (क) जोड़ने का प्रस्ताव।
- ◆ सिविल कोर्ट के समान अधिकारों से युक्त आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा।
- ◆ आयोग जांच, निगरानी तथा सलाहकारी भूमिकाओं का निर्वहन करेगा।

सं. काली शंकर 'शारदेय'

भारत : संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास का अध्यक्ष निर्वाचित

● भूमिका

शहरीकरण, 21वीं सदी की सर्वाधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों में से एक है। यह वैश्विक स्तर पर अब एक व्यापक रुझान में परिवर्तित हो गया है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक विश्वभर में प्रत्येक 10 में से 6 लोग शहरी क्षेत्रों के निवासी होंगे, जबकि वर्ष 1950 में विश्व की मात्र एक-तिहाई जनसंख्या ही शहरों में निवासित थी। उचित एवं प्रभावी शहरी नियोजन के अभाव में इस तीव्र शहरीकरण के परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं।

तीव्र एवं अनियंत्रित शहरीकरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 1 जनवरी, 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'यूएनएचएचएसएफ' (UNHHSF : United Nations Habitat & Human Settlements Foundation) की स्थापना की। यह शहरीकरण को समर्पित पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र निकाय था।

● संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास

➡ शहरीकरण की उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में 'पहले अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (हैबिटैट-1) का आयोजन वर्ष 1976 में वैंकूवर (कनाडा) में किया गया।

- ➲ इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप वर्ष 1978 में 'संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास : संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम' (UN-Habitat : United Nations Human Settlements Programme) की स्थापना की गई।
- ➲ संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास, मानव बस्तियों तथा सतत शहरी विकास के क्षेत्र में गतिविधियों को समन्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष एजेंसी है।
- ➲ इसका मिशन सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से वहनीय मानव बस्तियों के विकास को बढ़ावा देना तथा सभी के लिए यथोचित आश्रय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

● संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास के अंग

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास के निम्न तीन प्रमुख अंग हैं–

(i) संचालन परिषद (Governing Council)

संचालन परिषद, संयुक्त-राष्ट्र पर्यावास की एक अंतर्सरकारी निर्णय-निर्धारण संस्था है। इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित होती है।

58 सदस्यीय इस परिषद के सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र की 'आर्थिक एवं सामाजिक परिषद' (Economic & Social Council : ECOSOC) द्वारा चार वर्षीय कार्यकाल के लिए किया जाता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सचिवालय (UN-Habitat Secretariat)

यह संयुक्त-राष्ट्र पर्यावास का एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) है। इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में स्थित है।

यह संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास की शहरी पहलों एवं मानव बस्ती विकास परियोजनाओं की डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन एवं उनकी निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

(iii) सीपीआर (CPR : Committee of Permanent Representatives)

यह संस्था एक निश्चित प्रारूप के अंतर्गत संचालन परिषद के निर्णयों के सचिवालय द्वारा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

● संचालन परिषद की 26वीं बैठक

➡ संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास की संचालन परिषद की 26वीं बैठक 8-12 मई, 2017 के मध्य नैरोबी में आयोजित हुई।

- ➲ इस बैठक का केंद्रीय विषय था-'नए शहरी एजेंडे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवसर' (Opportunities for the Effective Implementation of the New Urban Agenda)।
- ➲ उल्लेखनीय है कि अक्टूबर, 2016 में क्वीटो (इक्वाडोर) में हैबिटैट-III कॉन्फ्रेंस के दौरान नए शहरी एजेंडे को अंगीकृत किया गया था।

● भारत को अध्यक्षता

➡ मई, 2017 में भारत को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास का अध्यक्ष चुन लिया गया।

- ➲ भारत की तरफ से केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम. वेंकैया नायडू अगले दो वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास की संचालन परिषद की बैठकों एवं अन्य आयोजनों की अध्यक्षता करेंगे।
- ➲ संचालन परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता भी वेंकैया नायडू ने ही की।

➡ संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास के अस्तित्व में आने के बाद से यह तीसरा अवसर है जब भारत को इस प्रतिष्ठित संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।

- ➲ इसके पूर्व भारत वर्ष 1988 एवं 2007 में संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास की अध्यक्षता कर चुका है।

➡ उल्लेखनीय है कि भारत 14-16 दिसंबर, 2016 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 'आवास एवं शहरी विकास पर छठीं एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस' (6th Asia Pacific Ministerial Conference on Housing & Urban Development : 6th APMCHUD) का मेजबान था और इस नाते भारत को अगले दो वर्षों के लिए APMCHUD के ब्यूरो की अध्यक्षता हासिल हुई है।

- ➲ 8 मई, 2017 को भारत ने नैरोबी में APMCHUD के छठें ब्यूरो की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की।

सारांश

- ◆ वर्ष 1978 में UN-Habitat की स्थापना।
- ◆ 8-12 मई, 2017 के मध्य संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास की बैठक नैरोबी में संपन्न।
- ◆ केंद्रीय विषय : नए शहरी एजेंडे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवसर।
- ◆ भारत को अध्यक्ष चुना गया।
- ◆ इसके पूर्व 1988 एवं 2007 में भी भारत अध्यक्ष रहा।
- ◆ अगले दो वर्षों तक भारत APMCHUD के ब्यूरो की अध्यक्षता करेगा।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु समाधान सिद्धांत

● समीक्षा बैठक

➡ 8 मई, 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

➡ बैठक में वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक परिचालन रणनीति (Operational Strategy) 'समाधान' (SAMADHAN) की घोषणा की गई।

● समाधान : नई परिचालन रणनीति

➡ वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए नई परिचालन रणनीति 'समाधान' (SAMADHAN) के तत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है–

➡ रणनीति का पहला अक्षर 'एस' (S) स्मार्ट नेतृत्व (Smart Leadership) का बोधक है। स्मार्ट नेतृत्व के प्रमुख गुण हैं- परिकल्पना (Vision), लक्ष्य (Mission), जुनून (Passion) एवं आत्मविश्वास (Self belief)।

➲ रणनीति का दूसरा अक्षर 'ए' (A) आक्रामक रणनीति का घोतक है जिसमें शामिल हैं- सोच, रणनीति, सुरक्षा बलों की तैनाती, अभियानों, विकास और सड़क निर्माण में आक्रामकता।

➲ 'एम' (M) अक्षर से तात्पर्य 'प्रेरणा और प्रशिक्षण' (Motivation and Training) से है।

➲ वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सफलता के लिए आवश्यक है- सही परिकल्पना, सही रणनीति, संसाधनों का कुशल उपयोग, दुश्मन की कमजोरी एवं शक्ति का ज्ञान, सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण, उनकी सुविधाओं एवं संसाधनों की व्यवस्था।

➲ इसके अतिरिक्त तैनाती के स्थलों की जानकारी के साथ ही वहां की भाषा, बोली, परंपराओं एवं संस्कृति की जानकारी भी सुरक्षा बलों को होनी चाहिए जिससे कि स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल किया जा सके।

➡ 'ए' (A) अक्षर 'कार्रवाई योग्य आसूचना' (Actionable Intelligence) का द्योतक है।

➡ कार्रवाई योग्य आसूचना के लिए सभी आसूचना एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों को स्थानीय जनता के साथ अच्छा नेटवर्क विकसित करना चाहिए।

➲ साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों का उपयोग सूचना एकत्र करने में अधिकाधिक होना चाहिए।

➡ 'डी' (D) अक्षर से तात्पर्य है डैशबोर्ड आधारित 'मुख्य निष्पादन संकेतक' (Key Performance Indicators : KPI) और 'प्रमुख परिणाम क्षेत्र' (Key Result Areas : KRA)।

➡ 'एच' (H) अक्षर 'प्रौद्योगिकी के दोहन' (Harnessing Technology) का द्योतक है।

➲ इसके तहत वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु 'अनमैंड एरियल व्हीकल (UAV), जीपीएस ट्रैकिंग, पीटी जेड कैमरा, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग, रडार, सैटेलाइट इमेज आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

➡ 'ए' (A) अक्षर से तात्पर्य है 'प्रत्येक थिएटर के लिए कार्ययोजना' (Action Plan for Each Theatre) से है।

➲ विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक साथ अनेक मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता है और प्रत्येक मोर्चे के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी होगी।

➲ इसके लिए अलग से अल्प अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि की रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है जिसके लक्ष्य तथा समय-सीमा स्पष्ट निर्धारित हों।

➡ समाधान रणनीति का अंतिम अक्षर 'एन' (N) 'वित्तपोषण तक पहुंच को रोकना' (No Access to Financing) का द्योतक है।

➲ वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने का सबसे आधारभूत मंत्र है- उनके वित्तपोषण तंत्र को समाप्त करना।

● वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु सरकारी प्रयास

➡ केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 118 बटालियन और 10 कोबरा (Cobra) बटालियन तैनात की गई हैं।

➡ गृह मंत्रालय द्वारा 'सुरक्षा संबंधित व्यय योजना' (Security Related Expenditure Scheme) 10 राज्यों के 106 जिलों में लागू की गई है।

➲ इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा उक्त राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्ययों हेतु वित्त वर्ष 2016-17 में 210 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

➡ मंत्रालय द्वारा 'विशेष आधारभूत संरचना योजना' के तहत 6 राज्यों के विशेष बलों को मजबूत करने के लिए 122.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सारांश

◆ वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु नई परिचालन रणनीति है– समाधान (SAMADHAN)।

◆ देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की संख्या–10

◆ उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले-चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

➡ 'फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन स्कीम' (Fortified Police Station Scheme) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों में 400 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण हेतु 624 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

➡ गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को हेलीकॉप्टर, अनमैंड एरियल व्हीकल (UAV) आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं।

➡ केंद्र सरकार द्वारा 8 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में सड़क व्यवस्था को सुधारने हेतु 'सड़क आवश्यकता योजना' (Road Requirement Plan : RRP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- ➲ इस योजना के तहत स्वीकृत 5422 किमी. में से 4290 किमी. सड़कों का निर्माण हो चुका है।

➡ केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, 2016 में 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क संपर्क परियोजना' को स्वीकृति प्रदान की गई।

- ➲ परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में 11725 करोड़ रुपये की लागत से 5412 किमी. सड़क एवं 126 पुलों का निर्माण किया जाना है।

➡ विगत दो वित्तीय वर्षों में वित्तीय समावेशन की दिशा में विशेष प्रयास कर वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों में 358 बैंक शाखाएं तथा 752 एटीएम (ATM) खोले गए।

- ➲ साथ ही इन जिलों में 1789 नए डाकघर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

➡ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है।

- ➲ वर्तमान में इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 में से 32 जिले आच्छादित हैं।

➡ 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (DDUGJY) के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के 5778 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

- ➲ शेष 1461 गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2017 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सारांश

- ◆ वर्तमान समय में देश के 10 राज्यों के 106 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं।
- ◆ इनमें आंध्र प्रदेश के 8, तेलंगाना के 8, बिहार के 22, छत्तीसगढ़ के 16, झारखंड के 21, मध्य प्रदेश का 1, महाराष्ट्र के 4, ओडिशा के 19, उत्तर प्रदेश के 3 और पश्चिम बंगाल के 4 जिले शामिल हैं।
- ◆ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित उत्तर प्रदेश के तीन जिले हैं- चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

सं. नीरज ओझा

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017

● आवश्यकता

इस्पात आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत में निर्माण, बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष एवं औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात के उपयोग का दायरा काफी व्यापक है। इस्पात सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखता है। इतने महत्वपूर्ण उद्योग में क्षमताओं का पर्याप्त दोहन नहीं होने और नीतिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में नई इस्पात नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में इस्पात उद्योग को और दक्ष एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (National Steel Policy, 2017) संकल्पित की गई। इस नई नीति को 3 मई, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई।

● विजन

➡ एक ऐसे इस्पात उद्योग का निर्माण करना जो प्रौद्योगिकीय दृष्टि से विकसित हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

● मिशन

➡ इस्पात निर्माताओं को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।

➡ भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

➡ इस्पात उद्योग के आगतों (लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस) की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना।

➡ विदेशों में कच्ची सामग्री की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश को सुविधाजनक बनाना।

➡ घरेलू इस्पात मांग को बढ़ाना।

● उद्देश्य

(i) वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना।

(ii) भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को मौजूदा 60 किलोग्राम से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 160 किलोग्राम तक करना।

(iii) भारत को वर्ष 2030-31 तक उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना।

➡ नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास भी शामिल किया गया है जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके।

● महत्वपूर्ण बिंदु

➡ विगत कुछ वर्षों में भारत ने इस्पात के क्षेत्र में तीव्र विकास किया है। वर्ष 2016-17 में बिक्री के लिए 100 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया गया।

➲ इस्पात नीति, 2017 के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात निर्माण करने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

➲ इस नीति के अनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग में वर्ष 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।

➲ इस्पात नीति, 2017 में बुनियादी ढांचा, वाहन एवं आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

➲ इस्पात के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) में मौजूद संभावनाओं को मान्यता दी गई है, साथ ही इस क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है।

➲ इस्पात मंत्रालय नीतिगत उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर लौह अयस्क, कोकिंग कोल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे इस्पात उद्योग का तीव्र विकास संभव होगा।

➲ नई राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 लागू होने से देश में स्टील के उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही स्टील की घरेलू मांग को पूरा किया जा सकेगा।

● भारतीय स्टील उद्योग से संबंधित तथ्य

➡ अंतरराष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम (ISSF) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत, जापान को पीछे छोड़कर विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।

➲ इस दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम स्थान है।

➲ वर्ष 2016 में भारत का स्टील उत्पादन बढ़कर 3.32 मिलियन टन तक पहुंच गया।

➲ इसमें वर्ष 2015 के स्टील उत्पादन (3.0 मिलियन टन) की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

➡ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस्पात उद्योग का योगदान 2 प्रतिशत है।

➲ वर्तमान समय में इस्पात उद्योग 5 लाख प्रत्यक्ष एवं 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।

➲ भारत में स्टील की प्रति व्यक्ति खपत 60 किलोग्राम है जो विश्व में औसत प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 208 किलोग्राम से काफी कम है।

सारांश

◆ नई राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017, 3 मई, 2017 को स्वीकृत।

◆ इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मिशन।

◆ वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य।

◆ बुनियादी ढांचे में इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर।

◆ इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को मौजूदा 60 किग्रा. से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 160 किग्रा. तक करने का लक्ष्य।

◆ वर्ष 2016 में स्टील उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर।

सं. प्रभात सिंह

जैविक कृषि उत्पादों का अप्रतिबंधित निर्यात

● जैविक खेती

जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खर-पतवारनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें हरी खाद, कम्पोस्ट, जैव-नाशियों (Bio-Pesticides) आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे किसान को भी अधिक लाभ प्राप्त होता है।

भारत में विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों के कारण विभिन्न किस्मों के जैविक उत्पादों के उत्पादन की बृहद क्षमता उपलब्ध है। देश के कई भागों में विरासत में मिली जैविक खेती की परंपरा एक अतिरिक्त सुअवसर है। निर्यात बाजार में जैव उत्पादों की मांग में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ स्वदेशी बाजार में भी इन उत्पादों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही है जो जैविक उत्पादकों के लिए एक आशाजनक संकेत है।

● जैविक कृषि उत्पादों का अप्रतिबंधित निर्यात

➡ 31 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा 'विशिष्ट जैविक उत्पादों' पर सभी मात्रात्मक सीमाओं को हटाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

➲ समिति द्वारा सभी जैव कृषि और जैव प्रसंस्कृत उत्पादों के अप्रतिबंधित निर्यात (Unrestricted Export) की अनुमति प्रदान की गई, भले ही उनके मूल उत्पाद (गैर-जैविक) के निर्यात पर वर्तमान अथवा भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध/निषेध क्यों न हो।

➲ देश में जैविक दालों एवं मसूर की भारी कमी को देखते हुए इनके निर्यात पर मात्रात्मक सीमा को बनाए रखा गया है। किंतु, इस सीमा को वर्तमान के 10,000 मीट्रिक टन (MT) प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर दिया गया है।

➡ गेहूं, चीनी, गैर-बासमती चावल एवं जैविक चीनी पर मात्रात्मक सीमा हटने और जैविक दालों की निर्यात सीमा बढ़ाए जाने से किसानों की आय दोगुना करने संबंधी केंद्र सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

➲ इससे कृषि की निवेश लागत घटेगी एवं जैविक कृषि उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य (Premium Price) प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक किसान जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

➡ स्मरणीय है कि निर्यात होने वाले सभी जैविक उत्पाद 'राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम' (National Programme for Organic Production : NPOP) के तहत 'कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority : APEDA) द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं।

● भारत में जैविक कृषि उत्पादन एवं निर्यात

➡ भारत द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रमाणित जैविक उत्पादों का लगभग 1.35 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया गया।

➲ इन जैविक उत्पादों में शामिल थे–गन्ना, तिलहन, अनाज एवं मोटे अनाज, कपास, दालें, औषधीय पौधे, मसाले, मेवे, सब्जियां, चाय, कॉफी आदि।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 263687 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका कुल मूल्य 298 मिलियन डॉलर था।

➲ जैविक उत्पाद निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी तिलहन (50%) की रही। इसके बाद क्रमशः प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद (25%), अनाज एवं मोटे अनाज (17%), चाय (2%), दालें (2%), मसाले (1%), मेवे (1%) आदि का हिस्सा रहा।

● अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ भारत में कुल 5.71 मिलियन हेक्टेयर जैव प्रमाणित क्षेत्र हैं जिसमें से 26 प्रतिशत (1.49 मिलियन हेक्टेयर) पर कृषि की जाती है जबकि शेष पर वन हैं जहां से वनोत्पाद संग्रहीत किए जाते हैं।

➡ सभी राज्यों में जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) के अधीन सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है जिसके बाद हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान का स्थान है।

➡ जनवरी, 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है।

➲ अपने संपूर्ण कृषि उत्पाद को जैविक बनाने हेतु कानून (मिजोरम जैविक अधिनियम, 2004) बनाने वाला देश का प्रथम राज्य मिजोरम है।

➲ बृहद् स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश 'क्यूबा' है।

सारांश

◆ विशिष्ट जैविक उत्पादों पर सभी मात्रात्मक सीमाओं को हटाने की स्वीकृति।

◆ जैविक दालें एवं मसूर के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा की व्यवस्था अभी भी लागू।

◆ सिक्किम : भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य

सार्वजनिक मामले सूचकांक, 2017

● सार्वजनिक मामले केंद्र

➡ देश में शासन प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में स्थापित 'सार्वजनिक मामले केंद्र' (Public Affairs Centre : PAC) एक गैर-लाभकारी (Not-for Profit) थिंक टैंक (Think Tank) है।

➲ देश में सुशासन की मांग के लिए लोगों को लामबंद करने हेतु गठित इस केंद्र को वास्तव में सिविल सोसाइटी के नेतृत्व वाली पहली सांस्थानिक पहल के रूप में देखा जा सकता है।

➲ बंगलुरू स्थित यह केंद्र देश के उन 9 प्रतिष्ठित विचार मंचों में से एक है जो कनाडा स्थित 'आईडीआरसी' (IDRC : International Development Research Centre) के नेतृत्व वाले 'थिंक टैंक इनिशिएटिव कंसोर्टियम' का अंग हैं।

➲ साथ ही यह दक्षिण एशिया के उन 24 प्रमुख विचार-मंचों में से एक है जिन्हें इटली स्थित 'अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रशासन केंद्र' (International Centre for Climate Governance : ICCG) के थिंक टैंक मानचित्र पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

● सूचकांक

➡ वर्ष 2016 में 'सार्वजनिक मामले केंद्र' ने अपने नए उत्पाद के रूप में 'सार्वजनिक मामले सूचकांक' (Public Affairs Index : PAI) को लांच किया था।

➲ यह देश के राज्यों में शासन (Governance) की गुणवत्ता एवं उसके स्तर के मापन का एक अद्वितीय सांख्यिकीय साधन है।

➲ चूंकि यह सूचकांक पूर्णत: केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आंकड़ों पर ही आधारित है, इसलिए इसे एक विश्वसनीय सूचकांक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

➲ इस सूचकांक में राज्यों को उनकी शासन प्रणाली की गुणवत्ता के आधार पर स्कोर एवं रैंक प्रदान की जाती है।

➲ वर्ष 2016 में PAI के मापन हेतु के 10 व्यापक विषयों (Broad Themes), 25 फोकस विषयों (Focus Subjects) तथा 68 व्यक्तिगत संकेतकों (Individual Indicators) को आधार बनाया गया था।

● नवीनतम संस्करण

➡ 12 मई, 2017 को सार्वजनिक मामले केंद्र द्वारा सार्वजनिक मामले सूचकांक, 2017 (PAI, 2017) जारी किया गया।

➲ यह इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है।

➲ द्वितीय संस्करण वर्ष 2016 में जारी प्रथम संस्करण की तुलना में अधिक विस्तृत है और इसमें शासन प्रणाली के स्तर के मूल्यांकन हेतु 10 विषयों, 26 फोकस विषयों तथा 82 संकेतकों का सहारा लिया गया है।

➲ नवीनतम संस्करण में तेलंगाना के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है जबकि पिछले वर्ष डाटा की अनुपलब्धता के कारण इसे शामिल नहीं किया जा सका था।

➲ इस वर्ष की रिपोर्ट में 'असमानता' (Inequality) पर एक नए अध्ययन को भी शामिल किया गया है।

➡ PAI, 2017 में राज्यों को रैंक प्रदान करने के लिए उन्हें दो श्रेणियों यथा छोटे राज्य (Small States) एवं बड़े राज्य (Large States) में विभाजित किया गया है।

➲ यह वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया गया है।

➲ 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को बड़े राज्य तथा 2 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य को छोटे राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है।

● परिणाम

समग्र रैंकिंग, 2017 (शीर्ष 10 राज्य)

बड़े राज्य			छोटे राज्य		
रैंक	**राज्य**	**स्कोर**	**रैंक**	**राज्य**	**स्कोर**
1.	केरल	0.551	1.	हिमाचल प्रदेश	0.535
2.	तमिलनाडु	0.543	2.	गोवा	0.492
3.	गुजरात	0.536	3.	मिजोरम	0.489
4.	कर्नाटक	0.531	4.	सिक्किम	0.486
5.	महाराष्ट्र	0.512	5.	उत्तराखंड	0.479
6.	पंजाब	0.497	6.	नगालैंड	0.460
7.	राजस्थान	0.473	7.	त्रिपुरा	0.457
8.	छत्तीसगढ़	0.468	8.	मणिपुर	0.446
9.	आंध्र प्रदेश	0.467	9.	दिल्ली	0.443
10.	हरियाणा	0.464	10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.440

सारांश

◆ सार्वजनिक मामले केंद्र-PAC, बंगलुरू द्वारा 12 मई, 2017 को सार्वजनिक मामले सूचकांक, 2017 जारी।

◆ सूचकांक, शासन (Governance) की गुणवत्ता एवं उसके स्तर के मापन से संबंधित है।

◆ समग्र रैंकिंग में बड़े राज्यों में केरल व छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान।

◆ **उत्तर प्रदेश :**

▼ समग्र रैंकिंग में बड़े राज्यों में 14वां स्थान (0.441 स्कोर)।

▼ पारदर्शिता व जवाबदेही में चौथी रैंक।

▼ मानव विकास को सहयोग में अंतिम स्थान।

10 व्यापक विषयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त राज्य

बड़े राज्य			छोटे राज्य		
विषय	**राज्य**	**स्कोर**	**विषय**	**राज्य**	**स्कोर**
अनिवार्य अवसंरचना	पंजाब	0.724	अनिवार्य अवसंरचना	गोवा	0.757
मानव विकास को सहयोग	केरल	0.672	मानव विकास को सहयोग	मिजोरम	0.622
सामाजिक सुरक्षा	केरल	0.568	सामाजिक सुरक्षा	जम्मू एवं कश्मीर	0.624
महिलाएं एवं बच्चे	केरल	0.683	महिलाएं एवं बच्चे	नगालैंड	0.698
अपराध, कानून एवं व्यवस्था	तमिलनाडु	0.434	अपराध, कानून एवं व्यवस्था	नगालैंड	0.470
न्याय का अंतरण	तमिलनाडु	0.725	न्याय का अंतरण	त्रिपुरा	0.779
पर्यावरण	तमिलनाडु	0.829	पर्यावरण	अरुणाचल प्रदेश	0.832
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	हरियाणा	0.707	पारदर्शिता एवं जवाबदेही	हिमाचल प्रदेश	0.604
राजकोषीय प्रबंधन	तेलंगाना	0.654	राजकोषीय प्रबंधन	गोवा	0.577
आर्थिक स्वतंत्रता	गुजरात	0.828	आर्थिक स्वतंत्रता	दिल्ली	0.199

● उत्तर प्रदेश की स्थिति

➡ PAI, 2017 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में 0.441 के स्कोर के साथ 14वां स्थान प्राप्त हुआ है।

➲ जबकि वर्ष 2016 में यह 0.461 के स्कोर के साथ 12वें स्थान पर था।

➲ पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छी रैंक (चौथी रैंक) प्राप्त हुई है, जबकि मानव विकास को सहयोग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को 18 बड़े राज्यों में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017

● खनन नीति को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई, 2017 को सुशासन (Good Governance) एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूलमंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी खनन नीति (उत्तर प्रदेश खनन नीति, 2017) के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार की इस खनन नीति के प्रमुख मंत्र हैं–

(A) पारदर्शिता, (B) कानून का राज, (C) समता, (D) प्रभावशीलता, (E) आम सहमति, (F) उत्तरदायी एवं (G) भागीदारी।

● लक्ष्य

नीति के तहत उपर्युक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है :–

(a) खनिजों के विषय में जागरूकता (Awareness) को बढ़ाना

(b) सर्व सामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच (Accesibility) को सुनिश्चित करना

(c) सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता (Availability) में वृद्धि करना

(d) खनिजों के मूल्य को जन साधारण के सामर्थ्य के अनुरूप (Affordability) बनाए रखना तथा

(e) उपर्युक्त आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता (Acceptability) को बढ़ाना।

● खनन नीति के उद्देश्य

(i) सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास (Sustainable Socio-Economic Development) की गति को तीव्र करना।

(ii) खनिजों का संरक्षण (Mineral Conservation) करना।

(iii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology) का संतुलन बनाए रखना।

(iv) खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.85 प्रतिशत को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3 प्रतिशत करना।

(v) अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण

(vi) खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना।

(vii) खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।

(viii) खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना।

(ix) खनिज संबंधी सूचना/आंकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना।

(x) इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना।

(xi) तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना।

(xii) ई-टेंडरिंग/ई-नीलामी/ई-बिडिंग प्रणाली के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।

(xiii) खनन से प्रभावित व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

● रणनीति

➡ खनिजों के व्यावसायिक दोहन हेतु उनके अन्वेषण में तीव्रता लाना।

➡ निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

➡ खनन प्रशासन की प्रक्रिया को सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना। इसके अंतर्गत खनन पट्टों/अनुज्ञा-पत्रों को ई-टेंडर/ई-नीलामी/ई-बिडिंग के माध्यम से दिया जाएगा।

➡ खनिज आधारित सूचना के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना करना जिससे उद्यमियों को आवश्यक सूचना प्रदान की जा सके।

➡ अवस्थापना एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।

➡ अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल तथा विभागीय सुरक्षा बल का गठन।

➡ खनन संबंधी अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन।

➡ खनिज क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

➡ वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पर खनिजों का GVA में अंश गत पांच वर्षों में 3.1 प्रतिशत से घटकर 2.25 प्रतिशत रह गया है, वहीं राज्य के स्वयं के अर्जित संसाधनों में खनिजों से आय का अंश 1.24 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया है।

➡ प्रस्तावित नीति सुधार से राज्य में यह अंश अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाना संभव हो सकेगा।

सारांश

◆ 30 मई, 2017 को उत्तर प्रदेश खनन नीति के प्रख्यापन को मंजूरी।

◆ लक्ष्य : अगले 5 वर्षों में खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य के कुल राजस्व में अंश को वर्तमान 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना।

खनिज क्षेत्र के भारत के GVA तथा उत्तर प्रदेश के GSVA में योगदान का तुलनात्मक विवरण (करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारत में खनिज का GVA	चालू कीमतों पर कुल GVA	भारत के GVA में खनन क्षेत्र का हिस्सा % में	उत्तर प्रदेश में खनन का GVA	चालू कीमतों पर उ.प्र. का कुल GVA	खनन क्षेत्र का उ.प्र. के GVA में % हिस्सा	उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के अर्जित संसाधन	राज्य की खनन रॉयल्टी	राज्य के स्वयं अर्जित संसाधन में रॉयल्टी आय का हिस्सा % में
2012-13	285776	9205315	3.10	6888	777716	0.89	58098.36	722.17	1.24
2013-14	295716	10366266	2.85	8689	885939	0.98	66583.22	912.23	1.37
2014-15	313844	11470415	2.74	9015	973052	0.93	74272.98	1029.28	1.39
2015-16	296041	12451938	2.38	10115	1062374	0.95	81106.29	1222.22	1.51
2016-17	309178	13750786	2.25	11295	1212440	0.93	85865.41	1547.25	1.80
CAGR	1.99%	10.55%	-	13.16%	11.74%	-	10.26%	20.98%	–

नोट : CAGR - औसत वार्षिक वृद्धि दर

प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज

मुख्य खनिज	जिला
1. कोयला	सोनभद्र (बीना, ककड़ी, खड़िया, कृष्णशिला)
2. लाइमस्टोन	सोनभद्र (बिल्ली, मारकुंडी, कजरहट, भलुआ, गुरमा)
उपखनिज	
(i) सिलिका सैंड	इलाहाबाद (बारा, शंकरगढ़) , चित्रकूट (बरगढ़)
(ii) डायस्पोर (पायरोफिलाइट)	ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
(iii) ग्रेनाइट डायमेन्शनल स्टोन	ललितपुर
(iv) ग्रेनाइट-खंडा/गिट्टी	ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
(v) डोलोस्टोन-खंडा/गिट्टी	सोनभद्र
(vi) सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा/गिट्टी	सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा
(vii) बालू, बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में	सहारनपुर, बिजनौर
(viii) बालू/मोरम	जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र
(ix) साधारण बालू	प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभरहित जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास की स्थापना की गई है जो खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्यवाही को अंजाम देगा।
- मुख्य खनिज एवं उप-खनिज के पट्टाधारकों से खनिजों के निकासी या देय रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जनपदों में बनाए गए न्यास में जमा किया जाएगा।
- मुख्य खनिज के संदर्भ में रॉयल्टी का प्रतिशत जो जिला खनिज फाउंडेशन में जमा किया जाएगा, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तथा उपखनिजों के संदर्भ में इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास में जमा धनराशि का उपयोग 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (PMKKKY) में भी किया जाएगा।
- खनिजों के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए तकनीकी व्यय की पूर्ति हेतु खनन पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रॉयल्टी की एक प्रतिशत धनराशि अधिभार (Cess) के रूप में वसूल किए जाने का भी प्रावधान है।

सं. शिव शंकर कुमार त्रिवारी

दाबित भारी जल रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी

● 10 रिएक्टरों का निर्माण

➡ भारत में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने और विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को समाप्त करने की दृष्टि से नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन है।

➲ इसके लिए भारत के घरेलू नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को तेज गति प्रदान करने और देश के नाभिकीय उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

➲ इसी आवश्यकता के दृष्टिगत 17 मई, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के स्वदेशी 'दाबित भारी जल रिएक्टर' (Pressurized Heavy Water Reactors : PHWR) की 10 नई इकाइयों(प्रत्येक की क्षमता 700 MW) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

➲ इस नए संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 7000 मेगावॉट होगी।

➲ इन 10 रिएक्टरों समेत वर्तमान में निर्माणाधीन अन्य रिएक्टरों का परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात भारत की कुल स्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 20,480 MW हो जाएगी।

➡ भारत के नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी तरह की इस पहली परियोजना के तहत 10 नए परमाणु रिएक्टरों का निर्माण पूर्णतया स्वदेशी पहल के तौर पर 'फ्लीट मोड' (Fleet Mode) में किया जाएगा।

➡ ये रिएक्टर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा करने वाले अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त भारत के 700 मेगावॉट 'दाबित भारी जल रिएक्टर' (PHWR) फ्लीट के भाग होंगे।

➲ इन 10 रिएक्टरों की स्थापना एनपीसीआईएल (NPCIL : Nuclear Power Corporation of India Limited) द्वारा की जाएगी।

➲ 10 दाबित भारी जल रिएक्टरों के निर्माण की यह परियोजना भारत के नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में से एक होगी।

● लाभ

➡ परियोजना से देश के घरेलू उद्योगों को 70,000 करोड़ रुपये के विनिर्माण ऑर्डर प्राप्त होने का अनुमान है।

➲ साथ ही परियोजना से 33400 से भी अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।

➲ परियोजना से धारणीय विकास, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी।

● नाभिकीय ऊर्जा : अद्यतन स्थिति

➡ वर्तमान में भारत में कार्यशील नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या 22 है जिनकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावॉट है।

➡ हाल ही में केंद्र सरकार ने गोरखपुर (हरियाणा) एवं माही, बांसवाड़ा (राजस्थान) दोनों में 700 मेगावॉट क्षमता के 4 रिएक्टरों की स्थापना को सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।

➲ इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में हरिपुर (प. बंगाल) में 1000 मेगावॉट क्षमता के 6 रिएक्टरों के निर्माण को भी सैद्धांतिक अनुमति दी गई है।

● विद्युत की स्थापित क्षमता, मांग एवं आपूर्ति

➡ 31 मई, 2017 तक भारत में कुल विद्युत स्थापित क्षमता 3,30,261 मेगावॉट थी।

➲ इसमें शामिल हैं- ताप विद्युत 221626 मेगावॉट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 57260 मेगावॉट, जल विद्युत 44594 मेगावॉट और नाभिकीय ऊर्जा 6780 मेगावॉट।

➡ वर्ष 2016-17 में भारत में विद्युत की मांग 1142929 मिलियन यूनिट थी जबकि विद्युत की उपलब्धता 1135334 मिलियन यूनिट थी।

➲ इस प्रकार विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में अंतराल 7595 मिलियन यूनिट था।

➡ भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप मई, 2017 (वर्ष 2017-18 अनंतिम) तक विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का अंतराल कम होकर 1265 मिलियन यूनिट हो गया।

➡ मई, 2017 (वर्ष 2017-18 अनंतिम) तक भारत में विद्युत की मांग 208038 मिलियन यूनिट थी जबकि विद्युत की उपलब्धता 206773 मिलियन यूनिट थी।

सारांश

◆ 17 मई, 2017 को स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) की 10 नई इकाइयों के निर्माण को स्वीकृति।

◆ संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 7000 मेगावॉट।

◆ वर्तमान में भारत में स्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता : 6780 MW

◆ विद्युत आपूर्ति के स्रोत, (भारत में) – ताप विद्युत > नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत > जल विद्युत > नाभिकीय ऊर्जा।

अग्नि-II मिसाइल का परीक्षण

● अग्नि मिसाइल

अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर्महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक शृंखला है। अग्नि शृंखला की सभी मिसाइलें सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। अग्नि-I, अग्नि-II, अग्नि-III और अग्नि-IV को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तैनात किया जा चुका है। अग्नि-V परीक्षण के चरण में जबकि अग्नि-VI विकास के चरण में है।

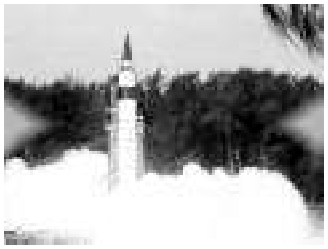

● अग्नि मिसाइलों का विकास

➡ अग्नि मिसाइल शृंखला के विकास का मुख्य उद्देश्य सैन्य उपयोग के लिए 'पुनर्प्रवेश यान तकनीक' (Re-entry Vehicle Technology) का परीक्षण करना था।

➡ 'तकनीकी प्रदर्शक परियोजना' (Technology Demonstrator Project) के रूप में अग्नि मिसाइल का तीन बार 22 मई, 1989; 29 मई, 1992 और 19 फरवरी, 1994 को उड़ान परीक्षण किया।

➡ अग्नि मिसाइल के तकनीकी प्रदर्शक मॉडल के प्रथम चरण में ठोस ईंधन एसएलवी-3 (SLV-3) और द्वितीय चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया।

- ➲ अग्नि मिसाइल के इस ठोस एवं तरल मिश्रित चरण के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तय मानकों पर खरा न उतरने और अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण इस मिसाइल का विकास रोक दिया गया।
- ➲ वर्ष 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अग्नि मिसाइल का विकास पुनः प्रारंभ किया गया।
- ➲ अग्नि मिसाइल शृंखला के तहत विकसित मिसाइलों में शामिल हैं- अग्नि-I (700 किमी.), अग्नि-II (2000 किमी.), अग्नि-III (3000 किमी.), अग्नि IV (4000 किमी.) और अग्नि-V (5000 किमी.)।

● अग्नि-II का प्रक्षेपण

➡ 4 मई, 2017 को ओडिशा के 'अब्दुल कलाम द्वीप' (ह्वीलर द्वीप) से नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-II का परीक्षण किया गया।

- ➲ स्वदेश निर्मित अग्नि-II मिसाइल का यह परीक्षण मोबाइल लांचर से 'एकीकृत परीक्षण रेंज' (ITR) के प्रक्षेपण परिसर-4 से किया गया।
- ➲ यह परीक्षण भारतीय थल सेना के 'सामरिक बल कमान' (SFC) ने प्रयोक्ता प्रशिक्षण के तहत 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) के वैज्ञानिकों के तकनीकी पर्यवेक्षण में किया।
- ➲ अग्नि-II, 20 मीटर लंबी, 17 टन वजनी और ठोस प्रणोदक चालित द्विचरणीय मिसाइल है।
- ➲ यह मिसाइल 1000 किग्रा. युद्धशीर्ष के साथ 2000 किमी. से अधिक दूरी तक मार कर सकती है।
- ➲ उल्लेखनीय है कि अग्नि-II का पहला परीक्षण 11 अप्रैल, 1999 को ह्वीलर द्वीप (वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप) से किया गया था।
- ➲ अग्नि-II मिसाइल को सशस्त्र सेना में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था।

● अद्यतन स्थिति

➡ 27 अप्रैल, 2017 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-III मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय सेना के 'सामरिक बल कमान' द्वारा डीआरडीओ (DRDO) के सहयोग से किया गया।

- ➲ अग्नि-III मिसाइल 1.5 टन वजनी पारंपरिक और परमाणु विस्फोटकों के साथ 3000 किमी. से अधिक दूरी तक मार कर सकती है।
- ➲ द्विस्तरीय ठोस प्रणोदक इंजन युक्त अग्नि-III मिसाइल की लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन लगभग 22 टन है।
- ➲ जून, 2011 में अग्नि-III मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है।
- ➲ 26 दिसंबर, 2016 को अग्नि-V मिसाइल का अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया।
- ➲ अग्नि-V एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी आरंभिक मारक क्षमता 5000 किमी. है, जिसे 8000 से 10000 किमी. तक बढ़ाया जा सकता है।
- ➲ 2 जनवरी, 2017 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सेना के सामरिक बल कमान द्वारा अग्नि-IV मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
- ➲ अग्नि-IV मिसाइल 20 मीटर लंबी, 17 टन वजनी और ठोस ईंधन संचालित द्विचरणीय मिसाइल है।
- ➲ यह मिसाइल एक टन नाभिकीय युद्धशीर्ष के साथ 4000 किमी. तक मार कर सकती है।

➡ 22 नवंबर, 2016 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइल का सेना के सामरिक बल कमान द्वारा सफल परीक्षण किया गया।

- ➲ ठोस ईंधन संचालित एकल चरणीय अग्नि-I मिसाइल की मारक क्षमता 700 किमी. है।
- ➲ अग्नि-I मिसाइल 15 मीटर लंबी एवं 12 टन वजनी है जो 1 टन से अधिक युद्धशीर्ष ले जा सकती है।

सारांश

- ◆ अग्नि-II मिसाइल का नवीनतम परीक्षण 4 मई, 2017 को।
- ◆ प्रक्षेपण स्थल : अब्दुल कलाम द्वीप (ओडिशा)।
- ◆ अग्नि-II की मारक क्षमता : लगभग 2000 किमी.।
- ◆ अग्नि-II की सशस्त्र सेनाओं में तैनाती : वर्ष 2004 में।

ई-विन परियोजना

● भूमिका

मई, 2017 में पांच देशों नामत: फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। प्रतिनिधिमंडल की इस भारत यात्रा का उद्देश्य भारत की स्वदेश में विकसित ई-विन परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करना था। इस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर ई-विन परियोजना के भारत में कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही इस संबंध में भी परिचर्चा की कि किस प्रकार वे अपने देश में इस परियोजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं।

● ई-विन परियोजना

➡ ई-विन (e-VIN: Electronic Vaccine Intelligence Network) भारत की स्वदेश में विकसित तकनीक प्रणाली है जो टीका भंडारों का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन (Cold Chain) के तापमान की निगरानी करती है।

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में कोल्ड चेन प्रणाली का अहम योगदान है।
- कोल्ड चेन के जरिए ही विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों, महिलाओं आदि को दिए जाने वाले टीके सुरक्षित रखे जाते हैं।

➡ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने 'सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम' (Universal Immunisation Programme : UIP) के तहत 12 राज्यों में ई-विन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- अक्टूबर, 2015 में प्रारंभ हुई यह परियोजना असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 371 जिलों में लागू की गई है।
- ई-विन परियोजना का लक्ष्य उपर्युक्त राज्यों में टीका भंडार एवं वितरण और सभी 'कोल्ड चेन प्वॉइंट्स' (Cold Chain Points) में भंडारण तापमान पर वास्तविक समय जानकारी प्रदान कर 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' की सहायता करना है।

➡ 'ई-विन' का भारत में कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme : UNDP) द्वारा 'गावि-द वैक्सीन एलायंस (GAVI-The Vaccine Alliance) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है।

● ई-विन की आवश्यकता

➡ भारत में 65 प्रतिशत बच्चों का पूर्णतया टीकाकरण किया जा चुका है जबकि भारत सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 27 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करना है।

- यद्यपि भारत में पोलियो के उन्मूलन और नवजात टिटनेस (Neonatal Tetanus) को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है फिर भी देश के 10 मिलियन बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है।
- देश में बच्चों के कम टीकाकरण के कारणों में शामिल हैं- अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण टीकों की कमी, टीका भंडार दृश्यता की कमी, खराब वितरण योजना एवं अनुपयुक्त भंडारण की स्थिति समेत मौजूदा आपूर्ति शृंखला की कमजोरियां।
- शत-प्रतिशत टीकाकरण के अपने लक्ष्य को साकार करने हेतु भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अपर्याप्त टीका आपूर्ति और टीका भंडारण स्थलों की तापमान निगरानी प्रणाली का समाधान करना।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 'राष्ट्रीय टीका संचालन प्रबंधन प्रणाली' (National Vaccine Logistic Management System) की आवश्यकता थी, जो सभी 'कोल्ड चेन प्वॉइंट्स पर वास्तविक समय टीका भंडार की दृश्यता प्रदान करती हो।
- इसी आवश्यकता के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'ई-विन' परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

● निष्कर्ष

ई-विन परियोजना के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भारत न केवल अपने शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर सकता है बल्कि अन्य देशों को भी ई-विन परियोजना से लाभान्वित कर सकता है। भारत की यात्रा पर आए पांच देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनकी क्षमताओं को मजबूत बनाने और उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने हेतु उन्हें सहयोग एवं समर्थन देने के लिए तैयार है।

सारांश

◆ ई-विन का उद्देश्य : टीका भंडारों का डिजिटलीकरण व कोल्ड चेन प्रणाली की निगरानी।

◆ सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम (U.I.P.) के तहत ई-विन परियोजना का कार्यान्वयन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।

◆ UNDP द्वारा, गावि-द वैक्सीन एलायंस की वित्तीय सहायता से, कार्यान्वयन।

◆ प्रतिवर्ष 27 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करने का सरकार का लक्ष्य।

भूपेन हजारिका सेतु : देश का सबसे लंबा नदी सेतु

● भूमिका

भारत का उत्तर-पूर्व क्षेत्र प्राकृतिक संपदा और वैभवपूर्ण संस्कृति से परिपूर्ण है। पर्यटन के नाम पर यहां सब कुछ है, जैसे- प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातियों की अलग-अलग लोक संस्कृति, वेशभूषा, खान-पान तथा पौराणिक स्थल इत्यादि। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी यह क्षेत्र विकास में पीछे छूट गया है। इसका प्रमुख कारण यातायात की सुविधाओं का अभाव है। पहाड़ी क्षेत्र की अधिकता, समतल मैदानों का अभाव तथा पहाड़ी नदियां इस क्षेत्र में रेलमार्ग, सड़क मार्ग तथा नदी जलमार्ग के विकास में एक बड़ी बाधा हैं। इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु परिवहन तंत्र में सुधार करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है-**भूपेन हजारिका सेतु**।

● भूपेन हजारिका सेतु राष्ट्र को समर्पित

➡ 26 मई, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने असम में भूपेन हजारिका सेतु (ढोला-सदिया सेतु) राष्ट्र को समर्पित किया।

➲ इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर किया गया है।

➲ नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर वर्ष 2011 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था (सेतु के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2009 में प्रदान की गई थी)।

● देश का सबसे लंबा सेतु

➡ 9.15 किमी. लंबा भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु है।

➲ यह सेतु बांद्रा-वर्ली सी लिंक (5.6 किमी.) से 3.55 किमी. लंबा है, जो अब देश का दूसरा सबसे लंबा सेतु हो गया है।

➲ भूपेन हजारिका सेतु के निर्माण से असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर स्थित रुपाई और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर स्थित मेका/रोइंग के मध्य यात्रा की दूरी 165 किमी. कम हो गई है जिससे यात्रा में 5 घंटे तक कम समय लगेगा।

➲ इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 10 लाख रुपये मूल्य तक के ईंधन की बचत का भी अनुमान व्यक्त किया गया है।

● सेतु की संरचना

➡ भूपेन हजारिका सेतु एक तीन लेन का बीम सेतु है। सेतु का निर्माण उच्च भूकंप संभावित क्षेत्र (सिज्मिक जोन-5) में किया गया है।

➲ भूकंप के संभावित खतरे को देखते हुए इसके निर्माण में भूकंपरोधी प्रणाली का उपयोग किया गया है।

➲ सेतु की भारत-चीन सीमा से निकटता (हवाई दूरी-100 किमी. से भी कम) को देखते हुए इसके निर्माण में सैन्य उपयोगिता को भी ध्यान से रखा गया है।

➲ इसकी भार वहन क्षमता 60 टन से अधिक है जिससे सैन्य साजो-सामान जैसे-टैंक आदि आसानी से इस पर से गुजर सकेंगे।

● सेतु की अन्य विशेषताएं

➡ सेतु का नाम असम के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार एवं कवि भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है।

➡ एसएआरडीपी-एनई (SARDP-NE : Special Accelerated Road Development Programme for North East) योजना के अंतर्गत सेतु का निर्माण किया गया है।

➲ सेतु से जहां एक ओर संबंधित राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो गई है वहीं दूसरी ओर इसके निर्माण से इन राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

➲ अब ऊपरी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के मध्य 24×7 संपर्क सुनिश्चित हो गया है।

➲ सेतु पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सीमा व्यापार के साथ औद्योगिक निवेश में भी वृद्धि करेगा।

● निष्कर्ष

इस सेतु के निर्माण से पूर्व यहां ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने का एकमात्र साधन नाव ही था, उसमें भी केवल दिन के समय ही नदी को पार किया जा सकता था तथा वह भी बाढ़ के समय मुमकिन नहीं था। यहां के दूरस्थ इलाकों से संपर्क स्थापित करना एक कठिन कार्य था। सेतु के निर्माण से इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी। भारत-चीन सीमा के करीब होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत-चीन सीमा विवाद, चीन की विस्तारवादी नीति, चीन-पाकिस्तान संबंध आदि ऐसे कई कारक हैं जो इस क्षेत्र के सैन्य महत्व को इंगित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह सेतु केवल एक सेतु न होकर उत्तर-पूर्व के राज्यों की विकास की जीवन रेखा है तथा देश की एकता और अखंडता का परिचायक है।

सारांश

◆ 26 मई, 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा असम में ढोला-सदिया सेतु का उद्घाटन।

◆ सेतु का अन्य नाम-भूपेन हजारिका।

◆ सेतु की लंबाई 9.15 किमी.।

◆ यह देश का सबसे लंबा नदी सेतु है।

◆ सेतु ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर स्थित।

◆ सेतु ऊपरी असम एवं पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के मध्य 24 × 7 संपर्क को सुनिश्चित करेगा।

सं. गौरव श्रीवास्तव

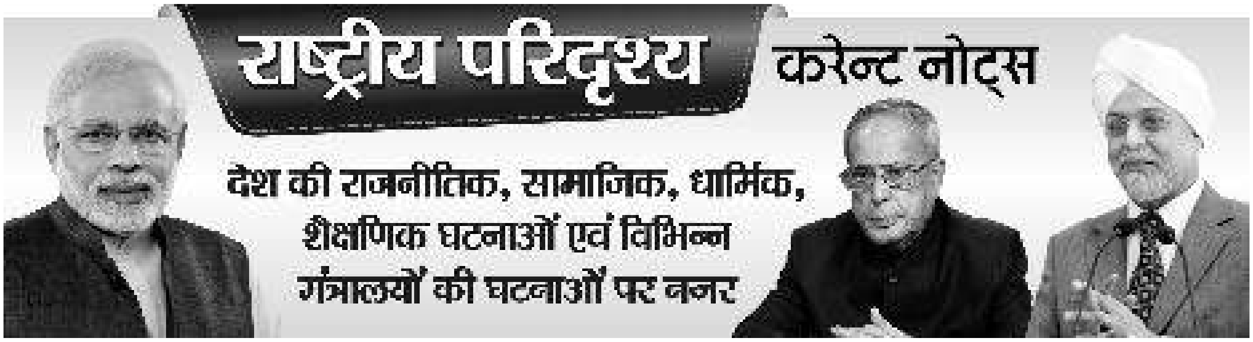
राष्ट्रीय परिदृश्य
करेन्ट नोट्स
देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक,
शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न
मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर

‘उड़ान’ योजना का शुभारंभ

उड़ान क्षेत्रीय उड्डयन बाजार विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है, जिससे देश में क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाया जा सकेगा। यह योजना जून, 2016 में जारी की गई ‘राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति’ (NCAP-2016) का एक प्रमुख घटक है। यह विश्व में अपने तरह की पहली योजना है जिसके तहत क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उड़ानें संचालित की जाएंगी।

➡ 27 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री ने ‘उड़े देश का आम नागरिक (Ude Desh ka Aam Nagarik : UDAN) नामक क्षेत्रीय संपर्क योजना को शिमला हवाई अड्डे से लांच किया। इसके तहत शिमला-दिल्ली मार्ग पर उड़ानें आरंभ हुईं।

- ➲ इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कडप्पा (आंध्र प्रदेश)-हैदराबाद तथा नांदेड़ (महाराष्ट्र)-हैदराबाद मार्ग पर उड़ानों के संचालन का शुभारंभ किया। नांदेड़-हैदराबाद तथा कडप्पा-हैदराबाद मार्गों के मध्य ट्रूजेट (Trujet) नामक एक क्षेत्रीय एयरलाइंस ने विमान सेवाएं आरंभ की हैं।

➡ इस योजना के सफल संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

- ➲ भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से इस योजना के तहत चयनित कुल 70 हवाई अड्डों में से पश्चिम क्षेत्र के 24 हवाई अड्डे, उत्तर भारत के 17, दक्षिण भारत के 11, पूर्वी भारत के 12 तथा पूर्वोत्तर भारत के 6 हवाई अड्डे शामिल हैं।

➡ इस योजना के तहत विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा का किराया अधिकतम 2500 रुपये होगा।

➡ साथ ही अलग-अलग दूरी एवं अवधि वाले मार्गों पर हवाई सफर का किराया समानुपातिक आधार पर तय किया जाएगा।

- ➲ उड़ान योजना में परिचालन हेतु हवाई अड्डों का चयन राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा।
- ➲ उड़ान योजना के तहत व्यवहार्यता अंतराल निधीकरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक क्षेत्रीय कोष (Regional Connectivity Fund : RCF) बनाया जाएगा।
- ➲ भागीदार राज्य सरकारें कोष में 20 प्रतिशत का योगदान देंगी जबकि केंद्रशासित प्रदेशों तथा पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान 10 प्रतिशत होगा।
- ➲ उड़ान योजना विमान सेवाओं से वंचित पड़े एवं कम प्रयोग होने वाले हवाई अड्डों से वहनीय विमानन सेवाएं उपलब्ध कराकर तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात करेगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालयों, ठोस एवं तरल कचरा निपटान प्रणालियों और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संकल्पना की गई है। इस मिशन के दो घटक-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हैं। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी वर्ष 2019 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी-फरवरी, 2017 में कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 का उद्देश्य शहरों और कस्बों में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी हासिल करना है जिससे लगभग 2.5 वर्ष पूर्व लांच किए गए स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव एवं प्रगति का आकलन किया जा सके।

➡ स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 देश के 434 शहरों में किया गया एक व्यापक स्वच्छता संबंधी सर्वेक्षण था।

- ➲ इस सर्वेक्षण को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर ‘क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India : QCI) द्वारा संचालित किया गया।

➡ 4 मई, 2017 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017’ के परिणाम जारी किए।

➡ इस सर्वेक्षण के अनुसार, इंदौर (मध्य प्रदेश) देश का सबसे स्वच्छ

शहर घोषित किया गया है।

- ➲ उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष (2016) के सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य का मैसुरू देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था जो कि वर्ष 2017 में पांचवें स्थान पर है।
- ➲ इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम 10 शहरों में इंदौर के बाद क्रमशः भोपाल (मध्य प्रदेश), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), सूरत (गुजरात), मैसुरू (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (दिल्ली), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तथा वड़ोदरा (गुजरात) शामिल हैं।
- ➲ स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश का गोंडा सबसे अस्वच्छ शहर (अंतिम 434वें स्थान पर) है, यद्यपि गत वर्ष धनबाद सबसे अस्वच्छ शहर (73 शहरों की सूची में) था।

➡ इस सूची में अंतिम पायदान के 10 प्रमुख शहरों में गोंडा के बाद क्रमशः भुसावल (महाराष्ट्र), बग्हा (बिहार), हरदोई (उत्तर प्रदेश), कटिहार (बिहार), बहराइच (उत्तर प्रदेश), मुक्तसर (पंजाब), अबोहर (पंजाब), शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

➡ शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में गुजरात के 12, मध्य प्रदेश के 11 और आंध्र प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं।

- ➲ स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 में उत्तर प्रदेश के कुल 62 शहर शामिल हैं।
- ➲ इस सूची में उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में वाराणसी 32वें, अलीगढ़ 145वें, झांसी 166वें, कानपुर 175वें, सहारनपुर 245वें, जौनपुर 246वें, इलाहाबाद 247वें, अयोध्या 252वें, आगरा 263वें और लखनऊ 269वें स्थान पर हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 मापदंड और प्रक्रिया

सर्वेक्षण हेतु स्वच्छता संबंधी पहलुओं के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित मापदंड और भार (Weightages) निम्नलिखित हैं–

(1) प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रित करने सहित ठोस कचरे का प्रबंधन, प्रक्रिया और निपटान, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति : 900 अंक (कुल 2000 अंकों का 45 प्रतिशत)।
(2) नागरिक प्रतिपुष्टि : 600 अंक (कुल 2000 अंकों का 30 प्रतिशत)।
(3) स्वतंत्र अवलोकन : 500 अंक (कुल 2000 अंकों का 25 प्रतिशत)।

सौनी योजना

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए वर्ष 2012 में 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई' (SAUNI) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नर्मदा नदी के बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों के 115 जलाशयों में वितरित करना है। इस अतिरिक्त जल को वितरित करने के लिए कुल 1126 किमी. लंबाई वाली चार लिंक पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाएगा तथा इस योजना से 10,22,589 एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होगा। वर्ष 2014 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौनी सिंचाई योजना के चरण-1 (लिंक-2) का उद्घाटन किया।

➡ 17 अप्रैल, 2017 को गुजरात के बोटाद (Botad) जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना' (Saurashtra Narmada Avtaran Irrigation Yojana : SAUNI) के चरण-1 (लिंक-2) पाइपलाइन नहर (Pipeline Canal) का उद्घाटन किया।

➡ साथ ही प्रधानमंत्री ने सौनी सिंचाई योजना चरण-2 (लिंक-2) का शिलान्यास भी किया।

- ➲ इस सिंचाई योजना के चरण-1 (लिंक-2) के पाइपलाइन की लंबाई लगभग 51.28 किमी. है जो लिंबडी-भोगावो-II (Limbdi Bhogavo-II) बांध को रायदी (Raidi) बांध से जोड़ती है।
- ➲ इस सिंचाई योजना के लिंक-2 पाइपलाइन नहर के माध्यम से बोटाद, भावनगर एवं अमरेली जिलों के 17 जलाशयों को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा।

➡ उल्लेखनीय है कि 30 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनोसरा (Sanosara), गुजरात में सौनी सिंचाई योजना के चरण-1 (लिंक-1) पाइपलाइन का उद्घाटन किया था।

➡ सौनी योजना की चार लिंक पाइपलाइनें निम्नलिखित हैं–

➡ लिंक-1 : मोरबी जिले के माछू-II बांध से जामनगर जिले के सैनी (Sani) बांध तक।

- ➲ इस लिंक से राजकोट, मोरबी, देवभूमि द्वारका और जामनगर जिलों के 30 जलाशयों को भरा जाएगा, जिससे 202100 एकड़ क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
- ➲ लिंक-2 : सुरेंद्रनगर जिले के लिंबडी-भोगावो-II बांध से अमरेली जिले के रायदी बांध तक।
- ➲ लिंक-2 से भावनगर, बोटाद एवं अमरेली जिलों के 17 जलाशयों को भरा जाएगा, जिससे 274700 एकड़ भूमि लाभान्वित हो सकेगी।

➡ लिंक-3 : सुरेंद्रनगर जिले के धोलिधाजा बांध से राजकोट जिले के वेणु-1 बांध तक।

- ➲ लिंक-3 से राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों के 28 जलाशयों को भरा जा सकेगा जिससे 198067 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी।

➡ लिंक-4 : सुरेंद्रनगर जिले के लिंबडी भोगावो-II बांध से जूनागढ़ की हिरण-II सिंचाई योजना तक।

- ➲ इससे राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर, सोमनाथ, अमरेली और बोटाद जिलों के 40 जलाशयों को भरा जा सकेगा।
- ➲ इससे 347722 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

स्वच्छ प्रतीक स्थल पहल

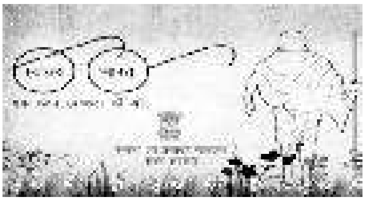

स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के 100 प्रतीकात्मक (Iconic) धरोहर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर केंद्रित एक विशेष स्वच्छता पहल को संचालित करने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस पहल के लिए 'समन्वयक मंत्रालय' (Co-ordinating Ministry) के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारें इस पहल में भागीदार हैं। इस पहल का उद्देश्य इन 100 स्थलों को मॉडल 'स्वच्छ पर्यटन गंतव्यों' के रूप में विकसित कर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के पर्यटन संबंधी अनुभवों में सुधार लाना है।

➡ केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रतीक स्थलों (Swachh Iconic Places) के संबंध में दूसरी तिमाही समीक्षा बैठक 25 अप्रैल, 2017 को जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी श्राइन में आयोजित की गई।

➡ इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वच्छ प्रतीक स्थल पहल के दूसरे चरण के अंतर्गत 10 नए महत्वपूर्ण स्थानों की घोषणा की।

➲ ये 10 स्थल हैं :– 1. गंगोत्री, 2. यमुनोत्री, 3. महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन; 4. चार मीनार, हैदराबाद; 5. चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, गोवा; 6. आदि शंकराचार्य निवास, कलाडी, एर्नाकुलम; 7. श्रावणबेलगोला में गोमतेश्वर; 8. बैजनाथ धाम, देवघर; 9. गया तीर्थ, बिहार और 10. सोमनाथ मंदिर, गुजरात।

➡ उल्लेखनीय है कि पहले चरण में निम्न 10 प्रतीक स्थल शामिल किए गए थे :–1. अजमेर शरीफ दरगाह, राजस्थान 2. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई; 3. स्वर्ण मंदिर, अमृतसर; 4. कामाख्या मंदिर, असम; 5. मणिकर्णिका घाट, वाराणसी; 6. मीनाक्षी मंदिर, मदुरई; 7. श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू-कश्मीर; 8. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी (ओडिशा); 9. ताजमहल, आगरा; 10. तिरुपति मंदिर, तिरुमाला (आंध्र प्रदेश)।

➡ उल्लेखनीय है कि देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1.92 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए, साथ ही स्वच्छता कवरेज बढ़कर 64 प्रतिशत तक पहुंच गई।

➡ जम्मू-कश्मीर में रियासी (Reasi) खुले में शौच से मुक्त (ODF) पहला ब्लॉक घोषित किया गया।

साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

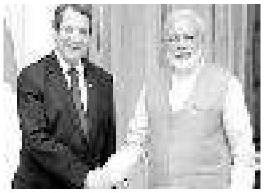

साइप्रस पूर्वी भू-मध्यसागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसकी राजधानी निकोसिया है। भारत और साइप्रस के बीच संबंध पारंपरिक रूप से बहुत करीबी और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति आर्कबिशप मैकारिऑस (Archbishop Makarios), जिन्हें साइप्रस का राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थे। ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों के विरुद्ध साइप्रस के संघर्ष को भारत द्वारा समर्थन भी दिया गया था। भारत-साइप्रस संबंधों की प्रगाढ़ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, कि साइप्रस के अब तक के लगभग सभी राष्ट्रपतियों द्वारा भारत की राजकीय यात्रा की गई। इसी क्रम में साइप्रस के वर्तमान राष्ट्रपति निकॉस अनास्तेसियाड्स (Nicos Anastasiades) 25-29 अप्रैल, 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।

➡ 25 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति अनास्तेसियाड्स अपनी पहली भारतीय यात्रा (राजकीय) पर मुंबई पहुंचे जहां उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की।

➡ 28 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में अनास्तेसियाड्स द्वारा भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारिऑस-III'** से सम्मानित किया गया।

➲ भारत और साइप्रस के बीच निम्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए–

1. व्यापारिक नौवहन समझौता (Merchant Shipping Agreement)।
2. संशोधित नागरिक उड्डयन समझौता।
3. कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्ययोजना।
4. सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम।

➡ उल्लेखनीय है कि साइप्रस भारत में 8वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।

➲ अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2016 के मध्य साइप्रस द्वारा भारत में 9.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है।

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड अधिनियम, 1981 द्वारा नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति हेतु नाबार्ड, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सहबद्ध अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए ऋण प्रदान करने के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और इनका विनियमन भी करता है। इसके बावजूद भी वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि की हिस्सेदारी 17.40 प्रतिशत है और कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव बना हुआ है। अतः नाबार्ड को अधिक सशक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र का अधिक विकास किया जा सके। इन्हीं प्रयासों के तहत नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन प्रस्तावित है।

नाबार्ड
NABARD

➡ 5 अप्रैल, 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 लोक सभा में पेश किया गया।

➡ यह विधेयक नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन के द्वारा नाबार्ड को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

➡ इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

➲ विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार नाबार्ड की पूंजी 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के सलाह से इसे 30,000 करोड़ से अधिक भी कर सकती है।

➲ ज्ञातव्य है कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार, नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है, जिसे आरबीआई की सलाह पर केंद्र सरकार बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर सकती है।

➡ विधेयक के अनुसार, नाबार्ड में केंद्रीय सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

➲ ज्ञातव्य है कि नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार, नाबार्ड में केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी को न्यूनतम 51 प्रतिशत रखने का प्रावधान है।

➡ यह विधेयक 'लघु स्तर के उद्योग' और 'छोटे तथा विकेंद्रित क्षेत्र में उद्योग' जैसे शब्दों को 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' जैसे शब्दों से बदलने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि एमएसएमई एक्ट, 2006 में परिभाषित है।

➡ 1981 के अधिनियम के तहत नाबार्ड मशीनरी एवं संयंत्र में 20 लाख रुपये तक के निवेश वाले उद्योगों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं

प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है।

➲ विधेयक में इस बाध्यता के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले तथा सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यमों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

➲ नाबार्ड अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित 'कंपनी अधिनियम, 1956' को 'कंपनी अधिनियम, 2013' द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1941 में सिडनी में भारत के व्यापारिक कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। इसके बाद 1945 में कैनबरा में भारतीय उच्चायोग स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मेलबर्न में तथा वर्ष 2011 में पर्थ में भारत के महावाणिज्य दूतावास (Consulate General) की स्थापना की गई। वर्ष 2014 में मोदी सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा प्रशांत सागरीय द्वीपीय देशों को शामिल किया गया। वर्ष 2014-15 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कुल 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न की।

➡ 9-12 अप्रैल, 2017 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की।

➲ यह प्रधानमंत्री टर्नबुल की पहली भारत यात्रा थी।

➲ इसके पूर्व तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॅट ने सितंबर, 2014 में भारत की राजकीय यात्रा की थी।

➲ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर, 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे।

➲ 10 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री टर्नबुल का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया।

➡ मैल्कम टर्नबुल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तथा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।

➡ 10 अप्रैल, 2017 को ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता संपन्न हुई।

➡ वार्ता के पश्चात दोनों देशों के मध्य निम्न 6 समझौतों/समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए—

(i) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(ii) नागरिक उड्डयन सुरक्षा में सहयोग के विकास एवं संवर्द्धन के लिए समझौता-ज्ञापन।

(iii) पर्यावरण, जलवायु और वन्य जीवन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(iv) खेल में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(v) स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता - ज्ञापन।

(vi) भू-अवलोकन और उपग्रह नौवहन में सहयोग पर इसरो और भू-विज्ञान ऑस्ट्रेलिया के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था।

➡ समझौते के पश्चात दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

➲ संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी, संयुक्त रणनीतिक कार्य, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों में सहयोग को मजबूत करने, साझा समृद्धि, ऊर्जा, संसाधन एवं पर्यावरण, शिक्षा और कौशल, नवाचार और विज्ञान, खेल और स्वास्थ्य सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।

➲ संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन का स्वागत किया।

➲ प्रधानमंत्री टर्नबुल ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन का उल्लेख किया।

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा भारत को नागरिक परमाणु हस्तांतरण अधिनियम के पारित होने का स्वागत किया।

➲ इस अधिनियम के पारित होने से भारत को शीघ्र ही ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का वाणिज्यिक निर्यात संभव हो सकेगा।

➡ चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मुंबई की यात्रा भी की।

➲ मुंबई में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले तथा प्रमुख व्यावसायिक नेताओं के साथ बातचीत एवं एक ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया।

➡ उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जी-20 के एंताल्या (2015) तथा हांगझाऊ (2016) सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें की थीं।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य
करेन्ट नोट्स
वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा-जोखा

वैश्विक शांति सूचकांक, 2017

*वैश्विक शांति सूचकांक की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया (Steve Killelea) द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। यह सूचकांक प्रति वर्ष **'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस'** (Institute for Economics and Peace: IEP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आईईपी विश्व का एक अग्रणी विचार मंच है जो वैश्विक शांति का विश्लेषण करने तथा इसके आर्थिक लाभों की मात्रा का निर्धारण करने हेतु विभिन्न प्रणालियों का विकास करने के क्षेत्र में संलग्न है। ब्रिटिश संस्था 'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (Economist Intelligence Unit : EIU) भी वैश्विक शांति सूचकांक को तैयार करने में आईईपी को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।*

- 1 जून, 2017 को आईईपी द्वारा 'वैश्विक शांति सूचकांक, 2017' (Global Peace Index, 2017 : GPI) जारी किया गया।
  - इस सूचकांक का यह **11वां वार्षिक संस्करण** है।
  - वर्ष 2017 के वैश्विक शांति सूचकांक का केंद्रीय विषय है– '**एक जटिल विश्व में शांति का मापन**' (Measuring Peace in a Complex World)।
  - वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व की लगभग 99.7 प्रतिशत जनसंख्या के शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है।
  - वर्ष 2017 के इस सूचकांक में विश्व के **163 स्वतंत्र देशों/क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग** प्रदान की गई है।
- वैश्विक शांति सूचकांक, 2017 के परिणाम दर्शाते हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व में शांति के स्तर में 0.28 प्रतिशत की दर से सुधार हुआ है।
  - इस दौरान 93 देशों के शांति के स्तर में बढ़ोत्तरी जबकि 68 देशों के शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई।
- इस सूचकांक के अनुसार, **यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र** है।
  - विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से 8 इसी क्षेत्र में स्थित हैं।
  - लगातार पांचवें वर्ष **'मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका'** (Middle East & North Africa : MENA) **विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र** घोषित किया गया।
- शांति के संदर्भ में 10 वर्षीय प्रवृत्ति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्ष 2008 से अब तक वैश्विक शांति के स्तर में 2.14 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की गई है।
- इस दौरान 80 देशों के शांति के स्तर में सुधार जबकि 83 देशों के शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई।
- वर्ष 2016 में हिंसा के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुल 14.3 ट्रिलियन डॉलर [क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में] का नुकसान हुआ जो सकल वैश्विक उत्पाद का 12.6 प्रतिशत है।
- वैश्विक शांति सूचकांक, 2017 के अनुसार, 163 देशों में न्यूनतम 1.111 स्कोर के साथ **आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश** है।
  - उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 से लगातार आइसलैंड इस सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर कायम है।
  - **सीरिया** (3.814 स्कोर के साथ 163वां स्थान) **विश्व का सर्वाधिक अशांत देश** है।
  - आइसलैंड के पश्चात सर्वाधिक शांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार है–2. न्यूजीलैंड (स्कोर : 1.241), 3. पुर्तगाल (स्कोर : 1.258), 4. ऑस्ट्रिया (स्कोर : 1.265) तथा 5. डेनमार्क (स्कोर : 1.337)।
  - सीरिया के पश्चात सर्वाधिक अशांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार है– 162. अफगानिस्तान (स्कोर : 3.567), 161. इराक

विश्व शांति सूचकांक, 2017 : दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति

देश	समग्र रैंक	समग्र स्कोर	क्षेत्रीय रैंक
भूटान	13	1.474	1
श्रीलंका	80	2.019	2
बांग्लादेश	84	2.035	3
नेपाल	93	2.080	4
भारत	137	2.541	5
पाकिस्तान	152	3.058	6
अफगानिस्तान	162	3.567	7

(स्कोर : 3.556), 160. दक्षिण सूडान (स्कोर : 3.524) तथा 159. यमन (स्कोर : 3.412)।

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2017 में **भारत को 163 देशों की सूची में 137वां** (स्कोर : 2.541) **स्थान** प्राप्त हुआ है जबकि गत वर्ष वह 141वें स्थान पर था।

➲ भारत की रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार हिंसक अपराधों के स्तर में कमी तथा कानून प्रवर्तन में वृद्धि के कारण दर्ज किया गया।

➡ वैश्विक शांति सूचकांक, 2017 में शामिल विश्व के अन्य प्रमुख देशों में दक्षिण अफ्रीका को 123वां (स्कोर : 2.324), ब्राजील को 108वां (स्कोर : 2.199), अमेरिका को 114वां (स्कोर : 2.232), ब्रिटेन को 41वां (स्कोर : 1.786) तथा जापान को 10वां (स्कोर : 1.408) स्थान प्राप्त हुआ है।

इक्वेटोरियल गिनी : OPEC का 14वां सदस्य

*10-14 सितंबर, 1960 के मध्य बगदाद (इराक) में आयोजित एक सम्मेलन में पांच देशों यथा- ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला के बीच हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप स्थापित **'ओपेक'** (OPEC : Organisation of the Petroleum Exporting Countries) एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है। वर्तमान में इस संगठन का मुख्यालय विएना (ऑस्ट्रिया) में स्थापित है, हालांकि स्थापना के प्रथम पांच वर्षों तक यह जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में विद्यमान था।*

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना तथा उन्हें एकरूप बनाना और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम पदार्थों की कुशल एवं नियमित आपूर्ति, उत्पादकों को एक स्थिर आय एवं पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों को उनकी पूंजी पर उचित प्रतिफल (Fair Return) की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों के स्थिरीकरण पर जोर देना है।

➡ 25 मई, 2017 को **विएना में ओपेक देशों की 172वीं बैठक** का आयोजन किया गया।

➲ इस बैठक में मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी को तत्काल प्रभाव से ओपेक के 14वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

➡ **इक्वेटोरियल गिनी उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश** है, हालांकि इस दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 37वां है।

➡ वर्तमान में इक्वेटोरियल गिनी में 220,000 बैरल/दिन की दर से तेल उत्पादन हो रहा है जिसमें बाजार के स्थिरीकरण की दिशा में ओपेक के प्रयासों के तहत 12000 बैरल/दिन की दर से कटौती की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

➡ उल्लेखनीय है कि पांच संस्थापक देशों के अतिरिक्त कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), गैबन (1975) तथा अंगोला (2007) ने ओपेक की सदस्यता ग्रहण की थी।

➲ इक्वाडोर को ओपेक की सदस्यता से दिसंबर, 1992 में निलंबित कर दिया गया था, हालांकि इसने अक्टूबर, 2007 में पुनः संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली।

➲ जनवरी, 2009 में निलंबित किए जाने के बाद इंडोनेशिया जनवरी, 2016 में पुनः ओपेक का सदस्य बना हालांकि नवंबर, 2016 में इसने एक बार फिर संगठन की सदस्यता को त्याग दिया।

➲ जनवरी, 1995 में सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद गैबन ने जुलाई, 2016 में पुनः ओपेक की सदस्यता ग्रहण कर ली।

➲ इस प्रकार वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या 14 है।

➲ कोई भी देश, जिसका कच्चे तेल का शुद्ध निर्यात संतोषजनक स्थिति में हो, साथ ही मूल रूप से जिसके हित सदस्य देशों के समान हो, वह ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है, बशर्ते उसे सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति सहित तीन-चौथाई पूर्णकालिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त हुआ हो।

विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017

विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी शृंखला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देशों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का वार्षिक संकलन है। यह शृंखला वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जा रही है। 'विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017' में जीवन प्रत्याशा के आंकड़ों के साथ-साथ 35 संकेतकों तथा 21 स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़े समाहित किए गए हैं। सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में जारी एजेंडा 2030 का एक लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करके 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन' (Universal Health Coverage) प्राप्त करना है।

➡ 17 मई, 2017 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) द्वारा विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017 को जारी किया गया। इसे तीन भागों में व्यवस्थित किया गया है।

➡ सतत विकास लक्ष्य (SDG)-3 (सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना तथा अच्छी सेहत को प्रोत्साहित करना) के संबंध में हुई प्रगति संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं–

➲ वर्ष 2015 में गर्भावस्था की जटिलताओं या प्रसव के कारण प्रतिदिन लगभग 830 महिलाओं की मृत्यु हुई।

➲ वर्ष 2015 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर वैश्विक मातृ मृत्यु दर 216 है जिसे वर्ष 2030 तक प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 तक लाने का लक्ष्य है।

➲ इस हेतु न्यूनतम 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से विश्व में मातृ मृत्यु में कमी लाना अपेक्षित है।

➲ वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 19 और पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 43 प्रति 1000 जीवित जन्म थी, जो कि वर्ष 2000 की तुलना में क्रमशः 37 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की कमी को प्रदर्शित करती है।

➡ वर्ष 2015 में अनुमानतः 2.1 मिलियन नए लोग एच.आई.वी. (H.I.V.) से संक्रमित हुए, जो कि वर्ष 2000 में संक्रमित संख्या (लगभग 3.2 मिलियन) से 35 प्रतिशत कम है।

➡ एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर लगभग 212 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आए।

➲ 30 से 70 वर्ष तक की उम्र के बीच मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और पुरानी फेफड़ों की बीमारी से मृत्यु की संभावना 19 प्रतिशत है, जो कि वर्ष 2000 से 17 प्रतिशत की कमी दिखाती है।

➲ वर्ष 2015 में लगभग 800,000 मौतें आत्महत्या के कारण हुई हैं। इसमें सर्वाधिक मौतें डब्ल्यू.एच.ओ. यूरोपियन क्षेत्र (14.1 प्रति 100000) में तथा सबसे कम मौतें डब्ल्यू.एच.ओ. पूर्वी भूमध्य क्षेत्र (3.8 प्रति 100000) में हुईं।

➲ वर्ष 2016 में वैश्विक स्तर पर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में शुद्ध एल्कोहल की खपत 6.4 लीटर प्रति व्यक्ति थी।

➲ वर्ष 2015 में 1.1 अरब से अधिक लोगों ने तंबाकू धूम्रपान किया।

➡ वर्ष 2013 में लगभग 1.25 मिलियन लोग सड़क दुर्घटना में मृत्यु के शिकार हुए जो कि वर्ष 2000 से 13 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 15-29 आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं।

➡ वर्ष 2012 में आंतरिक और बाह्य वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर अनुमानतः 6.5 मिलियन मौतें हुईं, जो कि कुल मौतों का लगभग 11.6 प्रतिशत है। इसमें से सर्वाधिक मौतें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हुईं।

➲ वर्ष 2012 में असुरक्षित जल, साफ-सफाई और स्वच्छता के अभाव के कारण अनुमानतः 871000 मौतें हुईं। इनमें से अधिकांश मौतें अफ्रीकी क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से हुईं।

➡ स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के संबंध में कुछ देशों की ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है–

➲ वर्ष 2015 में कजाख्स्तान में मातृ मृत्यु दर 12 प्रति 100000 जीवित जन्म थी, जबकि सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 70 तक लाने का लक्ष्य है।

➲ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानानुसार, वर्ष 2015 में पापुआ न्यू गिनी में मलेरिया के 900,000 मामले (1200 मौतों के साथ) सामने आए, जबकि वर्ष 2005 में यहां लगभग 14 लाख (2800 मौतों के साथ) मलेरिया के मामले सामने आए थे।

➲ वर्ष 2015 में कंबोडिया में 89 प्रतिशत शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की खुराक प्रदान की गई।

➲ आयरलैंड में वर्ष 2015 में 30 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच के लोगों के हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह अथवा पुराने श्वसन रोग से मृत्यु की संभावना 10.3 प्रतिशत है। आयरलैंड ने वायु को स्वच्छ करके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया है।

➲ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, उरुग्वे के वयस्कों में तंबाकू धूम्रपान करने की प्रवृत्ति वर्ष 2000-2015 के दौरान 40 प्रतिशत से 22 प्रतिशत हो गई।

➡ विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017 के महत्वपूर्ण आंकड़े–

जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)			
शीर्ष देश	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**
जापान	80.5	86.8	83.7
स्विट्जरलैंड	81.3	85.3	83.4
सिंगापुर	80.0	86.1	83.1
स्पेन	80.1	85.5	82.8
ऑस्ट्रेलिया	80.9	84.8	82.8
विश्व	**69.1**	**73.7**	**71.4**

जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)			
भारत एवं पड़ोसी देश	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**
भारत	66.9	69.9	68.3
बांग्लादेश	70.6	73.1	71.8
भूटान	69.5	70.1	69.8
चीन	74.6	77.6	76.1
म्यांमार	64.6	68.5	66.6
नेपाल	67.7	70.8	69.2
पाकिस्तान	65.5	67.5	66.4
श्रीलंका	71.6	78.3	74.9

मातृ मृत्यु दर	
शीर्ष दर वाले देश	**दर (प्रति 100000 जीवित जन्म पर)**
सिएरा लियोन	1360
मध्य अफ्रीका गणराज्य	882
चाड	856
नाइजीरिया	814
दक्षिण सूडान	789

निम्न दर वाले देश	**दर**
फिनलैंड/ग्रीस/आइसलैंड/पोलैंड	3
ऑस्ट्रिया/बेलारूस/चेक गणराज्य/इटली/स्वीडन/कुवैत	4
इस्राइल/नॉर्वे/स्पेन/स्विट्जरलैंड/जापान	5
विश्व	**216**

मातृ मृत्यु दर	
भारत एवं पड़ोसी देश	**दर (प्रति 100000 जीवित जन्म पर)**
भारत	174
श्रीलंका	30
मालदीव	68
भूटान	148
बांग्लादेश	176
म्यांमार	178
नेपाल	258
पाकिस्तान	178
चीन	27
द.- पू. एशिया क्षेत्र	**164**

अल सल्वाडोर : धातु खनन को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश

अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। यहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के बावजूद वर्षा-जल संचयन एक बड़ी समस्या है। अकुशल कृषि प्रक्रियाओं तथा अपर्याप्त औद्योगिक नियंत्रण के कारण यहां व्यापक रूप से भू-क्षरण (Soil Erosion) हुआ है और वनों का लगभग पूरी तरह विनाश हो चुका है और इसी के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। अल सल्वाडोर में वर्ष 1989 से 2009 तक लगातार सत्तारूढ़ रही एरेना पार्टी (Arena Party) द्वारा अपने शासनकाल के दौरान कई खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद से यहां जल समस्या (Water Crisis) में तीव्र वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि खनन गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले जहरीले रसायनों (मुख्यतः सायनाइड), भारी धातुओं तथा अपशिष्ट पदार्थों आदि के कारण यहां का 90 प्रतिशत से अधिक सतही जल संदूषित हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने ***अल सल्वाडोर*** *को लैटिन अमेरिका के* ***'पर्यावरणीय रूप से सर्वाधिक विकृत देशों में से एक'*** *(One of the most Environmentally Degraded Countries) के रूप में सूचीबद्ध किया है।*

➡ देश के जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाने की पहल के रूप में अल सल्वाडोर की संसद ने 29 मार्च, 2017 को सभी प्रकार के धातु खनन (Metal Mining) को प्रतिबंधित करने वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को पारित कर दिया।

- ➲ इस विधेयक में धात्विक खनिजों के अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण तथा दोहन जैसी सभी प्रकार की खनन गतिविधियों के निषेध का प्रावधान किया गया है।
- ➲ अल सल्वाडोर की 84 सदस्यीय संसद में उपस्थित सभी 69 सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया।
- ➲ 27 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति सल्वाडोर सांचेज सेरेन द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह अधिनियम प्रभावी हो गया।
- ➲ इस प्रकार **धातु खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश** बन गया है।
- ➲ हालांकि विश्व के कई देशों में सायनाइड के प्रयोग या खुली खान में खनन (Open-Pit Mining) का निषेध जैसे आंशिक प्रतिबंध अस्तित्व में हैं।
- ➲ जहां कोस्टा रिका में खुली खान में खनन प्रतिबंधित है, वहीं अर्जेंटीना में संवेदनशील हिमानी क्षेत्रों में खनन पर रोक है।

➡ उल्लेखनीय है कि अल सल्वाडोर ने **'मध्य अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते'** (Central American Free Trade Agreement: CAFTA) पर वर्ष 2004 में हस्ताक्षर किए थे।

- ➲ कई मध्य अमेरिकी देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए इस समझौते ने अल सल्वाडोर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे होल्सिम (Holcim), मोंसैंटो (Monsanto) तथा पैसिफिक रिम (Pacific Rim) के खनन कार्य आरंभ करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

➡ अल सल्वाडोर में खनन को प्रतिबंधित करने की दिशा में गंभीर प्रयास वर्ष 2008 में तब प्रारंभ हुए जब तत्कालीन राष्ट्रपति एंटोनियो साका ने खनन परमिट पर रोक लगा दी तथा देश के उत्तरी प्रांत कबानस में स्थित 'अल डोराडो खनन परियोजना' (El Dorado Mining Project) को निरस्त कर दिया।

- ➲ मूल रूप से वैंकूवर स्थित पैसिफिक रिम माइनिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली इस परियोजना को वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलियन-कनाडियन कंपनी 'ओशेना गोल्ड' (Oceana Gold) ने खरीद लिया था।

➲ इस परियोजना में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायनों से देश की राजधानी सहित आस-पास के 65 किमी. क्षेत्र के प्रभावित होने की आशंका थी।

➲ इस परियोजना को निरस्त करने के निर्णय के चलते ओशेना गोल्ड ने अल सल्वाडोर की सरकार पर निवेशकों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 250 मिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग की थी।

➲ मुक्त व्यापार समझौते के नियमों के तहत इस मामले की सुनवाई विश्व बैंक के एक न्यायाधिकरण आईसीएसआईडी (ICSID : International Centre for Settlement of Investment Disputes) द्वारा की गई।

➲ न्यायालय ने ओशेना गोल्ड को खनन परमिट प्राप्त करने के लिए मूल आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का दोषी ठहराते हुए निर्णय अल सल्वाडोर की सरकार के पक्ष में सुनाया।

➲ साथ ही न्यायालय ने मुकदमे के दौरान हुए कानूनी खर्च के एवज में ओशेना गोल्ड द्वारा अल सल्वाडोर की सरकार को 8 मिलियन डॉलर के भुगतान का आदेश दिया।

वैश्विक पवन रिपोर्ट, 2016

विश्व में जलवायु परिवर्तन एवं विकास लक्ष्यों को पूरा करने में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से है जिससे जलवायु पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे में पवन ऊर्जा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। पवन ऊर्जा की उपयोगिता को ध्यान में रखकर समय-समय पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी क्रम में ***'वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद'*** *(Global Wind Energy Council : GWEC) ने वैश्विक पवन रिपोर्ट, 2016 जारी की है।*

GWEC
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL

➡ 25 अप्रैल, 2017 को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2016 के मध्य (एक वर्ष में) विश्व में 54 गीगावॉट से अधिक स्वच्छ नवीकरणीय पवन ऊर्जा स्थापित की गई।

➲ वर्ष 2016 के दौरान 54 गीगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने में 90 देश शामिल रहे।

➲ इसमें से 9 ऐसे देश हैं, जिन्होंने 10,000 मेगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा को स्थापित किया (वर्ष 2015-16)।

➲ साथ ही 29 देश ऐसे हैं, जिन्होंने 1000 मेगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।

➡ विश्व में कुल पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2016 के अंत तक 486.8 गीगावॉट है।

➲ वर्ष 2016 में पवन ऊर्जा में वृद्धि 12.6 प्रतिशत रही।

➲ मार्च, 2017 तक संचयी पवन ऊर्जा क्षमता 500 गीगावॉट को पार कर चुकी है।

➡ जी.डब्ल्यू.ई.सी. के लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2021 के अंत तक 800 गीगावॉट पवन ऊर्जा की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष पवन ऊर्जा में 75 गीगावॉट की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

➲ वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा वर्ष 2017 में 60 गीगावॉट नई पवन ऊर्जा की स्थापना का अनुमान लगाया गया है।

➡ वैश्विक पवन रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, वैश्विक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से एशिया वर्ष 2016 तक 203685 मेगावॉट पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ शीर्ष पर है।

➡ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 के अंत तक विश्व में 168732 मेगावॉट पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ चीन शीर्ष पर है।

➲ वर्ष 2015 से 2016 के मध्य विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि (23370 MW) चीन में हुई।

➡ विभिन्न देशों के बाजारों में पवन ऊर्जा की भागीदारी के अनुसार, डेनमार्क 40 प्रतिशत पवन ऊर्जा में वृद्धि के साथ शीर्ष पर है।

➲ आयरलैंड अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का 20 प्रतिशत से अधिक पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त करता है।

➲ चीन, अमेरिका और कनाडा अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का क्रमशः 4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त करते हैं।

➡ दिसंबर, 2016 तक पवन ऊर्जा की वैश्विक संचयी क्षमता में प्रतिशतता के अनुसार, पांच बड़े देशों में चीन (34.7%), यू.एस.ए. (16.9%), जर्मनी (10.3%), भारत (5.9%) तथा स्पेन (4.7%) शामिल हैं।

➡ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में विश्व में नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में प्रतिशतता के अनुसार पांच शीर्ष देशों में क्रमशः चीन (42.8%), यू.एस.ए. (15%), जर्मनी (10%), भारत (6.6%) तथा ब्राजील (3.7%) शामिल हैं।

➡ वैश्विक पवन रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, भारत विश्व में पवन ऊर्जा की संचयी क्षमता एवं वर्ष 2016 के मध्य नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में विश्व में चतुर्थ स्थान पर है।

➡ वर्ष 2016 में 3612 मेगावॉट की नई पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के साथ अब भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 28,700MW (28.7GW) हो गई है।

➲ वर्तमान में भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है।

➲ भारत सरकार वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध है।

➲ इस लक्ष्य में 100 GW की सौर ऊर्जा क्षमता तथा 60 GW की संचयी पवन ऊर्जा क्षमता हासिल किया जाना शामिल है।

आर्थिक परिदृश्य
करेन्ट नोट्स
देश-विदेश की आर्थिक महत्त्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टिपात

बंगनपल्ली आम को जीआई टैग

किसी-किसी वस्तु की गुणवत्ता, उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर निर्भर करती है और उत्पादन का स्थान बदलने पर उसकी गुणवत्ता भी बदल जाती है। अतः इस तरह के किसी खास उत्पाद की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए यह जरूरी है कि ग्राहकों को उसके उत्पादन की जगह के बारे में भी बताया जाए। अतः किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए किसी स्थान विशेष के नाम के प्रयोग को 'भौगोलिक संकेत' (Geographical Indication : GI) कहा जाता है, क्योंकि स्थान विशेष का उल्लेख होते ही उस वस्तु के उद्‌गम/निर्माण स्थल व स्रोत की जानकारी स्वतः मिल जाती है। भौगोलिक संकेत कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक संकेत दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं, जो उत्पाद के उद्‌भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे शैंपेन (एक विशेष प्रकार की मदिरा, जो वास्तव में फ्रांस के एक प्रांत का नाम है और इसे यहीं उगने वाले अंगूरों से बनाया जाता है), दार्जिलिंग चाय आदि। दूसरे हैं-गैर-भौगोलिक पारंपरिक नाम, जो यह बताते हैं कि उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबद्ध है, जैसे अल्फांसो, बासमती आदि। किसी जीआई (GI) का पंजीकरण इसके पंजीकृत स्वामी और अधिकृत प्रयोगकर्ता को जीआई के प्रयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। गैर-अधिकृत व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता।

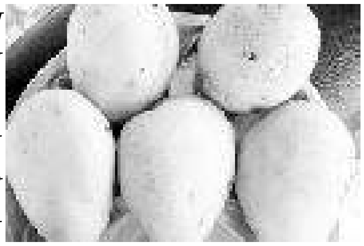

- ➡ अप्रैल, 2017 में चेन्नई स्थित 'भौगोलिक संकेत पंजीकरण' (GIR) कार्यालय द्वारा **'आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली आम'** (Banaganapalle Mangoes) को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया।
  - ➲ बंगनपल्ली आम को यह दर्जा कृषि उत्पादों के अंतर्गत दिया गया है।
  - ➲ ज्ञातव्य है कि यह भारत का 295 वां (आंध्र प्रदेश का 16वां) उत्पाद जबकि कृषि श्रेणी में 84वां उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त हुआ है।
- ➡ अब आंध्र प्रदेश सरकार बंगनपल्ली आमों के जीआई टैग की स्वामी के रूप में पंजीकृत हो गई है।
- ➡ उल्लेखनीय है कि बंगनपल्ली आम को बनेशन, चप्पताई, सफेदा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।
- ➡ आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित बंगनपल्ली एवं आस-पास के क्षेत्रों की विशिष्ट कृषि-जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां बंगनपल्ली आमों को अद्वितीय विशेषताएं प्रदान करती हैं।
  - ➲ आमतौर पर बंगनपल्ली आम आकार में बड़ा होता है तथा इसके पके फलों का रंग 'सुनहरा पीला' (Golden Yellow) होता है।
  - ➲ इसके छिल्के पतले होते हैं एवं उन पर हल्की चित्तियां (Light Spots) पाई जाती हैं।
  - ➲ शीतागार (Cold Storage) में रखे जाने पर ये आम तीन महीने तक अपनी गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं।
- ➡ कुरनूल जिले के बंगनपल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगनपल्ली, पानयम एवं नंदयाल मंडल इन आमों के उत्पादन के प्राथमिक केंद्र हैं।
  - ➲ इसके अतिरिक्त रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के खम्माम, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक एवं आदिलाबाद जिलों को इन आमों के उत्पादन के द्वितीयक केंद्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - ➲ समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक बंगनपल्ली आमों की अच्छी पैदावार होती है। इससे अधिक ऊंचाई पर फल के उत्पादन में गिरावट आने लगती है।
  - ➲ उष्णकटिबंधीय जलवायु भी इन आमों के उत्पादन में मददगार होती है।

भौगोलिक संकेत : अन्य प्रमुख तथ्य

- ◆ औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय के अनुच्छेद 1(2) तथा 10 के तहत भौगोलिक संकेतों को औद्योगिक संपदा अधिकारों के एक अवयव के रूप में शामिल किया गया है।
- ◆ बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के अनुच्छेद 22-24 के अंतर्गत भी इन्हें कवर किया गया है।
- ◆ भारत ने विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य के रूप में 'माल के भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999' [Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999] को लागू किया है तथा यह अधिनियम 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी है।

➡ आंध्र प्रदेश में प्रति वर्ष 24.35 लाख मीट्रिक टन बंगनपल्ली आमों का उत्पादन होता है।

➲ इनमें से प्रति वर्ष लगभग 5500 टन आमों का अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों इत्यादि को निर्यात कर दिया जाता है।

➲ प्रति वर्ष लगभग 1461 करोड़ रु. मूल्य के बंगनपल्ली आमों का व्यापार किया जाता है जिसका मात्र 1.4 प्रतिशत (20.68 करोड़ रुपये) निर्यात से प्राप्त होता है अर्थात इन आमों की देश में ही मांग काफी ज्यादा है।

➲ यह देश के लगभग 7,68,250 परिवारों की आजीविका का स्रोत भी है।

द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

मौद्रिक नीति वह उपकरण है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक तरलता तथा साख सृजन को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को बनाए रखने तथा उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारतीय संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वह प्राधिकृत संस्था है जो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। वर्तमान में मौद्रिक नीति निर्माण का कार्य मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee : MPC) द्वारा किया जाता है। स्मरणीय है कि इस 6 सदस्यीय समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण एवं नीति निर्माण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जून, 2016 में किया गया था।

➡ 7 जून, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee : MPC) ने द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 (Second Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2017-18) जारी किया।

➡ मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा जारी वर्तमान मौद्रिक नीति वक्तव्य वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय तथा कुल पांचवीं मौद्रिक नीति है।

➡ मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें निम्न हैं–

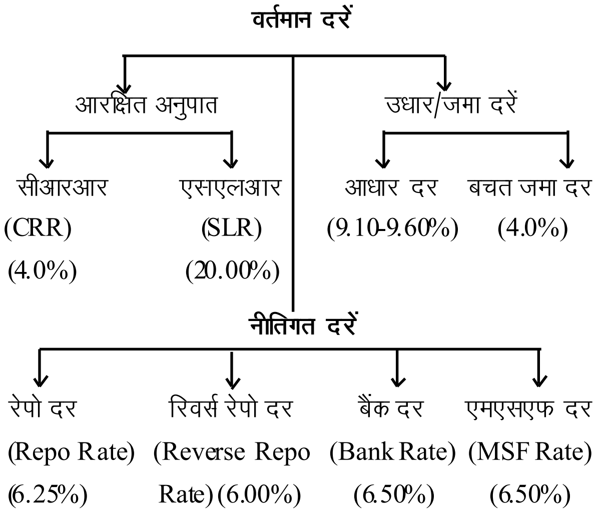

➡ मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा घोषित द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति में 'चलनिधि समायोजन सुविधा' (LAF) के अंतर्गत रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर तथा एमएसएफ दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

➡ आरक्षित अनुपातों सीआरआर (CRR) तथा एसएलआर (SLR) में भी कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं किया गया है।

➡ उल्लेखनीय है कि 24 जून, 2017 से एसएलआर (SLR) में 50 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 20.50 से घटाकर 20.00 प्रतिशत कर दिया गया है।

➡ एमपीसी के अनुसार, नीतिगत हस्तक्षेपों के बिना वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में मुख्य मुद्रास्फीति (Headline Inflation) 2-3.5 प्रतिशत तथा दूसरी छमाही में 3.5-4.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है।

➲ समिति ने जीएसटी लागू किए जाने से मुद्रास्फीति पर किसी विशेष प्रभाव की संभावना को नकार दिया है।

➡ उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 के बाद से पहली बार मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर आई है।

➲ मौद्रिक नीति समिति ने इसे स्थायी तौर पर 4 प्रतिशत के करीब बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

➲ 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन के बाद पहली बार एक सदस्य रवींद्र एच. ढोलकिया समिति के निर्णय से असहमत रहे। शेष पांच सदस्यों ने निर्णयों पर अपनी सहमति व्यक्त की।

विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को भंग करने की स्वीकृति

आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन 'विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' (Foreign Investment Promotion Board : FIPB) का गठन किया गया था। यह एजेंसी देश में निवेश संवर्धन करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment : FDI) से संबंधित मामलों पर कार्यवाही हेतु अधिकृत थी। वर्ष 1996 में इसे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) के अधीन लाया गया। जनवरी, 2003 में पुन: इसे वित मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में यह एक अंतर मंत्रालयी निकाय है तथा इसके अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं।

➡ विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने 24 मई, 2017 को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दे दी।

➡ ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अपने बजट भाषण में ही इसे भंग किए जाने की घोषणा की जा चुकी है।

➡ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह दो तरीकों से होता है– प्रथम 'स्वचालित मार्ग' और द्वितीय 'सरकार द्वारा अनुमोदन'।

- ➲ विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड अनुमोदित मार्गों के तहत आने वाले 5,000 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एकल खिड़की (Single Window) है।
- ➲ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह स्वचालित मार्ग के माध्यम से हो रहा है, जिसमें विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इन प्रस्तावों का अनुमोदन संबंधित क्षेत्रीय नियमों के अधीन होता है।
- ➲ शेष बचे एफडीआई प्रवाह के लिए संबंधित विभाग अपने तरह से नियम बनाते हैं।
- ➲ विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा कई बार एफडीआई अनुमोदनों को मंजूरी देने में देरी हो जाती थी जिससे विकास कार्य भी बाधित हो जाते थे।
- ➲ एफडीआई अनुमोदन से संबंधित अधिक नियम कानून होने के कारण भी निवेशकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।

➡ वर्तमान में लगभग सभी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों को ऑनलाइन किया जा चुका है।

- ➲ अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया संबंधी कार्य और एफडीआई नीति एवं फेमा के तहत सरकार की मंजूरी आदि को अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाया जाएगा।
- ➲ नए नियम से विदेशी निवेशकों को निवेश की दृष्टि से भारत अधिक आकर्षक दिखेगा और इसके परिणामस्वरूप एफडीआई का प्रवाह भी बढ़ेगा।

कृषिगत उत्पादन, 2016-17 : तृतीय अग्रिम अनुमान

आज भी भारतीय कृषि का निष्पादन मानसून पर निर्भर करता है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा सामान्य से कम होती है, उस वर्ष कृषिगत उत्पादन में कमी देखी जाती है लेकिन जिस वर्ष मानसूनी वर्षा सामान्य अथवा अधिक होती है, उस वर्ष कृषिगत उत्पादन में भी वृद्धि देखी जाती है। वर्ष 2016 के दौरान अच्छी वर्षा एवं सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप, 2016-17 में देश के खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े निम्न हैं–

➡ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 मई, 2017 को वर्ष 2016-17 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया।

➡ वर्ष 2016-17 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 273.38 मिलियन टन अनुमानित है, जो अब तक का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होगा।

➡ यह वर्ष 2013-14 में अब तक के सर्वाधिक उत्पादन 265.04 मिलियन टन से 8.34 मिलियन टन (3.15%) अधिक है।

- ➲ मौजूदा वर्ष का अनुमानित उत्पादन विगत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के औसत खाद्यान्न उत्पादन से भी 16.37 मिलियन टन (6.37%) अधिक है।
- ➲ वर्ष 2016-17 के खाद्यान्न उत्पादन में गत वर्ष (2015-16) के खाद्यान्न उत्पादन (251.57 मि.टन) की तुलना में 21.81 मिलियन टन (8.67%) की वृद्धि दर्ज की गई।

➡ इस वर्ष चावल का कुल उत्पादन 109.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो एक नया कीर्तिमान भी है।

- ➲ यह वर्ष 2013-14 के रिकॉर्ड उत्पादन (106.65 मि.टन) की तुलना में 2.50 मिलियन टन (2.34%) तथा विगत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के औसत उत्पादन (105.42 मिलियन टन) की तुलना में भी 3.73 मिलियन टन (3.54%) अधिक है।
- ➲ वर्ष 2015-16 में 104.41 मिलियन टन उत्पादित चावल की तुलना में वर्ष 2016-17 के चावल उत्पादन में 4.74 मिलियन टन (4.54%) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

➡ इस वर्ष गेहूं का अनुमानित उत्पादन 97.44 मिलियन टन भी नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

- ➲ यह वर्ष 2013-14 में अब तक के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 95.85 मिलियन टन की तुलना में 1.66 प्रतिशत अधिक है।
- ➲ वर्ष 2016-17 के दौरान गेहूं का उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के औसत गेहूं उत्पादन (92.6 मिलियन टन) से भी 4.83 मिलियन टन (5.21%) अधिक है।
- ➲ वर्ष 2016-17 का गेहूं उत्पादन, वर्ष 2015-16 के दौरान 92.29 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की तुलना में 5.15 मिलियन टन (5.58%) अधिक है।

➡ सभी मुख्य दलहनी फसलों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 22.40 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अब तक के सर्वाधिक दलहन उत्पादन 19.25 मिलियन टन से भी 3.15 मिलियन टन (16.37%) अधिक है।

- ➲ वर्ष 2016-17 के दौरान दलहनों का उत्पादन, विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 4.77 मिलियन टन (27.3%) अधिक अनुमानित है।

➲ वर्ष 2016-17 में अनुमानित दलहन उत्पादन के गत वर्ष के 16.35 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.05 मिलियन टन (37.03%) अधिक रहने का अनुमान है।

➡ मोटे अनाजों का उत्पादन, जो 44.39 मिलियन टन के एक नए रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है, पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 3.04 मिलियन टन (7.36%) अधिक है।

➲ वर्ष 2016-17 में मोटे अनाजों का उत्पादन वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त अब तक के सर्वाधिक उत्पादन 43.40 मिलियन टन से भी 0.99 मिलियन टन (2.28%) अधिक है।

➲ मौजूदा वर्ष (2016-17) के उत्पादन में गत वर्ष (2015-16) के उत्पादन 38.52 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 5.87 मिलियन टन (15.32%) वृद्धि का अनुमान है।

➡ गत वर्ष (2015-16) की तुलना में 7.27 मिलियन टन (28.80%) की वृद्धि के साथ वर्ष 2016-17 में देश में कुल तिलहन उत्पादन 32.52 मिलियन टन अनुमानित है।

➲ इस वर्ष तिलहन का उत्पादन गत पांच वर्षों के औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में भी 3.27 मिलियन टन (11.17%) अधिक है।

➡ वर्ष 2016-17 में गन्ने का उत्पादन 306.03 मिलियन टन अनुमानित है। यह गत वर्ष (2015-16) के उत्पादन (348.45 मिलियन टन) की तुलना में 42.42 मिलियन टन (-12.17%) कम है।

➡ वर्ष 2016-17 के दौरान कम क्षेत्रीय कवरेज के बावजूद कपास की उच्चतर उत्पादकता के परिणामस्वरूप 32.58 मिलियन गांठें (प्रति गांठ 170 किग्रा.) प्राप्त होने का अनुमान है।

➲ यह वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादित 30.01 मिलियन गांठों की तुलना में 8.57 प्रतिशत अधिक है।

➡ जबकि दूसरी ओर जूट एवं मेस्ता के अनुमानित उत्पादन 10.27 मिलियन गांठों (प्रति 180 किग्रा.) में वर्ष 2015-16 में उत्पादित 10.52 मिलियन गांठों की तुलना में थोड़ी कमी (–2.39%) का अनुमान है।

भारत में कृषिगत उत्पादन (मिलियन टन में)

फसल	2014-15	2015-16		2016-17	
	(अंतिम अनुमान)	(तृतीय अ. अनुमान)	(अंतिम अनुमान)	(लक्ष्य)	(तृतीय अ. अनुमान)
चावल	105.48	103.36	104.41	108.50	109.15
गेहूं	86.53	94.04	92.29	96.50	97.44
ज्वार	5.45	4.59	4.24	6.00	4.74
बाजरा	9.18	8.25	8.07	9.50	9.86
मक्का	24.17	21.02	22.57	24.50	26.14
रागी	2.06	1.86	1.82	2.00	1.43
छोटे अनाज	0.39	0.43	0.39	0.50	0.44
जौ	1.61	1.62	1.44	1.85	1.79
मोटे अनाज	42.86	37.78	38.52	44.35	44.39
कुल अनाज	**234.87**	**235.17**	**235.22**	**249.35**	**250.98**
अरहर	2.81	2.60	2.56	3.62	4.60
चना	7.33	7.48	7.06	9.60	9.08
उड़द	1.96	1.88	1.95	2.15	2.93
मूंग	1.50	1.59	1.59	1.87	2.07
अन्य खरीफ दालें	0.77	0.71	0.72	0.96	0.83
अन्य रबी दालें	2.77	2.80	2.47	2.55	2.90
कुल दालें	17.15	17.06	16.35	20.75	22.40
कुल खाद्यान्न	**252.02**	**252.23**	**251.57**	**270.10**	**273.38**
कुल नौ तिलहन	**27.51**	**25.90**	**25.25**	**35.00**	**32.52**
सोयाबीन	10.37	8.92	8.57	13.61	14.00
मूंगफली	7.40	6.89	6.73	8.50	7.65
रेपसीड और सरसों	6.28	6.86	6.80	8.50	7.98
अन्य तिलहन	3.44	3.24	3.15	4.39	2.88
गन्ना	362.33	346.72	348.45	355.00	306.03
कपास #	348.05	305.24	300.05	360.00	325.76
जूट एवं मेस्ता ##	111.26	104.59	105.24	117.00	102.72

नोट–# लाख गांठें प्रत्येक 170 किग्रा., # # लाख गांठें प्रत्येक 180 किग्रा.

एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2017

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु तीन स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रथम, उत्पादन लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि, द्वितीय कृषि आधारित कुटीर उद्योगों एवं क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन तथा तृतीय विपणन हेतु प्रतिस्पर्धी बाजार का सृजन। इनमें से कृषि विपणन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में देश में कृषि बाजार 'राज्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों' (State Agriculture Produce Market Committees) द्वारा विनियमित होते हैं। बाजार पर सरकार के इस नियंत्रण ने प्रतिस्पर्धी बाजार के सृजन को बाधित किया है। कृषि बाजारों पर सरकारी एकाधिकार को खत्म करने एवं किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि विपणन हेतु एक मॉडल अधिनियम (APMC Act, 2017) तैयार किया गया है।

- ➡ कृषि मंत्री द्वारा कृषि विपणन की जरूरतों को देखते हुए इस मॉडल एपीएमसी एक्ट (Model APMC Act), 2017 के प्रमुख प्रावधानों की घोषणा 24 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में की गई।
- ➡ एक्ट के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–
  - ➲ किसी भी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों की स्थापना हेतु वैध व्यक्तियों, उत्पादकों एवं स्थानीय अधिकारियों को आवेदन करने की अनुमति (मौजूदा कानून के तहत केवल राज्य सरकार की पहल पर ही नए बाजार की स्थापना संभव है) प्रदान की गई है।
  - ➲ परिणामस्वरूप अब किसी एक बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति, किसान एवं उपभोक्ताओं द्वारा एक से अधिक बाजार स्थापित किए जा सकते हैं।
  - ➲ इस अधिनियम में उत्पादकों को अपनी उपज कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) द्वारा नियंत्रित मौजूदा बाजारों के माध्यम से ही बेचने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
  - ➲ मौजूदा बाजारों के अतिरिक्त विशिष्ट कृषि उत्पाद हेतु अलग 'विशेष कमोडिटी बाजार' की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
  - ➲ किसी भी बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि जिंसों की बिक्री पर बाजार शुल्क की वसूली का प्रावधान राज्य सरकार के विवेकाधीन रखा गया है।
  - ➲ किसी भी कृषि उत्पाद को बाजार शुल्क से मुक्त घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है।
- ➡ अधिनियम के तहत राज्य कृषि बाजार बोर्ड (State Agricultural Marketing Board) को निम्न दो दायित्व सौंपे गए हैं–(i) किसानों को बाजार-आधारित विस्तारित सेवाएं प्रदान करने हेतु बोर्ड में एक अलग 'विपणन विस्तार सेल' का गठन (ii) अधिसूचित कृषि उत्पादों के वर्गीकरण, मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु एक कृषि उत्पाद विपणन मानक ब्यूरो (Agriculture Product Marketing Standards Bureau) की स्थापना।
  - ➲ कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) को निम्न उत्तरदायित्व दिए गए हैं–

1. बाजार क्षेत्र में होने वाले समस्त लेन-देन एवं मूल्य निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
2. किसानों को बाजार आधारित विस्तारित सेवाएं प्रदान करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि बेचे गए उत्पाद के लिए किसानों को उसी दिन भुगतान हो जाए।
4. बिक्री के लिए बाजार में आए कृषि उत्पादों एवं उनके मूल्यों का प्रकाशन करना।
5. कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी

भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय में लगभग दो-तिहाई (वर्ष 2015-16 में GVA का 66.1%) प्रत्यक्ष योगदान के अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा अर्जन तथा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अभी भी इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं शेष हैं। इन्हीं संभावनाओं के दोहन तथा नवीन क्षेत्रों के सृजन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से प्रति वर्ष सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रालय द्वारा सेवाओं पर तीसरी वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

- ➡ 17-20 अप्रैल, 2017 के मध्य 'सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी' (Global Exhibition on Services : GES) के तीसरे संस्करण का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में किया गया।
  - ➲ सेवाओं के व्यापार में वृद्धि करना, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना तथा नए व्यापारिक मार्गों को खोलने हेतु बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना प्रदर्शनी के प्रमुख उद्देश्य थे।
  - ➲ जीईएस, 2017 का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (SEPC) के सहयोग से किया गया।
  - ➲ 17 अप्रैल, 2017 को प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन से किया।
- ➡ चार दिवसीय प्रदर्शनी में 70 से अधिक देशों ने भाग लिया।
  - ➲ इस प्रदर्शनी में चीन ने फोकस देश (Focus Country) के रूप में प्रतिभाग किया।
- ➡ प्रदर्शनी में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, शिक्षा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं सहित 20 सेवा क्षेत्रों पर फोकस किया गया।
  - ➲ इस वर्ष जीईएस में इसरो ने भी समय आधारित सार्वजनिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित अपनी प्रस्तुतियों (Offerings) को प्रदर्शित किया।
- ➡ उल्लेखनीय है कि सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी, 2016 का आयोजन 21-23 अप्रैल, 2016 के मध्य इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में किया गया था, जिसमें 65 से अधिक देशों ने भाग लिया था।

वैज्ञानिक परिदृश्य
करेन्ट नोट्स
रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा
एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी
अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति

सोलीबैकिलस कलामी : नव-अन्वेषित जीवाणु

सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु इत्यादि सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के शरीर के अंदर तथा पादपों में पाए जाते हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष, जहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, वहां भी इनके अस्तित्व की पुष्टि की गई है।

'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) के सूक्ष्मजीवीय निरीक्षण से ज्ञात होता है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही इस प्रणाली में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्मजीव जीवित रह सकते हैं।

➡ हाल ही में नासा (NASA) की 'जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी' (Jet Propulsion Laboratory : JPL) में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं ने 'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' में 40 महीनों तक स्थापित रहे एक फिल्टर में एक नए जीवाणु (Bacteria)की खोज की है।

- ➲ भारत के भूतपूर्व दिवंगत राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में** इस नव-अन्वेषित जीवाणु को **'सोलीबैकिलस कलामी'** (Solibacillus Kalamii) नाम दिया गया है।
- ➲ उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में आर्द्रता-नियंत्रण तथा वायु-शोधन उपकरणों में कचरे के संग्रहण को रोकने तथा वातावरण को 'निलंबित पार्टिकुलेट मैटर' (Suspended Particulate Matter) से मुक्त रखने के लिए 'हेपा' (HEPA : High-Efficiency Particulate Arrestance) फिल्टर का प्रयोग किया जाता है।
- ➲ यह फिल्टर आईएसएस की पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणाली में शामिल वातायन तंत्र (Ventilation System) का अंग होता है।
- ➲ जिस हेपा फिल्टर से इस जीवाणु की खोज हुई है वह आईएसएस पर जनवरी, 2008 से मई, 2011 तक स्थापित रहा था।

➡ नव-अन्वेषित जीवाणु 'सोलीबैकिलस' प्रजाति का है।

- ➲ हालांकि यह जीवाणु अभी तक पृथ्वी पर नहीं पाया गया है, फिर भी यह परग्रही (Extra-Terrestrial) जीवाणु नहीं है।
- ➲ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाणु प्रक्षेपण के दौरान किसी सामान या उपकरण के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया और वहां की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहा।
- ➲ यह जीवाणु उच्च विकिरण को सहन करने के अतिरिक्त कुछ प्रोटीन-युक्त यौगिकों के उत्पादन में भी सक्षम है जो जैव-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उपयोगी साबित हो सकते हैं।
- ➲ यह जीवाणु ऐसे रसायनों का मुख्य स्रोत साबित हो सकता है, जिनसे भविष्य में विकिरण क्षति से रक्षा में मदद प्राप्त हो सकती है।

कलामसैट

- ◆ तमिलनाडु के करूर जिले में स्थित पल्लापट्टी के 18 वर्षीय छात्र रिफत शारूक ने विश्व के सबसे छोटे एवं हल्के उपग्रह का विकास किया है।
- ◆ इस उपग्रह को भूतपूर्व दिवंगत राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में 'कलामसैट' (KalamSat) नाम दिया गया है।
- ◆ 4 सेंटीमीटर के इस घनाकार उपग्रह (Cube Satellite) का वजन मात्र 64 ग्राम है।
- ◆ यह उपग्रह 'प्रबलित कार्बन फाइबर बहुलक' (Reinforced Carbon Fiber Polymer) द्वारा निर्मित है।
- ◆ यह पहला ऐसा उपग्रह है, जिसे 3-डी प्रिंटिंग तकनीक द्वारा बनाया गया है।
- ◆ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' तथा 'आई डूडल लर्निंग' (I Doodle Learning) द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित **'क्यूब्स इन स्पेस'** (Cubes in Space) नामक प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित इस उपग्रह को 22 जून, 2017 को अमेरिका के वर्जीनिया में वालप्स द्वीप स्थित 'वालप्स उड़ान सुविधा' (Wallops Flight Facility) से साउंडिंग रॉकेट SR-4 द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- ◆ यह प्रथम अवसर था जब किसी भारतीय छात्र के प्रायोगिक उपग्रह का प्रक्षेपण नासा द्वारा किया गया।
- ◆ प्रक्षेपण के बाद 'उप-कक्षीय पथ' (Sub-Orbital Path) में प्रवेश करते ही इस उपग्रह ने कार्य प्रारंभ कर दिया।
- ◆ लगभग 12 मिनट तक परिचालित रहकर विभिन्न आंकड़े एकत्र करने के बाद यह उपग्रह समुद्र में गिर गया।
- ◆ इस उपग्रह का प्रमुख कार्य अंतरिक्ष में 3-डी प्रिंटेड कार्बन फाइबर के कार्य-निष्पादन का प्रदर्शन करना था।

WHO ग्लास (GLAAS) रिपोर्ट, 2017

'स्वच्छता एवं पेयजल का वैश्विक विश्लेषण तथा आकलन' (Global Analysis & Assessment of Sanitation & Drinking Water : GLAAS) संयुक्त राष्ट्र-जल (UN-Water) की एक पहल है। इस पहल का क्रियान्वयन 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) द्वारा किया जाता है। 'ग्लास' (GLAAS) का उद्देश्य सभी स्तरों पर नीति निर्माताओं को निवेश का एक विश्वसनीय, सर्वसुलभ, व्यापक एवं वैश्विक विश्लेषण प्रदान करना है जिससे स्वच्छता, पेयजल इत्यादि के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'ग्लास (GLAAS), 2017' रिपोर्ट जारी की गई।

➡ 13 अप्रैल, 2017 को जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र-जल (UN-Water) की ओर से ग्लास रिपोर्ट, 2017 प्रकाशित की गई।

➡ 'संयुक्त राष्ट्र-जल' स्वच्छता समेत ताजे जल (Fresh Water) से संबंधित मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समन्वय-तंत्र है।

➡ ग्लास रिपोर्ट, 2017 में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत स्वच्छता एवं पेयजल के सार्वभौमिक उपयोग के वित्तपोषण से संबंधित 75 देशों एवं 25 बाह्य सहायता एजेंसियों का विश्वसनीय एवं अद्यतन आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है।

➡ रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग दूषित पेयजल का उपयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें हैजा, पेचिश, टायफाइड एवं पोलियो होने का खतरा है।

  ➲ अनुमान है कि प्रति वर्ष हैजे से होने वाली 5 लाख से अधिक मौतों का कारण दूषित पेयजल है।

  ➲ यदि वित्तीय संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने और वित्तीयन के नए स्रोतों की पहचान करने के प्रयासों में वृद्धि नहीं की जाती, तो सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

  ➲ रिपोर्ट के अनुसार, विगत तीन वर्षों में देशों ने 4.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से जल और स्वच्छता के लिए अपने बजट में वृद्धि की है।

  ➲ 80 प्रतिशत देशों ने रिपोर्ट किया है कि 'जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा' (Water, Sanitation and Hygiene : WASH) वित्तपोषण अभी भी 'वॉश' (WASH) सेवाओं हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

  ➲ जल एवं स्वच्छता पर 'आधिकारिक विकास सहायता' (Official Development Assistance : ODA) खर्च वर्ष 2012 के 6.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2015 में 7.4 बिलियन डॉलर हो गया है।

आईएनएस कारवाड़ एवं काकीनाड़ा सेवामुक्त

दुश्मन द्वारा समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर बंदरगाहों को सुरक्षित रखने में 'सुरंग-भेदी पोतों' (Minesweeper Ships) की भूमिका अहम होती है। उल्लेखनीय है कि भारी यातायात वाले समुद्री मार्गों में विरोधी ताकतें अक्सर बारूदी सुरंगें बिछा देती हैं जो जंगी पोतों के लिए विनाशकारी साबित होती हैं।

अभी तक भारतीय नौसेना के बेड़े में 'कारवाड़ श्रेणी' (Karwar Class) के 6 सुरंग-भेदी पोत तैनात थे, परंतु हाल ही में इस श्रेणी के 2 पोतों यथा आईएनएस कारवाड़ एवं आईएनएस काकीनाड़ा के सेवामुक्त हो जाने के पश्चात इनकी संख्या घटकर 4 रह गई है।

➡ 9 मई, 2017 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक औपचारिक समारोह में आईएनएस कारवाड़ एवं आईएनएस काकीनाड़ा को सेवामुक्त कर दिया गया।

  ➲ आईएनएस कारवाड़ तत्कालीन सोवियत संघ के 'नत्या श्रेणी' (Natya Class) के सुरंग- भेदी पोतों का संशोधित संस्करण था।

  ➲ इसे 14 जुलाई, 1986 को रीगा (रूस) में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

  ➲ वर्ष 2013 तक इस पोत को विशाखापत्तनम से संचालित किया गया तथा इसके पश्चात इसका गृह पोर्ट (Home Port) मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

➡ सोवियत संघ से प्राप्त कारवाड़ श्रेणी का दूसरा सुरंग-भेदी पोत आईएनएस काकीनाड़ा 23 दिसंबर, 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

  ➲ यह पोत भी वर्ष 2013 तक विशाखापत्तनम में तैनात रहा तथा उसके पश्चात मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

➡ इस प्रकार अब भारतीय नौसेना में कारवाड़ श्रेणी के 4 पोत यथा-आईएनएस कन्नूर, आईएनएस कोझीकोड, आईएनएस कुड्डलूर तथा आईएनएस कोंकण ही तैनात हैं।

  ➲ ये चारों पोत भी वर्ष 2018 के अंत तक सेवामुक्त कर दिए जाएंगे।

➡ कारवाड़ श्रेणी के सुरंग-भेदी पोतों का स्थान लेने के लिए भारत शीघ्र ही दक्षिण कोरिया के साथ 12 एमसीएमवी (MCMVs : Mine Counter Measure Vessels) के निर्माण के 32,640 करोड़ रु. मूल्य के समझौते को अंतिम रूप देगा।

➲ इन 12 नए पोतों का निर्माण 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बुसान स्थित 'कंगनम कॉर्पोरेशन' के सहयोग से किया जाएगा।

➲ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Transfer of Technology) द्वारा निर्मित 12 पोतों की श्रृंखला के पहले पोत की आपूर्ति, करार पर हस्ताक्षर होने के लगभग तीन वर्ष बाद (वर्ष 2021 तक) संभावित है।

भारतीय युद्धपोतों की ग्रीस, मिस्र एवं सऊदी अरब यात्रा

हाल के वर्षों में सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती सहित इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसैनिक परिसंपत्तियों को लगातार तैनात किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में जल सर्वेक्षण, तलाशी एवं बचाव, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी और क्षमता-सृजन एवं क्षमता-वृद्धि जैसी गतिविधियों में अनेक देशों की सहायता कर रही है। हाल ही में भूमध्य सागर क्षेत्र में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती से 'अंतर-संचालनीयता' (Inter-operability) तथा समुद्री-मित्रता को मजबूत करने के भारतीय नौसेना के प्रयासों में मदद मिलेगी।

➡ भूमध्य सागर एवं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की समुद्र-पारीय तैनाती के अंग के रूप में कुछ भारतीय युद्धपोत अप्रैल-मई, 2017 के दौरान ग्रीस, मिस्र एवं सऊदी अरब की यात्रा पर रहे।

➡ 17-19 अप्रैल, 2017 के मध्य चार भारतीय युद्धपोतों यथा-आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तरकश और आईएनएस आदित्य ने ग्रीस की तीन दिवसीय यात्रा संपन्न की।

➲ ग्रीस की सौदा खाड़ी (Souda Bay) पर पहुंचने के बाद इन युद्धपोतों ने ग्रीस की 'हैलेनिक नौसेना' (Hellenic Navy) के साथ सैन्य अभ्यासों में प्रतिभाग किया।

➲ उल्लेखनीय है कि भारत और ग्रीस के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना मई, 1950 में हुई थी।

➲ वर्तमान में दोनों देशों के मध्य सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कई द्विपक्षीय समझौते अस्तित्व में हैं, जिनमें से अधिकांश वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की ग्रीस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुए थे।

➲ भारत और ग्रीस के मध्य रक्षा-सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित हुआ था।

➡ 5-7 मई, 2017 के मध्य दो भारतीय युद्धपोत यथा-आईएनएस मुंबई एवं आईएनएस आदित्य मिस्र की यात्रा पर रहे।

➲ बंदरगाह शहर एलेक्जेंड्रिया में पहुंचने के बाद इन दोनों पोतों ने मिस्र की नौसेना के साथ व्यापक रूप से नौसैन्य अभ्यासों में प्रतिभाग किया।

➲ उल्लेखनीय है कि हेलवान-300 (Helwan-300) लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम की स्थापना तथा भारतीय वायुसेना के विमान चालकों द्वारा मिस्र के पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करना, दोनों देशों के रक्षा सहयोग की एक महत्वपूर्ण पहल थी।

➲ वर्ष 2006 में 'भारत-मिस्र संयुक्त रक्षा समिति' की स्थापना दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अन्य कदम था।

➡ 16-18 मई, 2017 के मध्य तीन भारतीय युद्धपोत यथा- आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस आदित्य सऊदी अरब की यात्रा पर रहे।

➲ उल्लेखनीय है कि ये सभी पोत भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसैनिक कमान का अंग है और वर्तमान में मुंबई में तैनात हैं।

आईएनएस तरकश की ब्रिटेन यात्रा

◆ आईएनएस तरकश रूस से प्राप्त तीन नवीनतम स्टील्थ युद्धपोतों की श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है।

◆ भारतीय नौसेना में इसकी तैनाती नवंबर, 2012 में हुई थी।

◆ मई, 2017 में यह पोत ब्रिटेन की यात्रा पर रहा।

◆ आईएनएस तरकश ने अपनी इस सद्भावना यात्रा के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण-17 तथा लंदन में भारत-यूके संस्कृति वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया।

◆ साथ ही यह एचएमएस त्रिंकोमाली युद्धपोत के निर्माण की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों में भी शामिल हुआ।

◆ उल्लेखनीय है कि विश्व के सबसे पुराने युद्धपोत की संज्ञा प्राप्त एचएमएस त्रिंकोमाली, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का युद्धपोत था, जिसका निर्माण 1817 ई. में बॉम्बे डॉकयार्ड में किया गया था।

संक्षिप्तियां करेन्ट नोट्स

चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ/संगठन, योजना/परियोजना, ऑपरेशन/अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ...

चर्चित व्यक्ति

❑ शशि शेखर वेमपति

➡ प्रसार भारती बोर्ड के अंशकालिक सदस्य; प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में पदभार ग्रहण। (12 जून, 2017)

- ➲ शशि यह पद ग्रहण करने वाले प्रथम गैर-आईएएस अधिकारी हैं।
- ➲ कार्यकाल-5 वर्ष।

❑ सी. नारायण रेड्डी

➡ प्रसिद्ध तेलुगू कवि और लेखक एवं पूर्व राज्य सभा सदस्य का निधन। (12 जून, 2017)

- ➲ कविताओं के संग्रह 'विश्वम्भरा' के लिए वर्ष 1988 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित।

❑ मिरोस्लाव लैजकक

➡ स्लोवाकिया के विदेश मंत्री; संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासभा के 72वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित। (31 मई, 2017)

- ➲ वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष पीटर थॉमसन (फिजी) का स्थान लेंगे।

❑ प्रो. राम शंकर कठेरिया

➡ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक सभा सदस्य; राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त।** (31 मई, 2017)

- ➲ कार्यकाल-3 वर्ष
- ➲ इस पद पर वह पी.एल. पुनिया का स्थान लिया।

❑ सैयद गय्यूर उल-हसन रिजवी

➡ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष; **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण।** (30 मई, 2017)

- ➲ इस पद पर उन्होंने वसीम अहमद का स्थान लिया।

➡ कार्यकाल-3 वर्ष।

❑ डॉ. नजमा हेपतुल्ला

➡ मणिपुर की राज्यपाल एवं अल्पसंख्यक मामलों की पूर्व मंत्री; **जामिया मिलिया केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलरः अमीर-ए-जामिया नियुक्त।** (29 मई, 2017)

- ➲ कार्यकाल-5 वर्ष

❑ राकेश कपूर

➡ इफको के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं उर्वरक एसोसिएसन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष; **अंतरराष्ट्रीय उर्वरक एसोसिएशन (IFA) के नए अध्यक्ष निर्वाचित।** (24 मई, 2017)

➡ आईएफए के 90 वर्षों के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय।

❑ डॉ. टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस

➡ इथिओपिया के पूर्व विदेश एवं स्वास्थ्य मंत्री; **विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के नए महानिदेशक नियुक्त।** (23 मई, 2017)

- ➲ 1 जुलाई, 2017 को कार्यभार ग्रहण।
- ➲ कार्यकाल : 5 वर्ष।
- ➲ इस पद उन्होंने डॉ. मार्गेट चान का स्थान लिया।

❑ रोजर मूर

➡ जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुके प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता का निधन। (23 मई, 2017)

- ➲ वर्ष 1991 में उन्हें यूनिसेफ का गुडविल एंबेसेडर नियुक्त किया गया था।

❑ अंशू जामसेनपा

➡ अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही; **5 दिनों के अंतराल में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर दुबारा चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला।** (21 मई, 2017)

❑ विजय कुमार सारस्वत

➡ डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक; केंद्र सरकार द्वारा **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के चांसलर नियुक्त।** (12 मई, 2017)

- ➲ कार्यकाल-5 वर्ष

➡ इस पद पर इन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन का स्थान लिया।

❑ अमिताभ बच्चन

➡ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के सद्भावना दूत नियुक्त। (12 मई, 2017)

➡ इससे पूर्व वह भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनीसेफ के सद्भावना दूत के रूप में कार्य कर चुके हैं।

❑ मून जे-इन

➡ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता; दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। (10 मई, 2017)

- ➲ इस पद पर उन्होंने पार्क ग्युन-हे का स्थान लिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था।

❑ अनिल माधव दवे

➡ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का निधन। (18 मई, 2017)

➡ डॉ. हर्षवर्धन नए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में नियुक्त।

❑ पूजा कपूर

➡ भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा **बुल्गारिया में भारत की अगली राजदूत नियुक्त।** (8 मई, 2017)

❑ न्यायमूर्ति लीला सेठ

➡ प्रसिद्ध विधिशास्त्री एवं देश के किसी उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेश) की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन। (5 मई, 2017)

- ➲ वह लंदन बार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थीं।
- ➲ वह निर्भया प्रकरण के बाद वर्ष 2012 में गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति के तीन सदस्यों में से एक थीं।

❑ मल्लिकार्जुन खड़गे

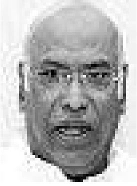

➡ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता; लोक लेखा समिति (PAC) के नए अध्यक्ष नियुक्त। (2 मई, 2017)

- ➲ इस पद पर उन्होंने के.वी. थॉमस का स्थान लिया।
- ➲ ज्ञातव्य है कि लोक लेखा समिति में लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा के 7 सदस्य होते हैं।

❑ शोभना कामिनेनी

➡ अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लि. की कार्यकारी उपाध्यक्ष; वर्ष 2017-18 के लिए 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (CII) की अध्यक्ष निर्वाचित। (1 मई, 2017)

- ➲ इस पद पर वह फोर्ब्स मार्शल के सह-अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स का स्थान लेंगी।

अन्य चर्चित व्यक्ति

- **शेर बहादुर देउबा**— नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष; नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। (7 जून, 2017)
- **बासुदेव चटर्जी**— प्रसिद्ध इतिहासकार एवं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) के पूर्व अध्यक्ष का निधन। (8 जून, 2017)
- **पी. गोवर्धन रेड्डी**— वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राज्य सभा सदस्य का निधन। (9 जून, 2017)
- **रुचिरा कंबोज**— भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त। (6 जून, 2017)
- **संजीव सिंह**— इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के नए अध्यक्ष नियुक्त। (1 जून, 2017)
- **दसारी नारायण राव**— दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं अभिनेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का **निधन।** (30 मई, 2017)
- **जॉर्ज कुरियन**— केरल के प्रसिद्ध सामाजिक और शैक्षणिक कार्यकर्ता; केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त।** (30 मई, 2017)
- **एल. मुरुगन**— केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त।**
- **जयदीप मजूमदार**— भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा **फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त।** (26 मई, 2017)
- **एस. रामास्वामी**— पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। (15 मई, 2017)

- **वानी सरराजू राव**— भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा फिनलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त (26 मई, 2017)
- **सौरभ अग्रवाल**— आदित्य बिड़ला समूह के मुख्य रणनीतिकार; टाटा समूह के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त।
- **चंद्रास्वामी**— प्रसिद्ध तांत्रिक, (वास्तविक नाम नेमीचंद जैन) का निधन। (23 मई, 2017)
- **रीमा लागू**— प्रसिद्ध बॉलीवुड चरित्र अभिनेत्री का निधन। (18 मई, 2017)
- **प्रो. तारिक मंसूर**— अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के नए कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण। (17 मई, 2017)
- **रेनू सती**— पेटीएम भुगतान बैंक लि. (PPBL) की **प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त।** (17 मई, 2017)
- **प्रदीप कुमार अमात**— बीजू जनता दल के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री; सर्वसम्मति से **ओडिशा विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित।** (16 मई, 2017)
- **एडुवर्ड फिलिप**— फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। (15 मई, 2017)
- **नीत चटर्जी**— भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक; अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (FERC) के प्रमुख प्रशासनिक पद के लिए नामित। (9 मई, 2017)
- **न्यायमूर्ति सुबल वैद्य**— त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण। (27 अप्रैल, 2017)
- **आर.के. पचनंदा**— वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण। (30 जून, 2017)
- **राजीव राय भटनागर**— वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के नए महानिदेशक नियुक्त। (26 अप्रैल, 2017)
- **केपीएस गिल**—पंजाब के पूर्व डीजीपी एवं इंडियन हॉकी फेडरेशन (IHF) के पूर्व अध्यक्ष का निधन। (26 मई, 2017)
- **मौनो कोइविस्तो**—फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का निधन। (12 मई, 2017)
- **विनय मोहन क्वात्रा**—भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। (11 मई, 2017)
- **संजय मित्रा**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त। (10 मई, 2017)
- **वेनू राजामोनी**—भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा नीदरलैंड्स में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। (8 मई, 2017)

चर्चित स्थल

❑ मेघालय

➡ हाल ही में मेघालय विधान सभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जारी पशु बिक्री और पशुवध पर रोक संबंधी अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित। (12 जून, 2017)

➲ इससे पूर्व 8 जून, 2017 को केरल विधान सभा में भी इस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

❑ कतर

➡ सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, लीबिया, यमन, मालदीव, मॉरिशस, मारितानिया और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कतर से सभी कूटनीतिक रिश्ते समाप्त करने की घोषणा। (जून, 2017)

➲ इन सभी देशों का आरोप है कि कतर आतंकवाद को समर्थन प्रदान करता है।

❑ धौला गांव

➡ भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्मार्ट ग्राम कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित **धौला गांव** में **चालक प्रशिक्षण संस्थान और माध्यमिक विद्यालय की आधारशिला रखी।** (2 जून, 2017)

➲ इसके अलावा **महेंद्रगढ़, अंबाला** और **पलवल** में तीन नए कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया।

❑ मल्लेश्वरम

➡ केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा द्वारा मल्लेश्वरम (बंगलुरू) में मोदी पर्व (Making of Developed India Festival) का उद्घाटन। (2 जून, 2017)

➲ **उद्देश्य**- केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस अवधि के दौरान सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराना और सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं पहलों के विषय में लोगों को जागरूक करना।

❑ मुजफ्फरपुर

➡ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा मुजफ्फरपुर (बिहार) में **लीची प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन।** (29 मई, 2017)

➲ इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL) एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के सहयोग से की जाएगी।

➲ ज्ञातव्य है कि बिहार लीची उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है।

❑ चित्रदुर्ग

- केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चित्रदुर्ग, कर्नाटक में निर्मित देश के पहले वैमानिकी परीक्षण क्षेत्र (Aeronautical Test Range) को राष्ट्र को समर्पित किया। (28 मई, 2017)

  - इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 1300 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
  - यह देश में अपनी तरह का पहला परीक्षण क्षेत्र है, जहां पर स्वदेशी मानव रहित व मानवयुक्त विमानों का उड़ान परीक्षण किया जा सकता है।

❑ चिली

- विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड दूरबीन का निर्माण यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Obser-vatory) द्वारा चिली में किया जा रहा है।

  - यह दूरबीन सेरो आर्माजोन्स (Cerro Armazones) पर्वत की चोटी (ऊंचाई लगभग 3046 मीटर) पर स्थापित की जाएगी।
- इसका निर्माण कार्य वर्ष 2024 तक पूरा होगा।
  - इस दूरबीन के मुख्य दर्पण का व्यास 39 मीटर है।

❑ मिंडानाओ द्वीप

- फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते द्वारा देश के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में 2 माह के लिए मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा। (23 मई, 2017)

❑ विफांग सिटी

- विश्व का सबसे बड़ा तीली रहित बड़ा चक्र (Spokeless Ferris Wheel) या झूला (ऊंचाई 145 मीटर) चीन के विफांग सिटी के 1771 फीट लंबे बैलांग नदी सेतु पर निर्मित किया गया है।

  - इसका व्यास 125 मीटर है।
  - इसमें बैठने के लिए 36 केबिन हैं तथा प्रत्येक केबिन में 10 लोग बैठ सकते हैं।

❑ जार्डन

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा जार्डन स्थित अज्राक (Azraq) शरणार्थी शिविर में नवनिर्मित सौर संयत्र चालू। (17 मई, 2017)

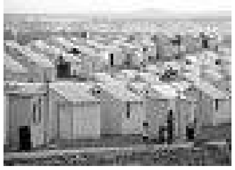

  - यह अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शरणार्थी शिविर है।

❑ यमन

- यमन की सरकार द्वारा राजधानी सना में हैजा का प्रकोप बढ़ने पर आपातकाल की घोषणा। (14 मई, 2017)

❑ ब्राजील

- ब्राजील सरकार द्वारा जीका वायरस के प्रकोप के कारण देश में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा। (11 मई, 2017)

  - ब्राजील द्वारा इस आपातकाल की घोषणा नवंबर, 2015 में की गई थी।
- जीका वायरस रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा संचारित वायरस के कारण होता है।

❑ पुणे

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में स्थापित देश के पहली एकीकृत जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन। (7 मई, 2017)

  - नवीकरणीय ईंधन और रसायन के लिए स्थापित द्वितीय पीढ़ी की इस आधुनिक जैव-परिशोधनशाला की स्थापना से एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को गति मिलेगी।

❑ भीलर

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस द्वारा सतारा जिले में स्थित गांव भीलर (Bhilar) में देश के पहले पुस्तक गांव का उद्घाटन। (4 मई, 2017)

  - इस पुस्तक गांव की अवधारणा ब्रिटेन के हे-ऑन-वाय (Hay-on-Wye) नगर से प्रेरित है, जिसे बुक स्टोर्स तथा साहित्यिक महोत्सवों के लिए जाना जाता है।

❑ असम

- केंद्र सरकार द्वारा 3 माह के लिए संपूर्ण असम सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित। (3 मई, 2017)

  - सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958, भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

❑ विजयवाड़ा हवाई अड्डा

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान** करने को मंजूरी। (3 मई, 2017)

➲ यह मंजूरी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई है।

❑ दुबई

➡ दुबई अपना माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट प्राप्त करने वाला विश्व का पहला शहर बना। (30 अप्रैल, 2017)

➲ टाइप फेस, जिसे दुबई फॉन्ट कहा जाता है, 23 भाषाओं और अरबी एवं लैटिन लिपि में उपलब्ध है।

❑ डोंगरगांव

➡ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के डोंगरगांव में राज्य के पहले स्वचालित मौसम स्टेशन का उद्घाटन। (30 अप्रैल, 2017)

❑ मेक्सिको

➡ मादक पदार्थों से संबंधित हिंसा से ग्रस्त देश मेक्सिको के सांसदों द्वारा द्रव्य नीति पर राष्ट्रीय बहस के बाद चिकित्सकीय उपयोग के लिए गांजा की वैधता से संबंधित विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी। (28 अप्रैल, 2017)

➲ कानून बनने के बाद चिकित्सकीय उपयोग और वैज्ञानिक शोध के उद्देश्य से गांजा की पैदावार, बिक्री एवं वितरण भी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।

❑ जर्मनी

➡ जर्मनी में संसद के निचले सदन द्वारा बुर्का पर आंशिक प्रतिबंध से संबंधित विधेयक को मंजूरी। (27 अप्रैल, 2017)

➲ ऊपरी सदन की मंजूरी के बाद यह प्रतिबंध नागरिक सेवाओं एवं न्यायपालिका में कार्यरत कर्मचारियों और सैन्यकर्मियों पर लागू होगा।

❑ बांग्लादेश

➡ भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम योद्धाओं को पर्यटक वीजा देने का फैसला। (26 अप्रैल, 2017)

➲ इस वीजा की अवधि 5 वर्ष की होगी।

➡ वर्तमान समय में बांग्लादेश के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 5 वर्ष की अवधि तक मान्य भारतीय वीजा प्रदान किया जाता है।

❑ ऑस्ट्रेलिया

➡ ऑस्ट्रेलिया द्वारा नागरिकता कानून में बदलाव की घोषणा। (20 अप्रैल, 2017)

➲ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता कानून संशोधन (ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता एवं अन्य उपायों हेतु आवश्यकताएं सुदृढ़ करना) विधेयक, 2017 संसद में पेश (जून, 2017)।

➲ नए नियमों के अनुसार, ऐसा व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, जो कम-से-कम 4 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से निवास कर रहे हों तथा अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने एवं समझने में सक्षम हो।

पुरस्कार/सम्मान

❑ अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, 2017

➡ डबलिन सिटी काउंसिल द्वारा अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार की घोषणा। (21 जून, 2017)

➲ विजेता-जोस एडुआर्डो एग्वासा (अंगोला), उपन्यास-ए जनरल थियरी ऑफ ऑब्लिवियन (A General Theory of Oblivion) के लिए।

❑ फुकुओका पुरस्कार, 2017

➡ योकाटोपिया फाउंडेशन (पूर्व में फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन) द्वारा फुकुओका पुरस्कारों की घोषणा। (8 जून, 2017)

➡ विभिन्न श्रेणियों के विजेता-

➲ **ग्रैंड पुरस्कार**-पासुक फोंगपैचित (थाईलैंड) एवं क्रिस बेकर (यू.के.)

➲ **कला एवं संस्कृति पुरस्कार**-कांग ने (कंबोडिया)

➲ **अकादमी पुरस्कार**-वांग मिंग (चीन)

❑ डैग हैमार्स्जोल्ड मेडल, 2016

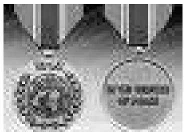

➡ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 117 व्यक्तियों को डैग हैमार्स्जोल्ड मेडल से सम्मानित किया। (24 मई, 2017)

➲ इसमें दो भारतीय शांति सैनिक-बृजेश थापा एवं रवि कुमार (दोनों मरणोपरांत) शामिल हैं।

❑ लोनली प्लैनेट मैगजीन ट्रैवल इंडिया पुरस्कार, 2017

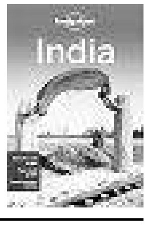

➡ मुंबई में लोनली प्लैनेट मैगजीन ट्रैवल इंडिया पुरस्कार, 2017 की घोषणा। (25 मई, 2017)

➲ इसके अनुसार भारतीयों का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल स्विट्जरलैंड है।

➡ निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है–

श्रेणी	राष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय
सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक पर्यटन स्थल	कर्नाटक	जापान
सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल	महाराष्ट्र	न्यूजीलैंड
सर्वश्रेष्ठ नैतिक मूल्य वाला पर्यटन स्थल	तमिलनाडु	मलेशिया
वन्यजीव के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल	मध्य प्रदेश	द. अफ्रीका
खाद्य एवं पेय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल	लखनऊ (उ.प्र.)	स्पेन
सर्वश्रेष्ठ सुकून वाला पर्यटन स्थल	गोवा	थाईलैंड
सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक पर्यटन स्थल	हिमाचल प्रदेश	सिंगापुर
सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन स्थल	मेघालय	आइसलैंड
रोमांस के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल	मुन्नार (केरल)	ऑस्ट्रिया
खरीददारी के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल	नई दिल्ली	यूएसए

❑ राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार, 2017

➡ राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार की अध्यक्ष कैमिला सैमजी द्वारा ग्रांटा (Granta) मैगजीन के सहयोग से वर्ष 2017 के पुरस्कारों की घोषणा। (22 मई, 2017)

➲ इस पुरस्कार हेतु विश्व के पांच क्षेत्रों से विजेताओं का चयन किया जाता है।

➡ वर्ष 2017 के विजेता-

- **प्रशांत क्षेत्र**– नैट न्यूमैन (ऑस्ट्रेलिया) को, 'द डेथ ऑफ मार्गरेट रो' लघुकथा के लिए।
- **एशिया क्षेत्र**– अनुष्का जसराज (भारत) को, 'ड्राइंग लेसंस' लघुकथा के लिए।
- **अफ्रीका क्षेत्र**– अक्वाएके एमेजी (नाइजीरिया) को, 'हू इज लाइक गॉड' लघुकथा के लिए।
- **कनाडा एवं यूरोप क्षेत्र**– ट्रेसी फेल्स (यूनाइटेड किंगडम) को, 'द नेमिंग ऑफ मॉथ्स' लघुकथा के लिए।
- **कैरेबियन क्षेत्र**– इनग्रिड पेरसौद (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) को, 'द स्वीट सॉप' लघुकथा के लिए।

नोट–सभी विजेता महिलाएं हैं।

❑ बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड, 2017

➡ अवॉर्ड समारोह का आयोजन लास वेगास (यूएसए) में संपन्न। (21 मई, 2017)

➲ कनाडा के प्रसिद्ध रैपर गायक ऑब्रे ड्रेक ग्राहम (ड्रेक) ने सर्वाधिक 13 श्रेणियों में अवॉर्ड प्राप्त किया।

➡ कुछ प्रमुख श्रेणियों के अवॉर्ड इस प्रकार हैं-

- **सर्वश्रेष्ठ कलाकार**– ड्रेक
- **सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार**– जॉयन
- **सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार**– बियान्से
- **सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार**– ड्रेक

❑ डैन डेविड पुरस्कार, 2017

➡ इस्राइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा तेल अवीव में डैन डेविड पुरस्कार, 2017 प्रदान किए गए। (21 मई, 2017)

➲ यह पुरस्कार उन नवाचारी एवं अंत:विषयी अनुसंधानों को पुरस्कृत करता है, जो पारंपरिक सीमाओं एवं मानदंडों को तोड़ते हैं।

➡ यह पुरस्कार प्रति वर्ष तीन समय आयामों 'भूत','वर्तमान' और 'भविष्य' (Past, Present and Future) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

➲ वर्ष 2017 के लिए विभिन्न वर्गों के पुरस्कृत विजेता-

➲ **भूतकाल; पुरातत्व विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान**

1. प्रो. स्वान्ते पाबो, 2. प्रो. डेविड रीच

➲ **वर्तमान; साहित्य**

1. जमैका किंकैड, 2. ए.बी. येहोशुआ

➲ **भविष्य; खगोल विज्ञान**

1. प्रो. नील गहरेल्स, 2. प्रो. श्रीनिवास कुलकर्णी (भारतीय)
3. प्रो. आंद्रजेज उदाल्स्की

❑ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2014

➡ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इसरो (ISRO) को वर्ष 2014 का इंदिरा गांधी शांति, नि:शस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। (18 मई, 2017)

➲ इसरो को यह पुरस्कार मंगल मिशन की सफलता एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया गया है।

➡ यूएनएचसीआर (United Nation High Commissioner for Refugees : UNHCR) को वर्ष 2015 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया था।

❑ कांस फिल्म महोत्सव, 2017

➡ कांस फिल्म महोत्सव का 70वां संस्करण फ्रांस के कांस (Cannes) शहर में संपन्न। (17-28 मई, 2017)

➲ महोत्सव का शुभारंभ फ्रेंच डायरेक्टर अरनॉड डेस्प्लेचिन की फिल्म **'इस्माइल्स घोस्ट्स'** (Ismael's Ghosts) और समापन रुबेन ऑस्टलुंड निर्देशित स्वीडिश फिल्म-**'द स्क्वायर'** (The Square) से।

➡ **प्रमुख पुरस्कार**

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म** (Plam d'Or)— 'द स्क्वायर', निर्देशक-रुबेन ऑस्टलुंड।
- **ग्रैंड प्रिक्स**— '120 बीट्स पर मिनट', निर्देशक-रॉबिन कैंपिल्लो।
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**— सोफिया कापोला, फिल्म-'द बीगाइल्ड'।
- **निर्णायक मंडल पुरस्कार**— 'नेल्यूबॉव' (अंग्रेजी नाम-लवलेस), निर्देशक-आंद्रेई ज्विगिन्त्सेव।
- **सर्वश्रेष्ठ पटकथा**— 'यू वर नेवर रियली हीयर', निर्देशक-लिन रैमसे और 'द किलिंग ऑफ ए सैक्रेड डियर', निर्देशक-यारगॉस लैन्थिमोस।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**— डायने क्रूगर, फिल्म 'अस डेम नाइस्ट्स' (अंग्रेजी नाम-इन द फेड)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**— जोकिन फीनिक्स, फिल्म-'यू वर नेवर रियली हीयर'।
- **सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक** (Camera d' or)— लियोनॉर सिरैली, फिल्म-ज्यून फेम' (अंग्रेजी नाम-मोंटपर्नानेस बीइनवेन्यू)।
- **सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म**— 'जिआओ चेंग इर यू' (अंग्रेजी नाम-ए जेंटिल नाइट), निर्देशक क्यू यांग।
- **70वां वार्षिक पुरस्कार-निकोल किडमैन**

दादासाहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार

➡ प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्या दत्ता को। (7 मई, 2017)

➲ उन्हें यह पुरस्कार फिल्म 'चॉक एंड डस्टर' में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए प्रदान किया गया है।

WWF इंटरनेशनल प्रेसीडेंट्स अवॉर्ड, 2017

➡ WWF (World Wide Fund For Nature) द्वारा मनादो (इंडोनेशिया) में इंटरनेशनल प्रेसीडेंट्स अवॉर्ड प्रदान किया गया। (8 मई, 2017)

➲ **विजेता**-रोहन चक्रवर्ती (भारत) और एडेलीन टिफनी सुवाना (इंडोनेशिया)।

➡ रोहन 'ग्रीन ह्यूमर' (Green Humour) के बैनर तले प्रकृति संरक्षण के मुद्दों पर कार्टून की एक श्रृंखला चलाते हैं।

➲ WWF इंटरनेशनल प्रेसीडेंट्स अवॉर्ड 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करता है, जो प्रकृति संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

17वां न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, 2017

➡ इंडो-अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित। (30 अप्रैल-7 मई, 2017)

LIPSTICK
BURKHA

➲ महोत्सव का शुभारंभ अलंकृता श्रीवास्तव निर्देशित फिल्म-'लिपिस्टक अंडर माई बुर्का' से।

➲ महोत्सव का समापन मिलिंद धायमाडे निर्देशित फिल्म-'यू आर माई संडे' से।

➡ प्रमुख पुरस्कार

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म**— 'मुक्ति भवन' (अंग्रेजी शीर्षक -होटल साल्वेशन) निर्देशक-शुभाशीष भूतियानी।
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**— कोंकणा सेन शर्मा, फिल्म-'ए डेथ इन द गूंज'।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**— के. कलाधरन, फिल्म-'ओट्टायाल एन पाथा' (अंग्रेजी शीर्षक-द नैरो पाथ)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**— कोंकणा सेन शर्मा, फिल्म-'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का'।
- **सर्वश्रेष्ठ पटकथा**— पी. बालाचंद्रन। (फिल्मः 'कम्मातिपाद्म')
- **सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री**— 'एन इनसिग्नीफिकेंट मैन', निर्देशक-खुशबू रांका और विनय शुक्ला।
- **सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म**— 'आबा' (ग्रैंडफादर); निर्देशक- अमर कौशिक।

विश्व स्नूकर अवॉर्ड, 2016-17

➡ लंदन में पुरस्कारों की घोषणा। (4 मई, 2017)

- **विश्व स्नूकर प्लेयर ऑफ द ईयर**— मार्क सेल्बी (यू.के.)
- **स्नूकर जर्नलिस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर**— मार्क सेल्बी (यू.के.)
- **फैन्स प्लेयर ऑफ द ईयर**— मार्क सेल्बी (यू.के.)

यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड, 2017

➡ भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा वर्ष 2017 के यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड की घोषणा। (1 मई, 2017)

➲ वर्ष 2017 के प्रमुख विजेताओं की सूची इस प्रकार है—डॉ. स्वाति अग्रवाल, डॉ. स्वेताप्रोवो चौधरी, डॉ.देबराज चौधरी, सृष्टि धर, डॉ. रिद्धि दत्ता, डॉ. सहाना होला, डॉ. रुचा किरन पाटिल, डॉ. उदय कुमार बी. रेड्डी, डॉ. अर्णब सेन, डॉ. विक्रम विशाल।

CII फाउंडेशन आदर्श महिला पुरस्कार, 2017

➡ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा CII फाउंडेशन आदर्श महिला पुरस्कार, 2017 प्रदान किया गया। (27 अप्रैल, 2017)

➲ पुरस्कृत महिलाएं एवं संबंधित क्षेत्र-

- **जयम्मा बंडारी (तेलंगाना)**— शिक्षा
- **मोनिका मजूमदार (कोलकाता)**— स्वास्थ्य
- **कमल कुम्भार (महाराष्ट्र)**— सूक्ष्म उद्यम

➡ CII प्रेसीडेंट्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-राहुल बजाज (चेयरमैन, बजाज ऑटो लि.)।

- भारतीय उद्योग महासंघ (CII) द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी।

❑ जी.डी. बिड़ला पुरस्कार, 2016

- के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु वर्ष 2016 का '26वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार' प्रो. उमेश वासुदेव वाघमारे को प्रदान किए जाने की घोषणा। (27 अप्रैल, 2017)
- प्रो. वाघमारे बंगलुरू स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई के प्रोफेसर हैं।
- इसके तहत 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

❑ मिस टीन यूनिवर्स, 2017

- मिस टीन यूनिवर्स, 2017 प्रतियोगिता का आयोजन मानागुआ (निकारागुआ) में संपन्न। (25 अप्रैल, 2017)
- **विजेता**-सृष्टि कौर (भारत)
  - प्रथम उपविजेता-सामंथा पियरे (कनाडा)
  - द्वितीय उपविजेता-ऐरी ट्रावा (मेक्सिको)
  - किसी भारतीय द्वारा यह खिताब पहली बार जीता गया है।

❑ कृषि कर्मण पुरस्कार, 2015-16

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार, 2015-16 की घोषणा। (20 अप्रैल, 2017)
- कुल खाद्यान उत्पादन की तीन श्रेणियों के विजेता राज्य-
  - **प्रथम श्रेणी** (10 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन)-तमिलनाडु
  - **द्वितीय श्रेणी** (1-10 मिलियन टन का उत्पादन)-हिमाचल प्रदेश
  - **तृतीय श्रेणी** (1 मिलियन टन से कम उत्पादन)-त्रिपुरा।

❑ छठां एमएस स्वामीनाथन अवॉर्ड, 2016

- कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉ. आर.आर. हंचिनल को। (14 अप्रैल, 2017)
  - डॉ. हंचिनल, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority) के अध्यक्ष हैं।

❑ राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार, 2016

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में प्रदान किए गए। (12 अप्रैल, 2017)
- प्रमुख पुरस्कार एवं उसकी श्रेणी–
  - **भूजल अन्वेषण**-डॉ. प्रदीप कुमार नायक
  - **खनन तकनीकी**-लक्ष्मण सिंह शेखावत, डॉ. संतोष कुमार रे
  - **धारणीय खनिज विकास**-डॉ.एबिन रेजिनाल्ड मास्तो
  - **भू-पर्यावरण अध्ययन**-डॉ. अरधि केशव कृष्ण (व्यक्तिगत)
  - **आपदा प्रबंधन**-प्रो. जावेद हुसैन एन. मलिक (व्यक्तिगत)
  - **समुद्र विकास**-डॉ. प्रतिमा मोहन केसारकर (व्यक्तिगत)
  - **युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 2016**-डॉ. अभिषेक साहा

❑ स्टॉकहोम वॉटर प्राइज, 2017

- विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा स्टॉकहोम वॉटर प्राइज की घोषणा। (22 मार्च, 2017)
  - अंतरराष्ट्रीय जल कानून को मान्यता दिलाने में योगदान प्रदान करने हेतु स्टीफेन मैक्केफ्री (अमेरिका) को।

योजना/परियोजना

❑ प्रथम कैनाल टॉप सोलर पीवी सिस्टम

- सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने महाराष्ट्र के नागपुर के निकट स्थित मौदा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (क्षमता-2320 मेगावॉट) में पॉवर स्टेशन परिसर के अंदर कूलिंग वॉटर चैनल पर भारत के पहली कैनाल टॉप सोलर पीवी सिस्टम को सक्रिय किया। (13 जून, 2017)
  - इस सौर ऊर्जा प्रणाली की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 150 किलोवॉट है।

❑ पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों हेतु **'पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम'** की घोषणा। (5 जून, 2017)
  - **उद्देश्य**-कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

❑ एकल महिला पेंशन योजना

Telangana Single
Woman Monthly
Pension Scheme

- राज्य में बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु तेलंगाना सरकार द्वारा पूरे राज्य में **एकल महिला पेंशन योजना** की शुरुआत। (4 जून, 2017)
  - इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला यह **देश का पहला राज्य** है।
  - अविवाहित महिला, जोगिनी, तलाकशुदा महिला, एसिड हमले से पीड़ित महिला, बलात्कार की शिकार महिला या किसी प्रकार से असहाय महिला, एकल पेंशन योजना के लिए पात्र होंगी जिन्हें **मानवीय आधार पर** 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

❑ टी-वॉलेट

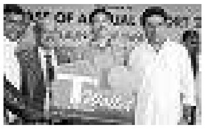

➡ तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के आधिकारिक **डिजिटल वॉलेट (ई-वॉलेट) टी-वॉलेट** का शुभारंभ। (1 जून, 2017)

➲ आधिकारिक ई-वॉलेट लांच करने वाला **तेलगांना देश का पहला राज्य** है।

➡ यह वॉलेट नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान हेतु किसी भी समय कहीं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

❑ एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप

➡ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर द्वारा एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप का नई दिल्ली में शुभारंभ। (29 मई, 2017)

➲ यह ऐप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा विकसित किया गया है।

❑ कृषि-समुद्रीय प्रसंस्करण योजना-'संपदा'

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम राज्य के धेमाजी जिले में **'कृषि-समुद्रीय प्रसंस्करण योजना- संपदा'** (SAMPADA : Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro Processing Clusters) की शुरुआत। (26 मई, 2017)

➲ **उद्देश्य**—खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

➲ इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गोगामुख (असम) में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की आधारशिला रखी।

❑ बीएसएनएल की सैटेलाइट फोन सेवा

➡ संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा द्वारा बीएसएनएल की सैटेलाइट फोन सेवा का शुभारंभ। (24 मई, 2017)

➲ प्रारंभिक चरण में यह सेवा सरकारी एजेंसियों यथा-आपदा का सामना करने वाली एजेंसियों, राज्य पुलिस, रेलवे, सीमा सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी एजेंसियों को प्रदान की जाएगी।

➡ इसी अवसर पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार योजना और पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना का भी शुभारंभ किया गया।

➲ पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 10 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

❑ सेवा ऐप

➡ केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन (SEVA: Saral Eindhan Vitaran Application) का शुभारंभ। (23 मई, 2017)

➲ **उद्देश्य**-उपभोक्ताओं से संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ कोयला प्रेषण में पारदर्शिता लाना और सरकार को अपने निर्णयों हेतु उत्तरदायी बनाना।

❑ स्वच्छ भारत ऐप

➡ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा द्वारा स्वच्छ भारत ऐप का शुभारंभ। (23 मई, 2017)

➡ **उद्देश्य**-लोगों को स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करने हेतु प्रोत्साहित करना।

❑ तेजस एक्सप्रेस

➡ भारतीय रेल द्वारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई) से कर्माली (गोवा) स्टेशन के बीच आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वातानुकूलित तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत। (22 मई, 2017)

➲ अधिकतम गति 200 किमी./घंटा है।

❑ रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधा

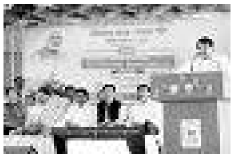

➡ रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा कोंकण रेलवे के 28 रेलवे स्टेशनों (कोलाड से मदुरई तक) पर वाई-फाई सुविधा का उद्घाटन। (21 मई, 2017)

➲ भारतीय रेलवे द्वारा इन स्टेशनों पर 24 घंटे नि:शुल्क 2 एमबीपीएस वाई-फाई इंटरनेट बैंडविड्थ सुविधा के प्रावधान हेतु मेसर्स सिस्कोन/जॉयस्टर के साथ अनुबंध किया गया है।

❑ मातृत्व लाभ कार्यक्रम

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मातृत्व लाभ कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने हेतु पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी। (17 मई, 2017)

➲ यह कार्यक्रम 1 जनवरी, 2017 से ही देश के सभी जिलों में लागू है।

➲ **उद्देश्य**-नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना, जिससे कि गर्भवती महिलाएं प्रथम जीवित बच्चे के प्रसव के पूर्व और पश्चात पर्याप्त आराम कर सकें।

❑ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

➡ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL) के पुनर्गठन को मंजूरी। (17 मई, 2017)

➡ पुनर्गठन योजना के तहत रसायनी (महाराष्ट्र) इकाई के ड्राइ-नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड (N_2O_4) संयंत्र (सामरिक महत्व) के अलावा सभी अव्यवहार्य संयंत्रों का परिचालन बंद करने का प्रस्ताव है।

➲ यह संयंत्र ड्राइ-नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड का एकमात्र स्वदेशी स्रोत है जिसका उपयोग इसरो अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों में तरल रॉकेट प्रणोदकों के रूप में करता है।

❑ टर्बो मेघा एयरवेज

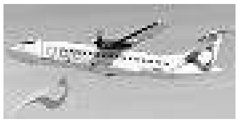

➡ हैदराबाद की टर्बो मेघा एयरवेज (Trujet) 'उड़ान' योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली निजी एयरलाइंस बनी। (17 मई, 2017)

➲ इस योजना के तहत यह एयरलाइंस कुल 128 मार्गों पर उड़ान संचालित करेगी।

➲ उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत एक घंटे की फ्लाइट का अधिकतम किराया 2500 रु. निर्धारित है।

➲ उड़ान योजना के अंतर्गत जिन पांच एयरलाइंस को उड़ान संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, वे हैं-एयर इंडिया, स्पाइसजेट, टर्बो मेघा, एयर ओडिशा एवं डेक्कन एयर।

➲ इन फ्लाइटों का संचालन एयर इंडिया के क्षेत्रीय अंग एलायंस एयर (AllianceAir) द्वारा किया जाएगा।

❑ ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल

➡ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ। (16 मई, 2017)

❑ ईपीएफओ का नागरिक चार्टर, 2017

➡ श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारू दत्तात्रेय द्वारा बंगलुरू में ईपीएफओ (EPFO-Employee's Provident Fund Organisation) के नागरिक चार्टर, 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ। (16 मई, 2017)

❑ देश की पहली स्मार्ट ग्रिड परियोजना

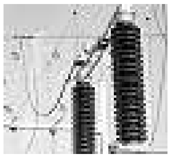

➡ भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर (हावड़ा) द्वारा देश की पहली स्मार्ट ग्रिड परियोजना सफलतापूर्वक स्थापित। (मई, 2017)

➲ यह स्मार्ट ग्रिड, सौर, वायु और सब्जियों के कचरे जैसे संसाधनों से बिजली उत्पन्न करेगी।

❑ एक्सप्रेस वाई-फाई सेवा

➡ सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी फेसबुक द्वारा भारत में एक्सप्रेस वाई-फाई सेवा की आधिकारिक घोषणा। (4 मई, 2017)

➲ भारती एयरटेल भागीदार कंपनी।

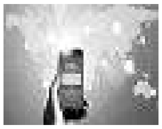

➡ इस सेवा के माध्यम से फेसबुक का लक्ष्य समाज के उन लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है जो अभी तक इससे वंचित हैं।

❑ बिजली परियोजना हेतु ऋण

➡ एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB-Asian Infrastructure Investment Bank) के निदेशक मंडल द्वारा आंध्र प्रदेश की पावर फॉर ऑल बिजली परियोजना हेतु 160 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी। (3 मई, 2017)

➲ यह किसी भारतीय परियोजना हेतु इस बैंक द्वारा प्रदत्त पहला ऋण है।

➲ **उद्देश्य**-आंध्र प्रदेश में बिजली पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।

❑ महाराजा एक्सप्रेस के दो नए सर्किट

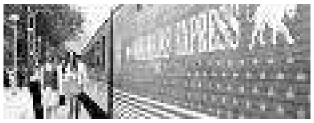

➡ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा महाराजा एक्सप्रेस (शाही रेल) के दो नए सर्किट शुरू करने का निर्णय। (2 मई, 2017)

➲ इन सर्किटों का नाम दक्षिणी सोजर्न (Southern Sojourn) और सदर्न ज्वेल्स (Southern Jewels) रखा गया है।

➲ दक्षिणी सोजर्न की नियमित यात्रा 9 सितंबर, 2017 को मुंबई से तथा दक्षिणी ज्वेल्स की 16 सितंबर, 2017 को त्रिवेंद्रम से शुरू होगी।

❑ 'तरंग संचार' वेब पोर्टल

➡ दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और ईएमएफ (EMF: Electromagnetic Fields) उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु 'तरंग संचार' नामक वेब पोर्टल की शुरुआत। (2 मई, 2017)

➲ यह पोर्टल लोगों को मोबाइल टावरों से ईएमएफ उत्सर्जन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

❑ प्रथम समुद्री रोपवे परियोजना

➡ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा भारत में समुद्र के ऊपर पहला और सबसे लंबा (लंबाई 8 किमी.) रज्जुमार्ग (Ropeway) अरब सागर में बनाया जाएगा।

➲ यह रज्जुमार्ग मुंबई के पूर्वी तट सेवरी से शुरू होगा और रायगढ़ जिले के एलीफैंटा द्वीप में समाप्त होगा।

❑ कौशल्या योजना

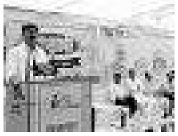

➡ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए कौशल्या योजना को मंजूरी। (18 अप्रैल, 2017)

➲ इस योजना के तहत प्रति वर्ष 2 लाख महिलाओं को परिधान, गृह सज्जा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य सेवा, टेलीकॉम, पर्यटन आदि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ऑपरेशन/अभियान

❑ मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन अभियान

➡ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा 1-13 जुलाई, 2017 के मध्य राज्य को कालाजार से मुक्त करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश। (14 जून, 2017)

➲ यह अभियान कालाजार प्रभावित चार जिलों- दुमका, गोड्डा, साहिबगंज तथा पाकुड़ में चलाया जाना है।

❑ अनुयात्रा अभियान

➡ विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए केरल सरकार के अनुयात्रा अभियान (एक सशक्तीकरण कार्यक्रम) का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा शुभारंभ। (12 जून, 2017)

➲ **उद्देश्य**-दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों को सशक्त बनाते हुए उनके प्रति सामाजिक जागरूकता लाना।

❑ समावेशी भारत पहल

➡ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय न्यास द्वारा **समावेशी भारत पहल** (Inclusive India Initiatice) का शुभारंभ। (6 जून, 2017)

➡ **उद्देश्य**-बौद्धिक और विकास संबंधी अक्षमताओं वाले दिव्यांगों को मुख्यधारा में शामिल कराना और सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं शिक्षा, रोजगार और समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

❑ 'स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ' अभियान

➡ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु **'स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ'** अभियान का शुभारंभ। (6 जून, 2017)

❑ वित्तीय साक्षरता सप्ताह

➡ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। (5-9 जून, 2017)

➲ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा।

➡ इस सप्ताह के तहत इस वर्ष चिह्नित चार संदेश हैं-अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन का उपयोग करना, डिजिटल बनाना, शिकायत समाधान तंत्र की जागरूकता आदि।

❑ 'दरवाजा बंद' अभियान

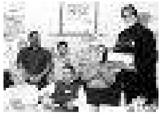

➡ केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए **सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन** के नेतृत्व में **'दरवाजा बंद'** अभियान का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया। (30 मई, 2017)

➲ **उद्देश्य**- ऐसे लोग जिनके घरों में शौचालय है, फिर भी वे इसका इस्तेमाल नहीं करते, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना।

➲ इस अभियान में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा महिलाओं को इस मुद्दे के बारे में आगे बढ़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगी।

❑ 'मलिन बस्ती को गोद लेना' संबंधी अभियान

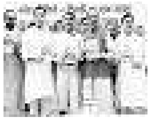

➡ केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विजय गोयल द्वारा केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'मलिन बस्ती को गोद लेना' संबंधी अभियान का शुभारंभ। (24 मई, 2017)

➲ अभियान के अंतर्गत विजय गोयल ने तिमारपुर क्षेत्र की इंदिरा बस्ती को गोद लिया।

➲ 26 मई, 2017 को इस अभियान के मद्देनजर **'स्लम युवा दौड़' दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित हुई।**

❑ ऑपरेशन गर्म हवा

➡ सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए जैसलमेर (राजस्थान) में **'ऑपरेशन गर्म हवा'** संपन्न। (15-23 मई, 2017)

➲ **उद्देश्य**-गर्मी के दिनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाना तथा सीमापार से होने वाली घुसपैठ को रोकना।

❑ सिम्बेक्स, 2017

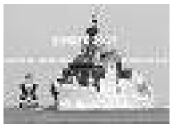

➡ भारत एवं सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक नौसैन्य अभ्यास 'सिम्बेक्स (SIMBEX) 2017' के 24वें संस्करण (हार्बर एवं समुद्री चरण) का आयोजन दक्षिण चीन सागर में संपन्न। (18-24 मई, 2017)

  - ज्ञातव्य है कि 'सिम्बेक्स' के 23वें संस्करण का आयोजन 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2016 के मध्य बंगाल की खाड़ी में किया गया था।

❑ कॉरपैट, 2017

- भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य **'29वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित निगरानी (India-Indonesia CORPAT) द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास'** संपन्न। (9-25 मई, 2017)
  - इसका उद्घाटन अंडमान एवं निकोबार कमांड के अधीन पोर्ट ब्लेयर (भारत) में किया गया जबकि समापन समारोह बेलावन (इंडोनेशिया) में आयोजित हुआ।

India - Indonesia Joint Patrol
CORPAT

❑ 'विजन जीरो' अभियान

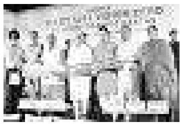

- हरियाणा सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए 'विजन जीरो' अभियान का शुभारंभ। (2 मई, 2017)
- इस प्रकार का अभियान शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
  - अभियान के पहले चरण में गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, सोनीपत और अंबाला सहित 10 जिले शामिल।

❑ विद्या वीरता अभियान

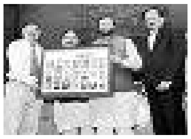

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई दिल्ली में **'विद्या वीरता अभियान'** का शुभारंभ। (2 मई, 2017)
  - **उद्देश्य**-विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना।
- इस अभियान के जरिए देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में **'वीरता की दीवार'** बनाई जाएगी, जिस पर सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के पोर्ट्रेट लगाए जाएंगे।

❑ सॉल्व फॉर इंडिया पहल

Google for
INDIA

- गूगल द्वारा एक नए कार्यक्रम 'सॉल्व फॉर इंडिया' (Solve for India) पहल की घोषणा। (28 अप्रैल, 2017)
  - **उद्देश्य**-पूरे देश में टियर-2 शहरों में नव उद्यम (Startup) पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित और सक्रिय करना तथा उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

❑ मस्तिष्क ज्वर/जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन हेतु विशेष टीकाकरण अभियान

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद कुशीनगर के ग्राम मैनपुर (बीनापट्टी) में शुभारंभ। (25 मई, 2017)
- अभियान के तहत 1-15 वर्ष की आयु वर्ग के 90 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित।

आयोग/समिति

❑ हर्ष मल्होत्रा समिति

- स्काउट्स एंड गाइड्स पर **हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय उच्च समिति** ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विजय गोयल को सौंपी। (22 मई, 2017)
  - समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स तथा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स में सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो निम्न हैं-
    - (i) इन संस्थाओं के लिए एक स्थायी निगरानी समिति होनी चाहिए जो समय-समय पर दोनों संस्थाओं की निगरानी करे और मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
    - (ii) इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में सरकारी नामित प्रतिनिधि होने चाहिए।
    - (iii) स्काउट मूवमेंट युवा आंदोलन का एक हिस्सा होना चाहिए जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है।
- ज्ञातव्य है कि मंत्रालय ने अक्टूबर, 2016 में इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।

❑ माधव चिताले समिति

- गंगा से गाद/तलछट निकालने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु **'राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण'** (NGRBA) के विशेष **सदस्य माधव चिताले** की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपी। (19 मई, 2017)
  - ज्ञातव्य है कि मंत्रालय ने जुलाई, 2016 में भीमगौड़ा (उत्तराखंड) से फरक्का (पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी की गाद निकालने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था।

❑ माधबी पुरी बुच समिति

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा साइबर सुरक्षा के विषय पर सेबी की पूर्णकालिक सदस्य **माधबी पुरी बुच की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल गठित**। (2 मई, 2017)
- पैनल सेबी और पूरे पूंजी बाजार के लिए साइबर सुरक्षा पर नजर रखने और उसके बारे में समग्र मार्गदर्शन करेगा।

सम्मेलन/समारोह

❑ द्वितीय ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, 2017

➡ 23-27 जून के मध्य 'द्वितीय ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, 2017' दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत चेंगदू में संपन्न।

➲ **'व्हेयर हैज़ टाइम गॉन'** महोत्सव की शुभारंभ फिल्म थी।

➲ यह पांच अलग-अलग कहानियों पर बनी थी, जिसे पांचों ब्रिक्स देशों के निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया गया था। इस प्रकार यह ब्रिक्स सह-निर्माण (Co-production) के रूप में बनी पहली फिल्म है।

➲ दक्षिण अफ्रीकी रोमांटिक कॉमेडी 'मिसेज राइट गाय' (Mrs. Right Guy) महोत्सव की समापन फिल्म रही।

➲ 'प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव' 2-6 सितंबर, 2016 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।

❑ प्रथम मानव संसाधन गोलमेज सम्मेलन

➡ रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा भारतीय रेलवे के प्रथम मानव संसाधन गोलमेज सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन। (8 जून, 2017)

➲ **उद्देश्य**-विभिन्न अंशधारकों, मानव संसाधन विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के बीच विचारों का आदान-प्रदान कर मानव संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाना।

❑ आठवीं स्वच्छ ऊर्जा एवं द्वितीय मिशन इनोवेशन मंत्रिस्तरीय बैठक

➡ बीजिंग, चीन में संपन्न। (7-8 जून, 2017)

➲ इस वार्षिक बैठक में मिशन इनोवेशन के 22 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

➡ इस अवसर पर भारत ने कुल 238 मिलियन डॉलर की लागत से स्वच्छ कोयला उपयोग के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की।

❑ वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस, 2017

➡ सिंगापुर के मकनसुत्रा [Makansutra (S) Pte Ltd.] द्वारा आयोजित **'वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस** (World Street Food Congress), 2017' मॉल ऑफ एशिया, मनीला (फिलीपींस) में संपन्न। (31 मई-4 जून, 2017)

World Street Food Congress 2017
THE BIGGEST GATHERING OF HERITAGE STREET FOOD LOVERS IS HERE AGAIN

➲ **मुख्य विषय** : संभावनाओं की पुनः कल्पना (Re-Imagine Possibilities)।

❑ 19वां आर्केशिया फोरम, 2017

➡ जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित। (21-25 मई, 2017)

➲ **मुख्य विषय (Theme)**- 'आर्किटेक्चर के माध्यम से खुशी' (Happiness Through Architecture)।

➡ ध्यातव्य है कि हाल ही में जयपुर में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है तथा इस शहर को एशिया के पहले सिस्कोलाइट हाउस सिटी के रूप में चुना गया है।

❑ स्टार्ट-अप इंडिया शिखर सम्मेलन

➡ अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला स्टार्ट-अप इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित। (23-24 मई, 2017)

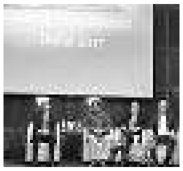

➲ सम्मेलन का आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास, दुबई और भारतीय दूतावास, अबू धाबी द्वारा आई स्पिरिट (iSPIRIT) (एक गैर-लाभकारी संगठन) की साझेदारी और टीआईई (TiE) दुबई के सहयोग से किया गया।

❑ राष्ट्रीय पुलिस मिशन : प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

➡ राष्ट्रीय पुलिस मिशन के माइक्रो मिशन का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। (23-24 मई, 2017)

➲ सम्मेलन का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय के तहत) द्वारा किया गया।

❑ आपदा जोखिम पर वैश्विक मंच की बैठक

GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION

➡ आपदा जोखिम कम करने हेतु वैश्विक मंच की बैठक कानकुन, मेक्सिको में संपन्न। (22-26 मई, 2017)

➲ यह एक ऐसा मंच है, जो आपदा जोखिम कम करने संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करता है और तत्संबंधी कार्यनीतिक परामर्श, समन्वय और भागीदारी विकास के लिए कार्य करता है।

➲ बैठक का आयोजन 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (UNISDR) द्वारा किया गया।

➲ यह पहला अवसर है जब यह बैठक जेनेवा के बाहर आयोजित की गई।

❑ आर्कटिक ऊर्जा शिखर सम्मेलन

➡ चौथा द्विवार्षिक आर्कटिक ऊर्जा शिखर सम्मेलन 18-20 सितंबर, 2017 के मध्य हेलसिंकी, फिनलैंड में आयोजित होगा।

➲ इसका **विषय**-'आर्कटिक ऊर्जा विशेषज्ञता, नवीनता और समाधान को एकजुट करना' है।

➲ इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ द नार्थ और फिनलैंड का आर्थिक एवं रोजगार मंत्रालय, संयुक्त रूप से करेंगे।

❑ चौथी एक्वा एक्वेरिया इंडिया, 2017

➡ मत्स्य और सजावटी मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को दर्शाने के लिए **'चौथी एक्वा एक्वेरिया इंडिया, 2017'** मंगलुरू, कर्नाटक में संपन्न। (14-16 मई, 2017)

➲ **मुख्य विषय-**'सतत मत्स्य पालन में विविधीकरण'।

➡ इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबद्ध समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

❑ आउटरीच कार्यक्रम 'विदेश संपर्क'

➡ तेलंगाना सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय का पहला आउटरीच कार्यक्रम 'विदेश संपर्क' आयोजित। (13 मई, 2017)

❑ संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस

➡ 12-14 मई, 2017 के मध्य 14वें संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस, 2017 का आयोजन श्रीलंका में किया गया।

➲ इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे।

➡ **मुख्य विषय-** 'सामाजिक न्याय और सतत शांति के लिए बौद्ध शिक्षा' (Buddhist Teaching for Social Justice and Sustainable Peace)।

➲ ध्यातव्य है कि वैशाख दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा उनके महापरिनिर्वाण के संदर्भ में मनाया जाता है।

❑ 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्माकल्चर कन्वर्जेंस, 2017

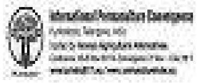

➡ 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्माकल्चर कन्वर्जेंस, 2017 का आयोजन मेडक, तेलंगाना में किया जाएगा। (27 नवंबर, 2017 से 2 दिसंबर, 2017 के मध्य)

➡ **मुख्य विषय-** 'स्वस्थ समाज की ओर' (Towards Healthy Societies)।

➲ इसका आयोजन हैदराबाद स्थित पर्यावरण और विकास एनजीओ अरन्या एग्रीकल्चरल आल्टर्नेटिक्स, अंतरराष्ट्रीय पर्माकल्चर काउंसिल (IPCC) और फ्रेंड्स ऑफ आईपीसी (FIPC) संयुक्त रूप से करेंगे।

❑ सीएसआर मेला

➡ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) मेला संपन्न। (4-6 मई, 2017)

➲ मेले का आयोजन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग एवं पीएचडी चैंबर द्वारा ओएनजीसी के सहयोग से किया गया।

❑ वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन

➡ नई दिल्ली में संपन्न। (3-4 मई, 2017)

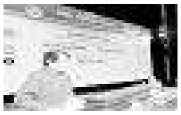

➲ इस सम्मेलन का मुख्य फोकस चार प्रमुख क्षेत्रों-सुरक्षा, विश्वसनीयता, क्षमता वृद्धि और ग्राहक सेवा पर केंद्रित था।

➲ सम्मेलन का आयोजन भारतीय रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ द्वारा किया गया।

❑ पंचायती राज सम्मेलन

➡ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित। (24 अप्रैल, 2017)

➲ **मुख्य विषय-** 'स्मार्ट गांव से बनेगा नया भारत'।

➡ इसका आयोजन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

➲ इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'ग्रामोदय संकल्प' का विमोचन और मोबाइल ऐप ग्रामोदय संकल्प तथा यू ट्यूब चैनल का शुभारंभ किया।

➡ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के पोर्टल 'पंचायत मित्र' का शुभारंभ किया।

संधि/समझौता

❑ आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में समझौता

➡ सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के मध्य तेल रिफाइनरी स्थापित करने हेतु समझौता। (14 जून, 2017)

➲ समझौते के तहत 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के निवेश से विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक रिफाइनरी महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के बाबुलवाडी में स्थापित की जाएगी।

➲ रिफाइनरी की क्षमता 60 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक होगी।

❑ अंतर्राज्यीय परिवहन समझौता

➡ उ.प्र. और राजस्थान राज्य के बीच यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर। (13 जून, 2017)

➲ इस समझौते से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के अनेक शहर सीधी बस सेवाओं से जुड़ जाएंगे।

भारत-सोमालिया समझौता

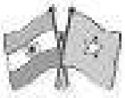

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **भारत और सोमालिया के बीच सजायाफ्ता लोगों के प्रत्यर्पण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर** करने और बाद में उसे अनुमोदित करने को मंजूरी। (7 जून, 2017)

सेबी और एसईओ के मध्य समझौता

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **प्रतिभूति बाजारों से संबंधित मुद्दों पर परस्पर सहयोग** को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा ईरान के प्रतिभूति एवं विनिमय संगठन (SEO) के बीच समझौता-ज्ञापन को अनुमति। (7 जून, 2017)

सैमसंग इंडिया और एमएसएमई मंत्रालय के मध्य समझौता

- समझौते के तहत बंगलुरू और जमशेदपुर में दो नए प्रौद्योगिकी स्कूल (MSME-Samsung Technical Schools) खोलने तथा देश में संचालित 10 वर्तमान स्कूलों के संचालन हेतु भागीदारी का नवीनीकरण किया गया। (2 जून, 2017)
    - इस अवसर पर सैमसंग इंडिया (कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी) ने एमएसएमई-सैमसंग तकनीकी स्कूल छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की।
    - इस कार्यक्रम के तहत 1000 लड़कियों और दिव्यांग प्रशिक्षुओं को प्राथमिक प्रशिक्षण के पश्चात 20,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

भारत-विश्व बैंक समझौता

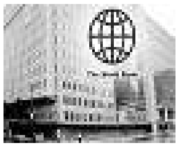

- **'हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम'** हेतु भारत द्वारा 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर। (31 मई, 2017)
    - **उद्देश्य**-हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और कर प्रशासन व्यवस्था की दक्षता में सुधार करना।

एडीबी और पंजाब नेशनल बैंक में समझौता

- **एशियाई विकास बैंक (ADB) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच 100 मिलियन डॉलर राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर।** (30 मई, 2017)
    - इस राशि की गारंटर भारत सरकार है।
- इस ऋण के माध्यम से पूरे देश में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भवनों पर लगाई जाने वाली विशाल सौर छत प्रणालियों का वित्त पोषण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार और सुंग हा टेलीकॉम के मध्य समझौता

- दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर। (30 मई, 2017)
    - समझौते के तहत दक्षिण कोरियाई कंपनी छत्तीसगढ़ में मोबाइल फोन उपकरणों के निर्माण हेतु 120 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से उद्योग स्थापित करेगी।
- वर्ष 2018 में इस उद्योग के शुरू होने की संभावना है।

राज्य आनंद संस्थान और आईआईटी, खड़गपुर के मध्य समझौता

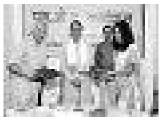

- मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंद संस्थान एवं आईआईटी, खड़गपुर के रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बीच राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स मापने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (मई, 2017)
    - राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर राज्य हैप्पीनेस इंडेक्स आईआईटी, खड़गपुर द्वारा तैयार किया जाएगा।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 155 देशों में 122वां स्थान है।

बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर

- कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। (17 मई, 2017)
    - यह कन्वेंशन ओईसीडी/जी-20 बीईपीएस परियोजना का हिस्सा है।

OECD/G20 BEPS PROJECT

- इसका लक्ष्य कर नियोजन रणनीतियों के माध्यम से ऐसे कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण से निपटना है, जो कर नियमों में अंतर और असंतुलन का लाभ उठाते हुए कृत्रिम रूप से लाभ को ऐसे कम कर या कर रहित देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां आर्थिक गतिविधियां नहीं होती या न के बराबर होती हैं।

एनडीसी, नई दिल्ली और एनडीसी, ढाका के मध्य समझौता

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ढाका (बांग्लादेश) के बीच फैकल्टी आदान-प्रदान के समझौते को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी। (17 मई, 2017)
    - **उद्देश्य**-राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों के बीच नियमित आदान-प्रदान कार्यक्रमों को स्थापित करना और इनके बीच संतुलन बनाना।

❑ भारतीय नौसेना एवं एसएसी, अहमदाबाद के मध्य समझौता

➡ भारतीय नौसेना एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के मध्य मौसम विज्ञान एवं सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में डाटा साझा करने एवं वैज्ञानिक सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (15 मई, 2017)

- ➲ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद (गुजरात) की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी।

❑ एनएचएआई और टिडको के मध्य समझौता

➡ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (TIDCO) के मध्य नई दिल्ली में एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर। (15 मई, 2017)

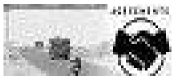

- ➲ इस समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तमिलनाडु में कामराज बंदरगाह के निकट पोन्नेरी औद्योगिक नोड क्षेत्र में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा।

❑ डीआईपीपी और विपो में समझौता

➡ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization : WIPO) के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र (TISC) स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर। (8 मई, 2017)

संघ/संगठन

❑ वात्सल्य मातृ अमृत कोष

➡ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में **'वात्सल्य मातृ अमृत कोष'** का उद्घाटन। (7 जून, 2017)

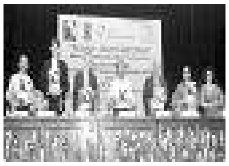

- ➲ यह संपूर्ण उत्तर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र होगा।

➡ इस कोष की स्थापना नॉर्वे की सरकार, ओस्लो विश्वविद्यालय और नॉर्वे इंडिया पार्टनर इनीशिएटिव (NIPI) के सहयोग से हुई है।

❑ एफआईपीबी को समाप्त करने को मंजूरी

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB)** को समाप्त करने को मंजूरी। (24 मई, 2017)

- ➲ इसके बाद, एफडीआई के लिए आवेदनों के प्रक्रिया संबंधी कार्य, FDI नीति एवं फेमा के तहत सरकार की मंजूरी आदि को अब वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाया जाएगा।

❑ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

➡ केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को निजी क्षेत्र के रक्षा उपकरण निर्माताओं को लाइसेंस जारी करने की अनुमति। (19 मई, 2017)

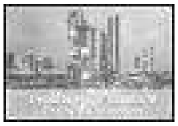

- ➲ यद्यपि संभावित निर्माताओं को यह लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी और नियंत्रण के तहत ही प्रदान किए जाएंगे।

➡ इससे पूर्व लाइसेंस जारी करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास था।

❑ संयुक्त राष्ट्र के चुनाव सहायता कार्यक्रम में योगदान

➡ भारत द्वारा 2,50,000 डॉलर का योगदान। (18 अप्रैल, 2017)

- ➲ चुनावी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए 250,000 डॉलर का यह दूसरा (इससे पूर्व 2012 में)भारतीय योगदान है।
- ➲ वर्ष 1991 में स्थापित चुनाव सहायता प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने 100 से अधिक देशों के चुनावों में सहायता की है।

❑ भारतीय यकृत और पाचन विज्ञान संस्थान

➡ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सोनारपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 'भारतीय यकृत और पाचन विज्ञान संस्थान' (Indian Institute of Liver and Digestive Sciences) का उद्घाटन। (18 मई, 2017)

❑ टाटा स्टार कार्ड

➡ 'टाटा कैपिटल' और 'एसबीआई कार्ड' द्वारा मल्टी-फॉर्मेट ग्रॉसरी रिटेल चेन **'स्टार बाजार'** की साझेदारी में एक अनोखा क्रेडिट कार्ड **'टाटा स्टार कार्ड'** लांच करने की घोषणा। (15 मई, 2017)

- ➲ यह कार्ड मुख्यत: ऐसे ग्राहक वर्ग की बढ़ती मांगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्राय: संगठित रिटेल स्टोर्स से ग्रॉसरी/डिपार्टमेंटल श्रेणी की वस्तुएं खरीदते हैं।
- ➲ इस कार्ड को दो वैरिएंट्स **प्लैटिनम** और **टाइटेनियम** में पेश किया गया है।

विधि/न्याय

❑ उ.प्र. जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017

➡ उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खनन प्रक्रिया से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के विकास हेतु 'जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017' प्रख्यापित करने को मंजूरी। (2 मई, 2017)

➲ इस मंजूरी के तहत जिला खनिज फाउंडेशन की निधि के 60 प्रतिशत फंड का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा-पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, स्वच्छता एवं कौशल विकास आदि पर खर्च किया जाएगा।

➲ इसके अलावा 40 प्रतिशत फंड अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा-भौतिक संरक्षण, सिंचाई आदि पर व्यय होगा।

वर्ष/दिवस

❑ विश्व महासागर दिवस

➡ **तिथि**-8 जून, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'हमारे महासागर, हमारा भविष्य' (Our Oceans, Our Future) ।

❑ विश्व पर्यावरण दिवस

➡ **तिथि**-5 जून, 2017

World Environment Day
Connecting People to Nature

➲ **मुख्य विषय**-'लोगों को प्रकृति से जोड़ना' (Connecting People to Nature)।

➡ इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कनाडा को दी गई थी।

❑ विश्व तंबाकू निषेध दिवस

➡ **तिथि**-31 मई, 2017

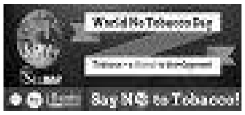

➲ **मुख्य विषय**-'तंबाकू-विकास के लिए खतरा' (Tobacco- A Threat to Development)।

❑ संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस

➡ **तिथि**-29 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'संपूर्ण विश्व में शांति में निवेश' (Investing in Peace Around the World)।

❑ विश्व कछुआ दिवस

➡ **तिथि**-23 मई, 2017

➲ यह दिवस कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है।

❑ अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस

➡ **तिथि**-22 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'जैव-विविधता और सतत पर्यटन' (Biodiversity and Sustainable Tourism)।

❑ आतंकवाद निरोधक दिवस

➡ **तिथि**-21 मई, 2017

➡ उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी आतंकवाद के नापाक मंसूबों का शिकार बने थे।

❑ विश्व मापविज्ञान दिवस

➡ **तिथि**-20 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'परिवहन के लिए माप' (Measurements for Transport)।

❑ विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस

➡ **तिथि**-17 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'बड़े प्रभाव के लिए बड़े आंकड़े' (Big Data for Big Impact)।

❑ अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस

➡ **तिथि**-15 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'परिवार, शिक्षा और कल्याण' (Families, Education and Well-being)।

❑ अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस

➡ **तिथि**-12 मई, 2017

➲ **मुख्य विषय**-'नर्स : सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक नेतृत्वकर्ता का स्वर' (Nurses : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals)।

❑ विश्व थैलेसीमिया दिवस

➡ **तिथि**-8 मई, 2017

World Thalassemia Day
8th May

➲ **मुख्य विषय**-'आइए जुड़ें : ज्ञान और अनुभव साझा करें और थैलेसीमिया में बेहतर कल के लिए लड़ें' (Get Connected : Share Knowledge and experience and fight for a better tomorrow in thalassaemia)।

❑ विश्व अस्थमा दिवस

➡ **तिथि**-2 मई, 2017 (मई महीने के प्रथम मंगलवार को)

➲ **मुख्य विषय**-'अस्थमा : बेहतर वायु, बेहतर श्वसन' (Asthma : Better Air, Better Breathing)।

अन्य प्रमुख वर्ष/दिवस

- **विश्व दुग्ध दिवस** – 1 जून, 2017
- **हिंदी पत्रकारिता दिवस**– 30 मई, 2017
- **अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस**– 18 मई, 2017
- **राष्ट्रीय डेंगू दिवस**– 16 मई, 2017
- **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस**– 11 मई, 2017
- **विश्व लूपस दिवस**– 10 मई, 2017
- **विश्व रेडक्रॉस दिवस**– 8 मई, 2017
- **विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस**– 3 मई, 2017
- **गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस**– 2 मई, 2017
- **अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस**– 1 मई, 2017

पुस्तकें

- **मन की बातः रेडियो पर सामाजिक क्रांति**- राजेश जैन
- **मार्चिंग विद ए बिलियनः एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट ऐट मिड टर्म**- उदय माहुरकर
- **कन्फेशंस ऑफ ए डाईंग माइंडः द ब्लाइंड फेथ ऑफ एथिइज्म**- हैलिआनलाल गाइट
- **इंदिरा गांधीः ए लाइफ इन नेचर**— जयराम रमेश
- **ए हार्स वाक्स इनटू ए बार**— डेविड ग्रासमैन
- **एडल्ट्स इन द रूमः माई बैटल विथ यूरोप'स डीप एस्टेब्लिशमेंट**— यानिस वैरोफैकिस
- **एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटः एस्सेज ऑन ए चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी**— दीपक नैयर
- **इंडिया'ज कोल स्टोरीः फ्रॉम दामोदर टू जाम्बेजी**— सुभोमॉय भट्टाचार्य
- **द वैनिशिंगः इंडिया'ज वाइल्डलाइफ क्राइसिस**— प्रेरणा सिंह
- **इन द नेम ऑफ गॉड**— रवि सुब्रमणियन
- **द हैंडमेड'स टेल**— मार्गरेट एटवुड
- **बैंकोक्रेसी**— इरिक टोसेंट
- **नो फ्री लेफ्टः द फ्युचर्स ऑफ इंडियन कम्युनिज्म**— विजय प्रसाद
- **साइंस एंड कंजरवेशन ऑफ वाइल्डलाइफ पॉपुलेशन**— के. उल्लास करांथ
- **ट्रंपः द आर्ट ऑफ द डील**— डोनाल्ड जे. ट्रंप और टोनी श्वार्ट्ज
- **ट्रंपः हाउ टू गेट रिच**— डोनाल्ड जे. ट्रंप एवं मेरेदिथ मेक्लेवर
- **थिंक बिगः मेक इट हैपेन इन बिजनेस एंड लाइफ**— डोनाल्ड जे. ट्रंप एवं बिल जैंकर
- **द वार इज इन द माउंटेंस**— जुडिथ मैटलॉफ
- **हाफ गर्लफ्रेंड**— चेतन भगत
- **द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस**— अरुंधति रॉय
- **टू सेंट्सः स्पेक्युलेशंस एराउंड एंड एबाउट रामकृष्ण परमहंस एंड रामना महाऋषि**— अरुण शौरी
- **द बाबा रामदेव फेनोमेननः फ्रॉम मोक्ष टू मार्केट**— कौशिक डेका
- **लोन फॉक्स डांसिंगः माई ऑटोबायोग्राफी**— रस्किन बांड

विविध

❑ उच्चतम भुगतान पाने वाली 100 मशहूर हस्तियों की सूची, 2017

➡ प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा' **विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली 100 मशहूर हस्तियों'** (The World's 100 Highest-Paid Celebrities) की सूची, 2017 जारी। (12 जून, 2017)

➡ **सूची में शीर्ष 3 हस्तियां**-(i) प्रसिद्ध अमेरिकी रैपर और उद्योगपति सीन कॉम्ब्स (130 मिलियन अमेरिकी डॉलर), (ii) प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका **बियॉन्से नोल्स** (105 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जे.के. रॉलिंग (95 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

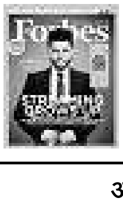

➡ सूची में भारत से शामिल तीन मशहूर हस्तियां-(i) बॉलीवुड अभिनेता **शाहरुख खान** (38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को 65वां स्थान। (ii) बॉलीवुड अभिनेता **सलमान खान** (37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को 71वां स्थान तथा (iii) बॉलीवुड अभिनेता **अक्षय कुमार** (35.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को 80वां स्थान।

❑ क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग, 2018

➡ इस रैंकिंग में 84 देशों के लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। (8 जून, 2017 को जारी)

- ➲ **रैंकिंग में विश्व के शीर्ष चार विश्वविद्यालय**— (i) मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (MIT), अमेरिका, (ii) स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, (iii) हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, तथा (iv) कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अमेरिका।

➡ क्यूएस (Qs-Quacquarelli Symonds) विश्वविद्यालय रैंकिंग, 2018 में भारत के तीन संस्थानों को विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त हुआ।

- ➲ आईआईटी, दिल्ली को 172वां, आईआईटी, बॉम्बे को 179वां तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू को 190वां स्थान प्राप्त।

❑ उच्चतम भुगतान पाने वाले 100 एथलीटों की सूची, 2017

➡ प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका **'फोर्ब्स' द्वारा 'विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले 100 एथलीटों'** (The World's 100 Highest Paid Athletes) की सूची, 2017 जारी। (8 जून, 2017)

- ➲ सूची में शामिल शीर्ष 3 एथलीट हैं-(i) **क्रिस्टियानो रोनाल्डो** (93 मिलियन अमेरिकी डॉलर), (ii) **लेब्रॉन जेम्स** (86.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा (iii) **लियोनेल मेसी** (80 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

➡ **भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (22 मिलियन अमेरिकी डॉलर)** ब्रिटेन के मुक्केबाज एंथोनी जोशुआ के साथ इस सूची में संयुक्त रूप से 89वें स्थान पर रहे।

❑ एंबुसेंस

➡ **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), खड़गपुर** द्वारा एम्बुलेंस में लाए जा रहे मरीजों की स्थिति पर दूर से निगरानी रखने हेतु वायरलेस प्रौद्योगिकी 'एंबुसेंस' (AmbuSens) विकसित। (जून, 2017)

- ➲ यह विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के मानदंडों यथा-ईसीजी, हृदय की धड़कन, तापमान और रक्तचाप पर वायरलेस के माध्यम से निगरानी रखने में सक्षम है।

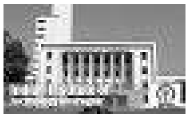

❑ जापान : राजा को पद त्याग की मंजूरी

➡ जापान की संसद के उच्च सदन द्वारा जापानी राजा को पद त्याग की अनुमति देने वाले वाले विधेयक को मंजूरी। (7 जून, 2017)

- ➲ इससे पूर्व 2 जून को निचले सदन तथा मई, 2017 में जापान की कैबिनेट द्वारा राजा को पद त्याग की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई थी।

➡ दिसंबर, 2018 में राजा अकिहितो द्वारा पद त्याग करने का अनुमान है।

❑ एलएनजी निर्यात को मंजूरी

➡ अमेरिका द्वारा एक अपतटीय परियोजना से **प्राकृतिक तरल गैस (LNG) के निर्यात हेतु दीर्घावधि आवेदन को अनुमति।** (1 जून, 2017)

➲ यह परियोजना मेक्सिको की खाड़ी में एक भारतीय और अमेरिकी कंपनी का संयुक्त उपक्रम है।

➲ इसके तहत डेलफिन एलएनजी (Delfin LNG's) के प्रस्तावित लुईसियाना फ्लोटिंग टर्मिनल से 1.8 बिलियन घन फुट प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस निर्यात की अनुमति दी गई है।

❑ पं. दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी

➡ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में पं. दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन। (26 मई, 2017)

➲ प्रदर्शनी का विषय-**'सबका साथ, सबका विकास'** था।

❑ दिव्यांगजन भरण-पोषण योजना

➡ उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन भरण-पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि में वृद्धि करने का निर्णय। (23 मई, 2017)

➲ मासिक अनुदान राशि को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया।

➡ इसके अलावा ऐसे दिव्यांगजन, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना से आच्छादित हैं और केंद्रीय योजना से अनुदान राशि प्राप्त कर रहें हैं, उनकी भी अनुदान राशि में वृद्धि करके 500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया।

❑ नर्मदा नदी में रेत खनन पर प्रतिबंध

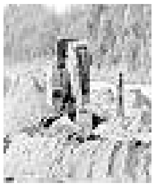

➡ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा। (22 मई, 2017)

➲ इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नदी खनन पर वैज्ञानिक सुझाव हेतु कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जो नदी को नुकसान पहुंचाए बिना रेत खुदाई के तरीके तलाशने से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

❑ रोबोकॉप

➡ दुबई पुलिस द्वारा विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी 'रोबोकॉप' पुलिस बल में शामिल। (21 मई, 2017)

➲ अरबी, अंग्रेजी के अलावा यह 6 प्रकार की भाषाओं से परिचित है।

➲ दुबई प्रशासन की योजना वर्ष 2030 तक पुलिस बल में 25 प्रतिशत रोबोट शामिल करने की है।

❑ भारत का पहला सफल गर्भाशय प्रत्योरापण

➡ डॉ. शैलेश पुन्तांबेकर के नेतृत्व में डॉक्टरों के एक दल द्वारा गैलेक्सी केयर लैप्रोस्कोपी इंस्टीट्यूट, पुणे में 21 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक गर्भाशय प्रत्योरापण। (18 मई, 2017)

➲ इस महिला हेतु गर्भाशय उसकी मां ने दान किया।

❑ हेलीकॉप्टर सौदा निरस्त

➡ भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा अमेरिका से नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले 16 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों का सौदा निरस्त। (14 जून, 2017)

➲ भारतीय नौसेना हेतु हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए यह समझौता अमेरिकी कंपनी सिकोर्स्की से हुआ था।

➡ सौदे की राशि 6500 करोड़ रुपये थी।

❑ यूगोंग-1

➡ बीजिंग के एरोनॉटिक्स एवं एस्ट्रोनॉटिक्स अनुसंधान विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा चंद्रमा के समान वातावरण प्रदान करने हेतु 'यूगोंग-1' (YUEGONG-1) या लूनर पैलेस (Lunar Palace) नामक प्रयोगशाला स्थापित। (12 मई, 2017)

➲ 160 वर्ग मीटर (1720 वर्ग फुट) की इस प्रयोगशाला में छात्रों को 200 दिनों तक चंद्रमा पर रहने योग्य वातावरण प्रदान किया जाएगा।

➡ यह प्रयोगशाला विश्व की तीसरी एवं चीन द्वारा निर्मित पहली बायोरिजेनेरेटिव लाइफ सपोर्ट बेस प्रयोगशाला है।

❑ एनएचएआई मसाला बांड का शुभारंभ

➡ सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** (NHAI) के **मसाला बांड** इश्यू का शुभारंभ। (11 मई, 2017)

➲ यह मसाला बांड इश्यू 1500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया गया।

➲ बाद में निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दी गई।

❑ एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उच्चतम न्यायालय की एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ। (10 मई, 2017)

❑ उत्तर प्रदेश में 2 नए नगर निगम

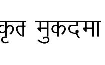

➡ उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा नगरपालिका परिषद मथुरा एवं नगरपालिका परिषद वृंदावन को मिलाकर **'नगर निगम मथुरा-वृंदावन'** के गठन का निर्णय। (9 मई, 2017)

➲ इसके अलावा नगरपालिका परिषद अयोध्या एवं नगरपालिका परिषद, फैजाबाद को मिलाकर **'नगर निगम अयोध्या'** बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

खेल परिदृश्य

क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों का विवरण

टेनिस

❑ फ्रेंच ओपन

➡ पेरिस, फ्रांस में संपन्न (28 मई - 11 जून, 2017)।

➡ इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता (वर्ष की दूसरी) के परिणाम इस प्रकार रहे-

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - राफेल नडाल (स्पेन)

उपविजेता - स्टेनिस्लास वावरिंका (स्विट्जरलैंड)

➲ **महिला एकल**

विजेता- जेलेना ओस्टापेंको (लाटविया)

उपविजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - रेयान हैरिसन (अमेरिका) एवं **माइकल वीनस** (न्यूजीलैंड)

उपविजेता - सैंटियागो गोंजालेज (मेक्सिको) एवं डोनाल्ड यंग (अमेरिका)

➲ **महिला युगल**

विजेता - बेथनी माटेक सैंड्स (अमेरिका) एवं **लूसी साफारोवा** (चेक गणराज्य)

उपविजेता - एशले बार्टी एवं केसी डेलाकुआ (दोनों ऑस्ट्रेलिया)

➲ **मिश्रित युगल**

विजेता - गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) एवं **रोहन बोपन्ना** (भारत)

उपविजेता - एना-लिना ग्रोनफेल्ड (जर्मनी) एवं रॉबर्ट फराह (कोलंबिया)

➡ यह नडाल का 10वां फ्रेंच ओपन एवं कुल 15 वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था।

➲ नडाल एक ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दस खिताब जीतने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी बने।

➡ जेलेना ओस्टापेंको कोई ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली लाटविया की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गईं।

➡ साथ ही वह 1933 के बाद से यह खिताब जीतने वाली पहली गैर-वरीय (Unseeded) महिला खिलाड़ी भी हैं।

➡ यह बोपन्ना का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है।

➡ लिएंडर पेस, महेश भूपति एवं सानिया मिर्जा के बाद यह कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय हैं।

❑ रोम मास्टर्स टूर्नामेंट, 2017

➡ इटली मे संपन्न। (15-21 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - अलेक्जेंडर ज्वेरेव (जर्मनी)

उपविजेता - नोवाक जोकोविक (सर्बिया)

➲ **महिला एकल**

विजेता - एलीना स्विटोलिना (यूक्रेन)

उपविजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

❑ मुटुआ मैड्रिड ओपन, 2017

➡ मैड्रिड (स्पेन) में संपन्न। (5-14 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - राफेल नडाल (स्पेन)

उपविजेता - डॉमिनिक थिएम (ऑस्ट्रिया)

➲ **महिला एकल**

विजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

उपविजेता - क्रिस्टिना म्लाडेनोविक (फ्रांस)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - लुकॉस कुबोत (पोलैंड) एवं मार्सेलो मेलो (ब्राजील)

उपविजेता - निकोलस माहुत एवं एडुअर्ड रोजर-वेसेलिन (दोनों फ्रांस)

➲ **महिला युगल**

विजेता - मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड) एवं युंग-जन चान (चीनी ताइपे)

उपविजेता - तिमेया बाबोस (हंगरी) एवं एंड्रिया हलावकोवा (चेक गणराज्य)

❑ TEB BNP परिबास इस्तांबुल ओपन

➡ इस्तांबुल, तुर्की में संपन्न। (1-7 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - मारिन सिलिक (क्रोएशिया)

उपविजेता - मिलोस राओनिक (कनाडा)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - रोमन जेब्ी एवं **जिरि वेस्ले** (दोनों चेक गणराज्य)

उपविजेता - तुना अल्तुना (तुर्की) एवं एलेसांद्रो मोट्टी (इटली)

❑ BNP परिबास प्रिमरोज, 2017

➡ ATP चैलेंजर टूर प्रतियोगिता।

➲ बोर्दो, फ्रांस में संपन्न। (15-21 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - स्टीव डार्किस (बेल्जियम)

उपविजेता - रोजेरियो दुत्रा सिल्वा (ब्राजील)

➲ **पुरुष युगल**

विजेता - पूरव राजा एवं दिविज शरण (दोनों भारत)

उपविजेता - सैंटियागो गोंजालेज (मेक्सिको) एवं अर्टेम सिताक (न्यूजीलैंड)

क्रिकेट

❑ ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2017

➡ 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद' (ICC) द्वारा प्रशासित 8वां **'चैंपियंस ट्रॉफी'** टूर्नामेंट 1 से 18 जून, 2017 के मध्य इंग्लैंड एवं वेल्स की मेजबानी में संपन्न।

➲ राउंड रॉबिन एवं नॉक आउट प्रारूप के इस एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में ICC के शीर्ष 8 सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया था।

ग्रुप A - इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड।

ग्रुप B - भारत, पाकिस्तान, द.अफ्रीका एवं श्रीलंका।

➲ **वेस्टइंडीज** क्रिकेट टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाई।

➲ 18 जून, 2017 को द ओवल क्रिकेट ग्राउंड (लंदन) में खेले गए फाइनल में **पाकिस्तान** ने भारत को 180 रनों से पराजित कर यह टूर्नामेंट जीत लिया।

➲ पाकिस्तान की टीम के कप्तान सरफराज अहमद एवं भारत के कप्तान विराट कोहली थे।

➲ फाइनल में सर्वाधिक 114 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज **फखर जमान** को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

➲ टूर्नामेंट में प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार रहे-

'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' - हसन अली (पाकिस्तान)

'गोल्डेन बॉल' - हसन अली (पाकिस्तान), सर्वाधिक 13 विकेट।

'गोल्डेन बैट' - शिखर धवन (भारत), सर्वाधिक 338 रन।

➲ पाकिस्तान की 180 रनों की जीत ICC के किसी भी एकदिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल में जीत का सर्वाधिक अंतर (Margin) है।

➲ इससे पूर्व वर्ष 2003 में ICC के विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों के अंतर से पराजित किया था।

➲ पाकिस्तान द्वारा बनाए गए 338 रन ICC के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा उच्चतम स्कोर है।

➲ इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2007 के विश्व कप के फाइनल में भारत के विरुद्ध 359 रन बनाए थे।

➲ **फखर जमान** का शतक (114 रन) ICC विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किसी पाकिस्तानी द्वारा बनाया गया पहला शतक है।

➲ 19 जून, 2017 को ICC द्वारा घोषित वर्ष 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का कप्तान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को चुना गया।

➲ इस टीम में शामिल 3 भारतीय हैं- **शिखर धवन, विराट कोहली एवं भुवनेश्वर कुमार**।

➲ न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन को टीम का 12वां खिलाड़ी चुना गया है।

❑ IPL-10 ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट

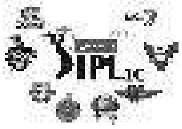

➡ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा प्रशासित **10वां IPL ट्वेंटी-20** (प्रायोजक-वीवो) क्रिकेट टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में संपन्न (5 अप्रैल - 21 मई, 2017)।

➡ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में **मुंबई इंडियंस** (कप्तान : रोहित शर्मा) ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (कप्तान : स्टीव स्मिथ) को 1 रन से पराजित कर तीसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।

➲ फाइनल में 38 गेंदों पर बहुमूल्य 47 रन बनाने वाले **क्रुणाल पाण्ड्या** (मुंबई इंडियंस) को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

➲ राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के **बेन स्टोक्स** को आईपीएल के इस सत्र का **'सबसे मूल्यवान खिलाड़ी'** (Most Valuable Player) चुना गया।

❑ IPL-10 : प्रमुख तथ्य

➡ **ऑरेंज कैप**-(सर्वाधिक रन बनाने के लिए)- डेविड वॉर्नर (641 रन), सनराइजर्स हैदराबाद।

➡ **पर्पल कैप**-(सर्वाधिक विकेट लेने के लिए)-भुवनेश्वर कुमार (26 विकेट), सनराइजर्स हैदराबाद।

➡ **फेयर प्ले अवॉर्ड-** गुजरात लायंस

➡ **सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर :** (एक पारी में)-डेविड वॉर्नर (126 रन, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध)

➡ **सबसे तेज अर्धशतक :** सुनील नारायण (कोलकाता नाइट राइडर्स) : 15 गेंदों पर।

➡ **सबसे तेज शतक :** डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद); 43 गेंदों पर (कुल 126 रन, 59 गेंदों पर) कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध।

➡ **सर्वाधिक छक्के :** 26, ग्लेन मैक्सवेल (किंग्स इलेवन पंजाब)

➡ **सर्वाधिक चौके :** 63, डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)

➡ **सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी :** बासिल थम्पी (गुजरात लायंस)

➡ **FBB स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन :** गौतम गंभीर (कोलकाता नाइट राइडर्स)

➡ **विटारा ब्रेजा ग्लैम शॉट ऑफ द सीज़न :** युवराज सिंह (सनराइजर्स हैदराबाद)

➡ **वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन -** सुरेश रैना (गुजरात लायंस)

➡ IPL-10 में शतक लगाने वाले 4 खिलाड़ी इस प्रकार रहे–डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद), हाशिम अमला (2 शतक, किंग्स इलेवन पंजाब), बेन स्टोक्स (राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स) एवं संजू सैमसन (दिल्ली डेयरडेविल्स)।

➡ **सर्वाधिक टीम स्कोर :** 230/3, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस के विरुद्ध।

➡ **न्यूनतम स्कोर :** 49 रन, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू, कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध यह IPL इतिहास का न्यूनतम स्कोर रहा।

➡ **सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन :** एन्ड्रयू टॉय (गुजरात लायंस), 4 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट।

➡ **हैट्रिक** -3 [एंड्रयू टॉय (गुजरात लायंस), जयदेव उनादकड़ (राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स) एवं सैम्युल बद्री (रॉयल चैलेंजर्स, बैंगलोर) द्वारा]

➡ **किसे क्या मिला?**

विजेता - मुंबई इंडियंस (15 करोड़ रुपये)

उपविजेता - राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (10 करोड़ रुपये)

फुटबॉल

❑ फीफा U-20 विश्व कप, 2017

➡ दक्षिण कोरिया में संपन्न। (20 मई - 11 जून, 2017)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

विजेता - इंग्लैंड (1- 0से)

उपविजेता - वेनेजुएला

➡ प्रमुख पुरस्कार विजेता इस प्रकार रहे-

गोल्डन बूट - रिकार्डो ओर्सोलिनि (इटली, 5 गोल)

गोल्डन बॉल - डोमिनिक सोलांके (इंग्लैंड)

गोल्डन ग्लव - फ्रेडी वुडमैन (इंग्लैंड)

फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड - मेक्सिको

❑ यूएफा चैंपियंस लीग, 2016-17

➡ यूरोपीय फुटबॉल के सर्वाधिक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 'यूएफा चैंपियंस लीग' के 62वें संस्करण का फाइनल कार्डिफ (वेल्स) में संपन्न। (4 जून, 2017)

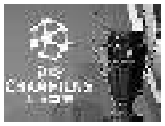

➲ **विजेता - रियल मैड्रिड** (4 - 1 से)

➲ उपविजेता - जुवेंट्स फुटबॉल क्लब

➲ प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल - क्रिस्टियानो रोनॉल्डो (रियल मैड्रिड, 12 गोल)

❑ एफए कप, 2016-17

➡ विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की मान्यता प्राप्त एफए कप का 136वां संस्करण वेम्बले स्टेडियम (लंदन) में संपन्न। (27 मई, 2017)

➲ प्रायोजक - अमीरात एयरलाइंस

➡ प्रतियोगिता परिणाम

विजेता - आर्सेनल फुटबॉल क्लब (2-1से)

उपविजेता - चेल्सी फुटबॉल क्लब

❑ यूएफा यूरोपा लीग, 2016-17

➡ यूरोपीय फुटबॉल प्रतियोगिता यूएफा यूरोपा लीग का 46वां संस्करण सोलना, स्वीडन में संपन्न। (15 सितंबर, 2016 - 24 मई, 2017)

➲ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - मैनचेस्टर यूनाइटेड, (ब्रिटिश फुटबॉल क्लब) (2 - 0 से)

उपविजेता - अजेक्स, (डच फुटबॉल क्लब)

❑ हीरो फेडरेशन कप

➡ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित **फेडरेशन कप, 2017** फुटबॉल प्रतियोगिता (प्रायोजक-हीरो मोटो कॉर्प) के 38वें संस्करण का फाइनल कटक (ओडिशा) में संपन्न (21 मई, 2017)

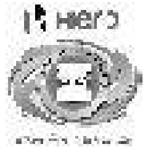

विजेता - बंगलुरू फुटबॉल क्लब (2-0 से)

उपविजेता - मोहन बागान फुटबॉल क्लब

❑ 2016-17 ला लीगा कप

➡ स्पेनिश फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा (La Liga) कप, 2016-17 संपन्न। (21 मई, 2017)

➲ **विजेता** - रियल मैड्रिड (33वां खिताब)

➲ बार्सीलोना के लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 37 गोल किए।

हॉकी

❑ सुल्तान अजलान शाह कप, 2017

➡ 26वां सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह (Ipoh) में संपन्न। (29 अप्रैल - 6 मई, 2017)

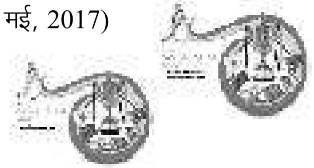

➡ प्रतियोगिता परिणाम

स्वर्ण पदक - ग्रेट ब्रिटेन

रजत पदक - ऑस्ट्रेलिया

➡ भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया।

➡ भारतीय टीम के कप्तान पी.आर. श्रीजेश एवं मुख्य कोच रोलैंट ओल्टमांस थे।

➡ **प्रतियोगिता में प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार रहे-**

➲ **प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी** - टॉम क्रेग (ऑस्ट्रेलिया)

➲ **फाइनल का 'मैन ऑफ द मैच'** - एलन फॉरसिथ (ग्रेट ब्रिटेन)

➲ **सर्वाधिक गोल** - टॉम क्रेग, ट्रेंट मिटन (दोनों ऑस्ट्रेलिया) एवं मंदीप सिंह (भारत), तीनों 5-5 गोल।

➲ **सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर** - सुगुरू शिमोतो (जापान)

➲ **फेयर प्ले अवॉर्ड (राजा अश्मान ट्रॉफी,** - न्यूजीलैंड

शतरंज

❑ फिडे ग्रैंड प्रिक्स सीरीज, 2017

➡ फिडे ग्रैंड प्रिक्स सीरीज, 2017 के 4 चरणों में से दूसरा चरण मॉस्को (रूस) में संपन्न। (12-21 मई, 2017)

➲ **प्रतियोगिता परिणाम**

प्रथम स्थान - डिंग लिरेन (चीन) (6 अंक)

द्वितीय स्थान- शख़ियार मैमेड्यारोव (अजरबैजान) (5.5 अंक)

❑ ऑल इंडिया ओपन रैपिड फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट, 2017

➡ कोलकाता (भारत) में संपन्न। (17-18 मई, 2017)

➲ **प्रतियोगिता परिणाम**

प्रथम - आर.आर. लक्ष्मण (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री), अंक : 9.5

➲ इस प्रतियोगिता का यह प्रथम संस्करण है।

बैडमिंटन

❑ सुदीरमन कप, 2017

➡ विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का 15वां संस्करण गोल्ड कोस्ट (क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में संपन्न। (21 - 28 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - दक्षिण कोरिया (चौथा खिताब)

उपविजेता - चीन

➲ यह पहला अवसर था जब यह प्रतियोगिता एशिया या यूरोप से बाहर खेली गई।

➲ अब तक सर्वाधिक 10 बार चीन ने इस खिताब पर कब्जा किया है।

➲ भारत क्वार्टर फाइनल में चीन से पराजित होकर इस प्रतियोगिता से बाहर हो गया था।

❑ थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, 2017

➡ बैंकॉक (थाईलैंड) में संपन्न। (30 मई- 4 जून, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - बी.साई प्रणीत (भारत)

उपविजेता - जोनाथन क्रिस्टी (इंडोनेशिया)

➲ श्रीकांत किदांबी (2013) के बाद यह खिताब जीतने वाले प्रणीत दूसरे भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।

गोल्फ

❑ द प्लेयर्स चैंपियनशिप, 2017

➡ PGA टूर का 'द प्लेयर्स चैंपियनशिप' पोंटे वेड्रा बीच, फ्लोरिडा (अमेरिका) में संपन्न (11-14 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - सी वू किम (दक्षिण कोरिया)

➡ किम द प्लेयर्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के गोल्फर बने।

टेबल टेनिस

❑ प्रथम टेबल टेनिस लीग

➡ भारत में **'अल्टीमेट पिंग पोंग चैंपियनशिप'** (Ultimate Ping Pong Championship) नाम से पहली बार टेबल टेनिस लीग का आयोजन किया जाएगा। (13-30 जुलाई, 2017)

➲ लीग का प्रथम एवं द्वितीय चरण चेन्नई और नई दिल्ली में जबकि फाइनल मुंबई में खेला जाएगा।

➲ यह लीग 11 ईवन स्पोर्ट्स (ESPL) द्वारा आयोजित की जाएगी।

➲ इस लीग की कुल ईनामी राशि 450,000 डॉलर (लगभग 3 करोड़ रुपये) होगी।

❑ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2017

➡ ITTF की इस विश्वस्तरीय प्रतियोगिता का 54वां संस्करण डसेलडोर्फ, जर्मनी में संपन्न। (29 मई - 5 जून, 2017)

➡ **प्रतियोगिता के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे-**

➲ **पुरुष एकल**

स्वर्ण पदक - मा लोंग (चीन)

रजत पदक - फान झेनडोंग (चीन)

➲ **महिला एकल**

स्वर्ण पदक - डिंग निंग (चीन)

रजत पदक - झु युलिंग (चीन)

बिलियर्ड्स/स्नूकर/स्क्वैश

❑ SYS ओपन, 2017

➡ PSA वर्ल्ड टूर स्क्वैश प्रतियोगिता न्यूयॉर्क (अमेरिका) में संपन्न। (11-14 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - रमित टंडन (भारत)

उपविजेता - कुश कुमार (भारत)

➲ रमित टंडन का यह पहला PSA (Professional Squash Association) वर्ल्ड टूर खिताब है।

❑ मलेशियन स्क्वैश टूर IX, 2017

➡ कुआलालम्पुर, मलेशिया में संपन्न (10-13 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - हरिन्दर पाल सिंह संधू (भारत)

उपविजेता - हेनरी लियुंग (हांगकांग)

❑ निसान ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, 2017

➡ मकाती सिटी, फिलीपींस में संपन्न। (18-21 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **पुरुष एकल**

विजेता - हरिन्दर पाल सिंह संधू (भारत)

उपविजेता - मो. शफीक कमाल (मलेशिया)

❑ द अमेरिका कप, 2017

➡ बिलियर्ड्स प्रतियोगिता विनीपेग (कनाडा) में संपन्न। (29 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

विजेता - माइक रसेल (इंग्लैंड)

उपविजेता - रॉबर्ट हॉल (इंग्लैंड)

➡ सेमीफाइनल में भारत के ध्रुव सितवाला, माइक रसेल से हार गए थे।

एथलेटिक्स

❑ टीसीएस वर्ल्ड 10K रेस

➡ वार्षिक 10 किमी. रेस प्रतियोगिता बंगलुरू में संपन्न। (21 मई, 2017)

➡ **विजेता (अंतरराष्ट्रीय)**

➲ **पुरुष वर्ग-** एलेक्स कोरियो (केन्या)

➲ **महिला वर्ग-** इरेन चेप्ताई (केन्या)

➡ **विजेता (भारतीय)**

➲ **पुरुष वर्ग-** नवीन कुमार

➲ **महिला वर्ग-** साई गीता नायक

❑ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2017

➡ इस द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण बैंकॉक (थाईलैंड) में संपन्न। (20-23 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता में चीन ने कुल 30 पदक (16 स्वर्ण, 9 रजत एवं 5 कांस्य) प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

➲ **पदक तालिका में प्रथम तीन स्थान**

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	चीन	16	9	5	30
2.	चीनी ताइपे	6	7	2	15
3.	भारत	5	5	4	14

➡ भारत के अभय गुप्ता ने डिस्कस थ्रो में 56.47 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया।

फॉर्मूला वन

❑ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, 2017

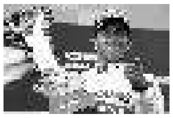

➡ मॉन्ट्रियल में संपन्न। (11 जून, 2017)

➡ विजेता - लुइस हैमिल्टन (टीम - मर्सिडीज)।

❑ मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, 2017

➡ फॉर्मूला वन सत्र 2017 की 6वीं रेस मोंटे कार्लो सर्किट, (मोनाको) में संपन्न। (28 मई, 2017)

➲ **विजेता - सेबेस्टियन वेट्टल** (टीम-फेरारी)

❑ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स

➡ फॉर्मूला वन सत्र 2017 की 5वीं रेस बर्सिलोना (स्पेन) में संपन्न। (14 मई, 2017)

➡ **प्रतियोगिता परिणाम**

➲ **विजेता - लुईस हैमिल्टन** (टीम-मर्सिडीज)

विविध

❑ ब्रिक्स खेल, 2017

➡ **प्रथम ब्रिक्स खेलों** (BRICS Games) का आयोजन चीन के ग्वांगझू में संपन्न। (17-21 जून, 2017)

➲ ब्रिक्स देशों **ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका** के लगभग 300 एथलीटों ने 3 खेलों की 10 स्पर्धाओं में भाग लिया।

➲ 3 खेल - पुरुष बास्केटबॉल, महिला वॉलीबॉल एवं वुशु।

➲ प्रतियोगिता की वुशु स्पर्धा में भारतीय टीम ने 6 पदक (2 स्वर्ण, 2 रजत एवं 2 कांस्य) जीते।

स्वर्ण पदक - एम. ग्यानदास और अंजुल नामदेव

रजत पदक - बिधेश्वरी देवी और तोशीबाला

कांस्य पदक - एल. सानातगोम्भी चानू एवं साजन लामा

➡ **पुरुष बास्केटबॉल परिणाम**

स्वर्ण पदक - रूस

रजत पदक - चीन

कांस्य पदक - दक्षिण अफ्रीका

भारत चौथे स्थान पर रहा।

➡ महिला वॉलीबॉल परिणाम

स्वर्ण पदक - रूस

रजत पदक - चीन

कांस्य पदक - ब्राजील

➲ भारत, दक्षिण अफ्रीका से पराजित होकर पांचवें स्थान पर रहा।

❑ ओली

➡ 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर (Mascot) जारी किया गया। (12 जून, 2017)

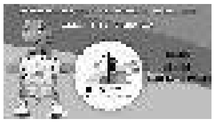

➲ यह एक ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ है जिसे **ओली** (Olly) नाम दिया गया है।

➲ चैंपियनशिप का आयोजन 6 - 9 जुलाई, 2017 के मध्य भुवनेश्वर, ओडिशा में किया जाएगा।

❑ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, 2017

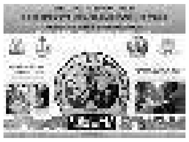

➡ इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में संपन्न (10-14 मई, 2017)

➡ प्रतियोगिता में जापान ने कुल 16 पदक (8 स्वर्ण, 3 रजत एवं 5 कांस्य) प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

➡ टीम-19 (फ्री-स्टाइल टीम-19)

➲ **पदक तालिका**

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	जापान	8	3	5	16
2.	ईरान	7	2	6	15
3.	कजाख्स्तान	2	5	6	13
4.	उज्बेकिस्तान	2	1	3	6
5.	भारत	1	5	4	10

➡ भारत को एकमात्र स्वर्ण **बजरंग पूनिया** ने पुरुषों की फ्री-स्टाइल स्पर्धा (65 किग्रा. भार वर्ग) में दिलाया।

➡ **भारत के रजत पदक विजेता**

➲ पुरुष फ्री-स्टाइल में सुमित (125 किग्रा. भार वर्ग)।

➲ महिलाओं की फ्री-स्टाइल में विनेश फोगाट (55 किग्रा.), सरिता (58 किग्रा.), साक्षी मलिक (60 किग्रा.) तथा दिव्या कक्कड़ (69 किग्रा.)।

➡ **भारत के कांस्य पदक विजेता**

➲ पुरुष ग्रीको-रोमन में हरप्रीत सिंह (80 किग्रा.) तथा अनिल कुमार (85 किग्रा.)।

➲ महिलाओं की फ्री-स्टाइल में रितु फोगाट (48 किग्रा.) तथा ज्योति (75 किग्रा.)।

❑ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 2017

➡ ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में संपन्न। (30 अप्रैल - 7 मई, 2017)

➲ पदक तालिका :

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	उज्बेकिस्तान	9	0	0	9
2.	कजाख्स्तान	1	3	4	8
3.	भारत	0	2	2	4

➲ **भारत के पदक विजेता**

रजत पदक - 1. शिव थापा - (60 किग्रा. भार वर्ग)
2. सुमित सांगवान- (91 किग्रा. भार वर्ग)

कांस्य पदक - 1. अमित (46-49 किग्रा. भार वर्ग)
2. विकास कृष्ण (75 किग्रा. भार वर्ग)

❑ खेलियो

➡ भारत की मेजबानी में 6 -28 अक्टूबर, 2017 के मध्य आयोजित होने वाले फीफा U-17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए **'खेलियो'** को शुभंकर चुना गया है।

➲ यह हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाने वाला तेंदुआ है।

❑ हीरो द हेजहोग

➡ IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2017 का आधिकारिक शुभंकर **'हीरो द हेजहोग'** (Hero the Hedgehog) को चुना गया है।

➲ चैंपियनशिप का आयोजन 4-13 अगस्त, 2017 के मध्य लंदन में किया जाएगा।

➲ 14-23 जुलाई, 2017 के मध्य लंदन में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेतु **'विजबी द बी'** (Whizbee the Bee) को शुभंकर चुना गया है।

चर्चित खेल व्यक्ति एवं स्थल

❑ दुष्यंत चौटाला

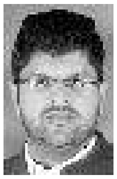

➡ भारतीय टेबल टेनिस संघ (TTFI) के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को जर्मनी में साउथ एशियन टेबल टेनिस संघ (SATTF) का अध्यक्ष चुना गया। (30 मई, 2017)

❑ सी.ए. भवानी देवी

➡ भारतीय तलवारबाज सी.ए. भवानी देवी किसी अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। (27 मई, 2017)

➲ रेक्जाविक (आइसलैंड) में संपन्न तरनोई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी ने साबरे (Sabre) स्पर्धा के फाइनल में ब्रिटेन की सारा जेन हैम्पसन को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की।

❑ लियोनेल मेसी

➡ अर्जेंटीना के फुटबॉलर।

➲ चौथी बार **यूरोपियन गोल्डेन शू अवॉर्ड** जीतकर रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की। (28 मई, 2017)

➲ उल्लेखनीय है कि स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में **मेसी** ने सर्वाधिक 37 गोल कर 74 अंक प्राप्त किए।

➡ जुलाई, 2016 में स्पेन की एक अदालत द्वारा लियोनेल मेसी और उनके पिता जॉर्ज मेसी को कर धोखाधड़ी के मामले में सुनाई गई 21 माह की जेल की सजा को स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। (24 मई, 2017)

❑ पी.वी. सिंधु

➡ गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय शटलर सिंधु को बीडब्ल्यूएफ (BWF) के एथलीट कमीशन का सदस्य चुना गया। (24 मई, 2017)

➡ चार सदस्यों के लिए हुए मतदान में सर्वाधिक वोट (129) प्राप्त करने वाली सिंधु का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

➡ इनके अतिरिक्त स्कॉटलैंड की कर्स्टी गिलमोर (103 वोट), लिथुआनिया की अक्विले स्टापुसाईतिते (25 वोट) और जर्मनी के मार्क ज्वीब्लर (108 वोट) का भी चयन किया गया।

❑ स्टीफेन कोट्टालॉर्डा

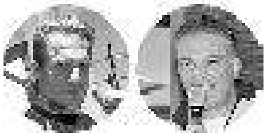

➡ 'इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन' (AIBA) के थ्री स्टारर कोच फ्रांस के **स्टीफेन कोट्टालॉर्डा** को 2 वर्षों के लिए भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। (23 मई, 2017)

➡ इसके अतिरिक्त इटली के **रॉफेल बर्गामॉस्को** को जूनियर महिला मुक्केबाजों का कोच नियुक्त किया गया है।

➡ बर्गामॉस्को तथा मार्च, 2017 में नियुक्त पुरुष मुक्केबाज कोच सैंटियागो निएवा का अनुबंध दिसंबर, 2020 तक रहेगा।

➡ भारतीय बॉक्सिंग के इतिहास में पहली बार विभिन्न स्तरों पर तीन विदेशी कोच नियुक्त किए गए हैं।

❑ जिंदर महल

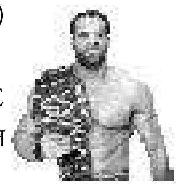

➡ भारतीय मूल के कनाडाई पहलवान **जिंदर महल** (वास्तविक नाम राज सिंह धेसी) WWE (वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट) चैंपियन बने। (21 मई, 2017)

➲ इन्होंने शिकागो (अमेरिका) में संपन्न WWE चैंपियनशिप में 13 बार के चैंपियन रैंडी ऑर्टन को पराजित किया।

➲ जिंदर WWE चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम एवं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतवंशी हैं।

➲ इनसे पूर्व **'द ग्रेट खली'** वर्ष 2007 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं।

❑ दीप्ति शर्मा एवं पूनम राउत

➡ दक्षिण अफ्रीका में एक चतुष्कोणीय शृंखला के दौरान भारतीय महिला क्रिकेटर **दीप्ति शर्मा एवं पूनम राउत** ने आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेले गए एक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 320 रन की साझेदारी की। (15 मई, 2017)

➲ महिला एवं पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह प्रथम अवसर था, जब पहले विकेट के लिए 300 से अधिक रन की साझेदारी निभाई गई।

➲ पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट में उच्चतम ओपनिंग साझेदारी 286 रन की है, जो श्रीलंका के उपुल थारंगा एवं सनथ जयसूर्या के नाम है।

➲ इस साझेदारी में दीप्ति ने 188 रन बनाए जो महिला एकदिवसीय क्रिकेट का दूसरा उच्चतम (पहला ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क, नाबाद 229 रन) व्यक्तिगत स्कोर है।

❑ सचिन तेंदुलकर

➡ तेंदुलकर विवो (Vivo) प्रो-कबड्डी लीग के पांचवें संस्करण में शामिल हो रही चार नई टीमों में से एक चेन्नई फ्रेंचाइजी टीम 'तमिल थलाईवास' (Tamil Thalaivas) के सह-मालिक (Co-owner) बने। (12 मई, 2017)

❑ मुकुल मुद्गल

➡ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।

➲ बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित फीफा की 67वीं कांग्रेस में 'फीफा संचालन समिति' (FGC) के अध्यक्ष चुने गए। (11 मई, 2017)

➲ वह इस पद पर मिगुएल मादुरो का स्थान लेंगे।

❑ वीवीएस लक्ष्मण

➡ मेरीलबोन क्रिकेट क्लब (MCC), लॉर्ड्स ने भारतीय बल्लेबाज **लक्ष्मण** को आजीवन मानद सदस्य चुना। (11 मई, 2017)

➡ लक्ष्मण यह सम्मान पाने वाले 25वें भारतीय क्रिकेटर हैं।

➡ इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा हैं जिन्हें वर्ष 2016 में शामिल किया गया था।

❑ झूलन गोस्वामी

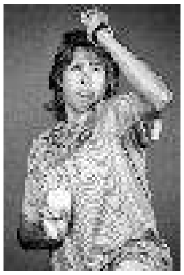

➡ भारतीय महिला क्रिकेटर।

➲ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में **सर्वाधिक विकेट (181) लेने वाली महिला गेंदबाज** बनीं। (9 मई, 2017)

➲ दक्षिण अफ्रीका की रेसीबे नटोजाखे इनका 181वां शिकार बनीं।

➲ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक (180 विकेट) का रिकॉर्ड तोड़ा।

❑ यूनुस खान

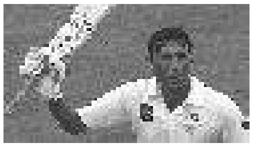

➡ पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के मध्य खेली गई टेस्ट शृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और विश्व के 13वें बल्लेबाज बने। (23 अप्रैल, 2017)

➡ यूनुस ने यह उपलब्धि 208वीं पारी (116 टेस्ट मैच) में अर्जित की।

➡ इस क्लब में भारत के तीन क्रिकेटर सुनील गावस्कर (1987), सचिन तेंदुलकर (2005) तथा राहुल द्रविड़ (2008) शामिल हैं।

ज्ञानिकी
सम्पूर्ण ज्ञान का धारावाहिक
सामान्य ज्ञान का विशेष परिशिष्ट

जैन धर्म

13 अंकों में आविष्कार/खोज, 4 अंकों में राष्ट्रगान, 5 अंकों में संसद, 3 अंकों में मुद्राओं तथा 11 अंकों में धरातलीय आकृतियों के पश्चात अब ज्ञानिकी के तहत पृथक-पृथक शीर्षकों में जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। 21 अंकों में परिवहन के विभिन्न घटकों, महासागरीय नितल के उच्चावच, स्थानीय पवन, आर्द्रता, कुहरा एवं बादल, वर्षा, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों, पाषाण काल तथा हड़प्पा काल पर जानकारी प्रस्तुत करने के बाद विगत तीन अंकों में वैदिक सभ्यता के विषय में तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था। इस अंक में भारतीय इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

❑ जैन धर्म

- जैन शब्द संस्कृत के 'जिन' शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है।
- जैन संस्थापकों को 'तीर्थंकर' जबकि जैन महात्माओं को 'निर्ग्रंथ' कहा गया।
- जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय-समय पर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया।
  - यह हैं-1. ऋषभदेव, 2. अजितनाथ, 3. संभवनाथ, 4. अभिनंदन, 5. सुमतिनाथ, 6. पद्मप्रभु, 7. सुपार्श्वनाथ, 8. चंद्रप्रभु, 9. पुष्पदंत (सुविधिनाथ), 10. शीतलनाथ, 11. श्रेयांसनाथ, 12. वासुपूज्य, 13. विमलनाथ, 14. अनंतनाथ, 15. धर्मनाथ, 16. शांतिनाथ, 17. कुंथुनाथ, 18. अरनाथ, 19. मल्लिनाथ, 20. मुनिसुव्रत, 21. नमिनाथ, 22. नेमिनाथ या अरिष्टनेमि, 23. पार्श्वनाथ एवं 24. महावीर स्वामी।
- जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे।
  - इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है।
- ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
- पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं।
  - इनका जन्म काशी (वाराणसी) में हुआ था।
  - इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
- पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था।
- पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था।
  - ये चार शिक्षाएं थी-सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह।
- महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ई. पू. में हुआ था।
  - इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे।
  - इनकी मात्रा त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवि गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं।
- महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्द्धमान था।
- इनकी पत्नी का नाम यशोदा (कुंडिन्य गोत्र की कन्या) था।
  - इससे उन्हें अजोज्या (प्रियदर्शना) नामक पुत्री उत्पन्न हुई।
  - इसका विवाह जामालि के साथ हुआ था।
- जैन धर्म में 'पूर्ण ज्ञान' के लिए 'कैवल्य' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात 'जृम्भिक ग्राम' के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य (पूर्ण ज्ञान) प्राप्त हुआ था।
  - ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अर्हत (योग्य), जिन (विजेता) तथा निर्ग्रंथ (बंधन रहित) कहलाए।
- कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया।
- वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया।
- महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्ट जामालि से मतभेद हो गया, मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत (कार्य करते ही पूर्ण हो जाना) था।
  - इस मतभेद के कारण जामालि ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतरवाद (कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा) का प्रतिपादन किया।
- जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामालि के विद्रोह के दो वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था।

- 527 ई.पू. के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह (राजगीर) के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया।

❑ जैन धर्म की शिक्षाएं

- महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी जो इस प्रकार है–अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य।
  - प्रथम चार व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे।
  - महावीर ने इसमें पांचवां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था।
- जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया।
  - ये पंच अणुव्रत हैं–अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत।
- महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इंकार किया तथा धार्मिक-सामाजिक रुढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया।
- उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया जिसे 'अनेकांतवाद' अथवा 'स्यादवाद' कहा गया।
  - 'स्यादवाद' को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है।

प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिह्न

तीर्थंकर	प्रतीक चिह्न
ऋषभदेव	बैल
अजितनाथ	हाथी
संभवनाथ	अश्व
पद्मप्रभु	कमल
सुपार्श्वनाथ	साथिया (स्वास्तिक)
मल्लिनाथ	कलश
नमिनाथ	नीलकमल
नेमिनाथ	शंख
पार्श्वनाथ	सर्प
महावीर स्वामी	सिंह

- जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं।
  - ये हैं–सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र।
  - इन तीनों को जैन धर्म में 'त्रिरत्न' की संज्ञा दी गई है।
- त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे 'संवर' कहते हैं।
  - इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे 'निर्जरा' कहा गया है।
  - जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
- जैन धर्म में 'अनंत चतुष्ट्य' है–अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख।
- महावीर स्वामी ने अपने जीवनकाल में एक संघ की स्थापना की।
  - इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये 'गणधर' कहे गए।
  - इनके नाम हैं–इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति (तीनों भाई), व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मोरियपुत्र, अकंपित, अचलभ्राता, मेतार्य तथा प्रभास।
- महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना।
- सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा।
- अंतिम नंद राजा के समय सम्भूतविजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे।
  - महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो (प्राचीनतम जैन ग्रंथों) के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे।
- कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया।
  - ये संप्रदाय थे–श्वेतांबर एवं दिगंबर।
- स्थूलभद्र के अनुयायी 'श्वेतांबर' कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी 'दिगंबर' कहलाए।
- 'यापनीय' जैन धर्म का एक संप्रदाय है।

श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर

श्वेतांबर	दिगंबर
● इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।	● इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं।
● इस मत के अनुसार, स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है।	● इस मत के अनुसार, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है।
● इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं।	● जबकि दिगंबर मत इसके विरुद्ध है।
● इस मत के अनुसार, महावीर स्वामी विवाहित थे।	● दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे।
● इस मत के अनुसार, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे।	● दिगंबर मतानुसार वे पुरुष थे।

जैन सभा

- प्रथम जैन सभा चतुर्थ शताब्दी ई.पू. में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
  - इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया।
  - इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया।
- द्वितीय जैन सभा छठीं शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगण या क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
  - द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 4 मूलसूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ।

जैन साहित्य

- जैन साहित्य को 'आगम' (सिद्धांत) कहा जाता है।
  - इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 4 मूलसूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नन्दिसूत्र की गणना की जाती है।
- जैन आगम में बारह अंगों का प्रमुख स्थान है।
  - ये हैं–आचारांग सुत्त, सूयग दंग (सूत्र कृतांग) सुत्त, ठाणंग (स्थानांग), समवायंग सुत्त, भगवती सुत्त, नायाधम्मकहा (ज्ञाताधर्मकथा) सुत्त, उवासगदसाओं (उपासकदशा) सुत्त, अंतगद्ददसाओं, अणुत्तरोववाइयदसाओं, पण्हावागरणाइ (प्रश्न व्याकरण), विवागसुयम् तथा दिट्ठिवाय (दृष्टिवाद)।
- बारह अंगों से संबंधित एक-एक 'उपांग' ग्रंथ हैं।
  - इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है।
  - बारह उपांग हैं–औपपातिक, जीवाभिगम, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निरयावलि, कल्पावसंतिका, पुष्पिका, पुष्प चूलिका तथा वृष्णि दशा।
- 'दस प्रकीर्ण' प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट है।
  - ये हैं–चतु:शरण, देवेंद्रस्तव, आतुर प्रत्याख्यान, वीरस्तव, भक्तिपरिज्ञा, तंदुल वैतालिका, चंद्रवैध्यक, गणितविद्या, संस्तार तथा महाप्रत्याख्यान।
- 'छेदसूत्र' की संख्या छ: है।
  - इसमें जैन-भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है।
  - छ: छेदसूत्र हैं–कल्प, पंचकल्प, निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार तथा आचार दशा।
- मूलसूत्र की संख्या चार है।
  - इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है।
  - चार मूलसूत्र हैं–दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, षडावशयक तथा पिंडनिर्युक्ति या पाक्षिक सूत्र।
  - अनुयोग सूत्र तथा नन्दिसूत्र जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं जो एक प्रकार का विश्वकोष है।
  - इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं।
- उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं।
- दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते।

अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार

जैन ग्रंथ	रचनाकार
कल्पसूत्र	भद्रबाहु
परिशिष्ट पर्वन	हेमचंद्र
स्यादवाद्दमंजरी	मल्लिसेन
द्रव्य संग्रह	नेमिचंद्र
न्यायावतार	सिद्धसेन दिवाकर
तत्वार्थ सूत्र	उमास्वामी
न्याय दीपिका	धर्मभूषण
श्लोक वार्तिक	विद्यानंद स्वामी
पंचविंशतिका	पद्मनंदि
प्रवचनसार	कुन्दकुन्द

जैन धर्म का विकास

- जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है।
  - इसे उज्जैन में शासन करने के कारण यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
- जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था।
  - यहां से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं।
- कलिंग का चेदि शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था।
  - इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे।
- राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल (9वीं शताब्दी) में तथा गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा।
- खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं।
- माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं।
  - इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य (सोलंकी) शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमलशाह ने करवाया था।
- श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है।
  - यहां गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ई. में बाहुबली (गोमतेश्वर) की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया।
  - बाहुबली, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं।
- महामस्तकाभिषेक, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2017

प्रथम प्रश्न-पत्र

सीरीज - D **परीक्षा तिथि - 18/6/2017**

सम-सामयिक घटना चक्र द्वारा अपने पाठकों के लिए UPSC सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2017 का हल प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक उत्तरों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न के हल हेतु व्याख्या के लिए उत्तर के मूल स्रोत तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। इन मूल स्रोतों अर्थात उत्तर को प्रमाणित करने वाली व्याख्या हेतु प्रयुक्त अधिकांश पाठ्य सामग्री हमारे पास संरक्षित है। इन्हीं मूल स्रोतों के आधार पर हम इस हल प्रश्न-पत्र की अधिकतम शुद्धता का दावा करते हैं। यदि कहीं किसी प्रश्न के उत्तर हेतु हमारी व्याख्या से न संतुष्ट हो पा रहे हों, तो दूरभाष सं. 9335140296 पर मध्याह्न 12 बजे से सायं 8 बजे के मध्य हमसे संपर्क करें। हम आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे।

1. निम्नलिखित में से कौन-सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था?

(a) काकिनाडा (b) मोटुपल्ली
(c) मछलीपटनम (मसुलीपटनम) (d) नेल्लुरु

उत्तर–(b)

मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्कोपोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्कोपोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान के आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। तेरहवीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब का पानी, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता था।

2. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलाएंस)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह यूरोपीय संघ की पहल है।
2. यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) द्वारा किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(a)

भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (GCCA) यूरोपीय संघ (EU) द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को दो पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इनमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। GCCA का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन (EC) द्वारा किया जाता है।

3. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे।
2. सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय (फिनोमिना) के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(b)

सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। अतः कथन (1) असत्य है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद, अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार, विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणमात्र के लिए ही रहता है।

जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे ही क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षणमात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। हालांकि सर्वास्तिवादियों की मान्यता है कि संसार की सभी वस्तुओं की सत्ता या अस्तित्व है, वे असार नहीं हैं। वे यह मानते हैं कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वास्तिवाद नाम का शाब्दिक अर्थ है कि सब कुछ मौजूद है। अतः कथन (2) सत्य है।

4. भूमध्यसागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है?

1. जॉर्डन

2. इराक

3. लेबनान

4. सीरिया

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1,2 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर–(c)

भूमध्यसागर या रुम सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा है। यह दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह सागर जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से, बासफोरस जलडमरूमध्य द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्यसागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं- अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इस्राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

5. 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह नीति (NITI) आयोग का एक अंग है।

2. वर्तमान में इसकी कॉर्पस रु. 4,00,000 करोड़ है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(d)

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि' एक अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है। यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी कॉर्पस रु. 40,000 करोड़ करना प्रस्तावित है। अतः कथन (1) एवं (2) दोनों असत्य हैं।

6. सार्वभौम अवसंरचना सुविधा (ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी)

(a) एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए ASEAN का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख (क्रेडिट) से वित्तपोषित है।

(b) गैर-सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारियों (PPPs) की तैयारी और संरचना-निर्माण को सुकर बनाता है।

(c) OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर-सरकारी विनिवेश संग्रहीत करने की क्षमता है।

(d) UNCTAD द्वारा वित्तपोषित उपक्रमण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है।

उत्तर–(b)

उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा 'सार्वभौम अवसंरचना सुविधा केंद्र' स्थापित किया गया है। यह सरकारी-निजी भागीदारियों तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता की सामर्थ्य वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है। सितंबर, 2014 में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अपने अधिशेष में से 15 मिलियन डॉलर सार्वभौम अवसंरचना सुविधा केंद्र में प्रारंभिक मूल पूंजी के रूप में अंतरित करने का अनुमोदन किया था।

7. लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र -

(a) भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

(b) जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

(c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।

(d) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

उत्तर–(c)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, लोक सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए अर्थात उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में, हिमालय केवल पांच राज्यों में फैला हुआ है।

2. पश्चिमी घाट केवल पांच राज्यों में फैले हुए हैं।

3. पुलिकट झील केवल दो राज्यों में फैली हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर—(b)

भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य - जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का पांच से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार छः राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा (चिल्का के बाद) लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्यानुसार कथन (1) एवं (2) गलत हैं जबकि कथन (3) सही है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

9. जैव ऑक्सीजन मांग (BOD) किसके लिए एक मानक मापदंड है?

(a) रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए

(b) वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए

(c) जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए

(d) उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए

उत्तर—(c)

जैव ऑक्सीजन मांग (Biological Oxygen Demand : BOD) जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग (BOD) कहते हैं। जहां उच्च BOD है, वहां निम्न घुली ऑक्सीजन (Dissovled Oxygen- DO) होगा।

$$\text{BOD} \propto \frac{1}{\text{DO}}$$

10. बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN-Habitat) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों।

2. इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

उत्तर—(b)

संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम (UN-Habitat) मानव अधिवास एवं धारणीय शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इस अभिकरण का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इस अभिकरण को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिकार (Mandated) दिया गया है कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय कस्बों एवं शहरों को प्रोत्साहित करे जो सभी को यथोचित आश्रय उपलब्ध कराता हो। इसके साझीदारों में केवल सरकारें एवं स्थानीय नगर प्राधिकरण ही सम्मिलित नहीं हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत एवं गैर-सरकारी साझीदार भी इसमें सम्मिलित हैं। यह अभिकरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता है। इस प्रकार कथन (1) एवं (3) सही हैं। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

11. 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' (NSQF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. NSQF के अधीन, शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण-पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है।

2. NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(b)

NSQF के अंतर्गत शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण-पत्र औपचारिक, गैर-औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए प्राप्त कर सकता है। अतः कथन (1) गलत है। NSQF के कार्यान्वयन से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित हैं-

1. NSQF के साथ डिग्री के संरेखण द्वारा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण।
2. पूर्व अधिगम (आरपीएल) की पहचान, गैर-औपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में संक्रमण की अनुमति।
3. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण की मानवीकृत, सुसंगत, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम।

4. NSQF के अंतरराष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता।
5. क्षेत्रों के भीतर एवं पार-क्षेत्रीय रूप से प्रगति पथ का मानचित्रण।
6. कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में NOS/ QPs का अनुमोदन।

12. भारतीय इतिहास के संदर्भ में 'द्वैध शासन' (डायआर्की) सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है?

(a) केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन।
(b) दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना।
(c) दो शासक-समुच्चय; एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना।
(d) प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।

उत्तर—(d)

द्वैध शासन (डायआर्की) सिद्धांत के अंतर्गत शासन के विषयों को प्रांतीय तथा केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया जो भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत बनाए गए विकेंद्रीकरण के नियमों (Devolution Rules) द्वारा किया गया। केंद्रीय विषय थे- रक्षा, विदेशी मामले, टंकण तथा मुद्रा, आयात-निर्यात कर इत्यादि। जहां एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए थे तथा प्रशासन केंद्रित होना चाहिए था। प्रांतीय विषयों में थे- शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन और कृषि इत्यादि जहां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन आवश्यक थे। प्रांतीय सूची को फिर दो भागों में बांटा गया- हस्तांतरित विषय (जैसा कि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि इत्यादि) जिनका प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपा जाना था तथा आरक्षित विषय (जैसा कि शांति और व्यवस्था, पुलिस, वित्त, भूमि कर, श्रम इत्यादि) जिनका प्रशासन कार्यकारी पार्षदों द्वारा चलाया जाना था। अतः द्वैध शासन सिद्धांत के तहत प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन किया गया था।

13. 'नेशनल कॅरियर सर्विस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नेशनल कॅरियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, का एक उपक्रमण है।
2. नेशनल कॅरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों	(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(b)

नेशनल कॅरियर सर्विस (NCS) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है। इसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जुलाई, 2015 को लांच किया गया था। इसके तहत देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ-साथ, छात्रों को कॅरियर काउंसिलिंग, अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन तथा नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यर्थियों की खोज में मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

14. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/ S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?

(a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है।
(b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है।
(c) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है।
(d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड' का एक महत्वपूर्ण उपबंध है।

उत्तर—(b)

'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति' (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets/S4A) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक योजना है। यह योजना वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। दबावयुक्त परिसंपत्ति, सकल एनपीए के साथ मानक पुनर्संरचित अग्रिम व माफी का योग होता है।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC), G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है।
2. CCAC मेथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लुओरोकार्बनों पर केंद्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों	(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(b)

जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (Climate and Clean Air Coalition : CCAC) विभिन्न देशों, नागरिक समाजों (Civil Societies) व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है, जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह 53 देशों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा

निर्मित एक गठबंधन है। CCAC, मेथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लुओरोकार्बनों पर मुख्यतया केंद्रित करता है। यह गठबंधन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ, उनकी उपशमन रणनीति तथा क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्यवाहियों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक एवं अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम हो।

16. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित 'इंडियन ओशन डाइपोल' (IOD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. IOD परिघटना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर-पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है।

2. IOD परिघटना मानसून पर एल-नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(b)

इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो (Indian Nino) के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। अतः कथन (1) गलत है। यह परिघटना मानसून पर एलनीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार कथन (2) सही है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

17. यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है?

(a) भितरकणिका मैंग्रोव
(b) चंबल नदी
(c) पुलिकट झील
(d) दीपर बील

उत्तर–(b)

घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखना सबसे सही है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैविएलिस गैंगेटिकस (Gavialis Gangeticus) है। घड़ियालों की ज्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। आईयूसीएन (IUCN) ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा है।

18. हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद (सिम्पोजियम) (IONS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. प्रारंभी (इनॉगुरल) IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था।

2. IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों (स्टेट्स) की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(b)

हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद (IONS) एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक समावेशी एवं खुला मंच उपलब्ध कराने के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। 14-16 फरवरी, 2008 के मध्य पहला हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

19. बोधिसत्त्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो -

(a) अजंता में है
(b) बदामी में है
(c) बाघ में है
(d) एलोरा में है

उत्तर–(a)

गुफा एक की बोधिसत्त्व पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कला कृतियों में से एक है। इसे छठीं शताब्दी ई. के अंत में निष्पादित किया गया था। उसने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ-कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है।

20. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

परंपराएं - समुदाय
1. चलिहा साहिब उत्सव - सिंधियों का
2. नंदा राज जात यात्रा - गोंडों का
3. वारी-वारकरी - संथालों का

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(a)

सिंधी समाज प्रति वर्ष जुलाई-अगस्त में माह में चलिहा साहिब उत्सव मनाता है। इसमें 40 दिनों तक कठिन व्रत रखते हुए अखंड ज्योति की पूजा की जाती है। नंदा राज जात यात्रा भारत के उत्तराखंड में होने वाली एक प्रमुख सांस्कृतिक यात्रा है। यह लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा 16वीं शताब्दी में राजा कल्याणचंद के शासन काल के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में शुरू हुआ था। अतः नंदा राजा जात यात्रा

का संबंध गोंडों से नहीं है। पिछले सात सौ वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर महायात्रा वारी-वारकरी का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णवजनों का कुंभ कहा जाता है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है- सालों-साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में प्रति वर्ष शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है और यह संप्रदाय भी 'वारकरी संप्रदाय' कहलाता है। इस प्रकार वारी-वारकरी का संबंध संथालों से नहीं है।

21. निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन-सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है/हैं?

1. भूमि की कम या शून्य जुताई

2. खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग

3. फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(d)

शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार-बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों ही पद्धतियां कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं।

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम' (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम) का उद्देश्य है-

1. सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।

2. मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना।

3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अति-उपयोग को रोकना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(b)

राष्ट्रीय 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (SHCS) का शुभारंभ 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से ''स्वस्थ धरा, खेत हरा'' नारे के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति-प्रयोग (अनावश्यक प्रयोग) से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। शेष विकल्पों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

23. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

सामान्यतः प्रयुक्त/ उपभुक्त पदार्थ	**उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन**
1. लिपस्टिक	**- सीसा**
2. शीतल पेय	**- ब्रोमीनित वनस्पति तेल**
3. चाइनीज फास्ट फूड	**- मोनोसोडियम ग्लूटामेट**

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(d)

लिपस्टिक मोम, तेल, प्रति-ऑक्सीकारक तथा प्रशामक (Emollients) इत्यादि से युक्त होती है। इसमें लेड (Lead) की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर (IQ) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल (BVO) एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः सभी युग्म सही सुमेलित हैं।

24. कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड (ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड/OLED) का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श (डिजिटल डिस्प्ले) सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं?

1. OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं।

2. OLED के प्रयोग से, वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिवेल्लनीय प्रदर्श (रोल्ड-अप डिस्प्ले) बनाए जा सकते हैं।

3. OLED के प्रयोग से, पारदर्शी प्रदर्श संभव है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

उत्तर—(c)

कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड (OLED) एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) ही होता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त (Electroluminescent) उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ओएलईडी डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं, अतः कथन (1) सत्य है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित रोल्ड-अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। साथ ही OLED के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण संभव है।

25. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है/हैं?

1. अरसवल्ली
2. अमरकंटक
3. ओंकारेश्वर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(a)

अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मान्धाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए, किए गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है।

2. भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 3

उत्तर—(d)

भारत में लोक सभा अथवा राज्य विधान सभाओं के चुनाव 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (First Past the Post) पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50 प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अतः कथन (1) गलत है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत, लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। अतः कथन (2) भी गलत है। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर होगा।

27. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ/हुए है/हैं?

1. GDP में कृषि का अंश बृहत् रूप से बढ़ गया।
2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया।
3. FDI का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया।
4. भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत् रूप से बढ़ गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर—(b)

विश्व विकास संकेतक के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का अंश वर्ष 2000 में 23 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2015 में यह घटकर 17 प्रतिशत रह गया। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, वर्ष 2014 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1990 और 2000 में यह क्रमशः 0.5 एवं 0.7 प्रतिशत ही थी। अतः कथन (2) सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, भारत का निवल FDI वर्ष 2014-15 (प्रारंभिक आंकड़े) में 31251 मिलियन डॉलर था जबकि वर्ष 2000-01 में यह मात्र 3272 मिलियन डॉलर था। अतः कथन (3) सत्य है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वर्ष 1991-92 में 9220 मिलियन डॉलर था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 320649 मिलियन डॉलर हो गया। अतः कथन (4) भी सत्य है।

28. कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी (सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी) का अनुप्रयोग क्या है?

(a) जैव-डिम्भनाशी का उत्पादन
(b) जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण
(c) जंतुओं की जननीय क्लोनिंग
(d) रोगमुक्त जीवों का उत्पादन

उत्तर—(c)

कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रजननीय प्रतिरूपण (Reproductive Cloning) द्वारा आनुवांशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका (कायिक कोशिका) से किसी नाभिक-विहीन अंडे में नाभिक (Nucleus) का स्थानांतरण करना शामिल होता है।

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/NPCI) देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है।

2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(c)

रुपे कार्ड (RuPay Card) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा अप्रैल, 2011 में विकसित स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसका नाम दो शब्दों 'रुपया' और 'पेमेंट' से मिलाकर रखा गया है। इसे बहुराष्ट्रीय वीजा, अमेरिकन, एक्सप्रेस एवं मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। 8 मई, 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड 'रुपे' राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है। यह देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है।

30. 'M-STrIPES' शब्द कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है?

(a) वन्य प्राणिजात का बद्ध प्रजनन

(b) बाघ अभयारण्यों का रख-रखाव

(c) स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली

(d) राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा

उत्तर–(b)

'M-STrIPES' (Monitoring System for Tigers - Intensive Protection and Ecological Status) शब्द कभी-कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रख-रखाव के संदर्भ में देखा जाता है। इस तंत्र के दो मुख्य घटक हैं।

1. पारिस्थितिकीय निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने व गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल।

2. संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर।

'M-STrIPES' द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके एवं जो नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो। समुचित क्रियान्वयन करने पर 'M-STrIPES' बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी विघातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने हेतु एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह GIS (Geogrphic Information System) आधारित तंत्र का प्रयोग करता है।

31. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किए जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/ हैं?

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा।

2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।

3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(a)

जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।

जीएसटी से लाभ-

व्यापार और उद्योग के लिए- आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए- सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता।

उपभोक्ताओं के लिए - वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।

32. 'व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार' (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट/BTIA) कभी-कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है?

(a) यूरोपीय संघ

(b) खाड़ी सहयोग परिषद

(c) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

(d) शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर–(a)

'व्यापक-आधारभूत व्यापार और निवेश करार' (Broad-based Trade and Investment Agreement- BTIA) भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह समझौता वर्ष 2007 में लागू हुआ।

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।

2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।

3. TFA, जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(a)

लंबे समय से विकासशील एवं विकसित दोनों देशों के व्यापारी सीमाओं के आर-पार वस्तुओं की आवाजाही में अनावश्यक रूप से लगने वाले अधिक समय के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं क्योंकि इससे छोटे एवं मझोले उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः इस समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक में ऐतिहासिक 'व्यापार सुविधा समझौते' (Trade Facilitation Agreement : TFA) पर हस्ताक्षर किए गए। WTO के कुल 164 सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्यों द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद यह समझौता 22 फरवरी, 2017 से प्रभावी हो गया। 22 अप्रैल, 2016 को भारत द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन किया गया था।

34. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है?

(a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी।
(b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे।
(c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
(d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।

उत्तर–(c)

चाबहार, ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह एक मुक्त बंदरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। मई, 2015 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से भारत की पहुंच न अफगानिस्तान तक, बल्कि मध्य एशिया के अन्य देशों तक हो जाएगी। इसके पूर्व यहां तक पहुंच बनाने के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता था।

35. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है/हैं?

1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(d)

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70-B केंद्र सरकार को 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2013' जारी किए हैं जिसमें CERT-In के कार्य करने के तरीके तथा स्थल आदि का उल्लेख है। ये नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डाटा केंद्रों तथा कॉर्पोरेट निकायों पर यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं, जिससे CERT-In इस पर शीघ्र कार्यवाही कर सके।

36. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार-

(a) मूल अधिकार है (b) नैसर्गिक अधिकार है
(c) संवैधानिक अधिकार है (d) विधिक अधिकार है

उत्तर–(d)

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (d) में निर्वाचक अधिकार (Electoral Rights) को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने तथा 'चुनाव में मतदान करने' या 'मतदान करने से विरत रहने' के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देबी घोषाल एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक/वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक/वैधानिक अधिकार है।

37. 'विकसित लेजर व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटेना' (इवॉल्वड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना/ eLISA) परियोजना का क्या प्रयोजन है?

(a) न्यूट्रिनों का संसूचन करना
(b) गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना
(c) प्रक्षेपणास्त्र रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन करना
(d) हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वाल (सोलर फ्लेयर) के प्रभाव का अध्ययन करना

उत्तर–(b)

eLISA परियोजना के तहत तीन भिन्न-भिन्न लेकिन एक-दूसरे से संबद्ध अंतरिक्षयान शामिल हैं। ये अंतरिक्षयान एक त्रिकोणीय विन्यास में सूर्य की परिक्रमा करेंगे। ये तीनों अंतरिक्षयान संयुक्त रूप से एक परिशुद्ध इंटरफेरोमीटर की रचना करेंगे। ये इंटरफेरोमीटर 0.1mHz से 1HZ की आवृत्तियों की रेंज में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा।

38. 'विद्यांजलि योजना' का क्या प्रयोजन है?

1. प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना।
2. निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।
3. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों

से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 3

उत्तर—(a)

विद्यांजलि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी आदि तथा अन्य कोई भी व्यक्ति और संस्थान स्तर पर सरकारी, अर्धसरकारी अथवा कोई भी निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपना योगदान (शिक्षण, खेलकूद एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान) दे सकता है।

39. 'उन्नत भारत अभियान' कार्यक्रम का ध्येय क्या है?

(a) स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना।

(b) उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

(c) भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना।

(d) ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

उत्तर—(b)

उन्नत भारत अभियान ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण विकास क्रिया-कलापों से संबद्ध कर ग्रामीण विकास की चुनौतियों को दूर करने की रणनीति बनाई गई है। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के मध्य एक समझौता भी किया गया है। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण रणनीति के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की सहभागिता से विकास योजनाओं की दक्षता एवं सहभागिता में वृद्धि होगी।

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. **भारत का निर्वाचन आयोग पांच-सदस्यीय निकाय है।**
2. **संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।**
3. **निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तर—(d)

भारतीय संविधान के भाग-15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत का निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधायिका तथा संसद के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में है। इस प्रकार आम चुनाव और उप-चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। इसके अलावा निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है।

41. भारत में, यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो, तो इसका निहितार्थ क्या है?

(a) इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को।

(b) इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंद संरक्षण के अंतर्गत हैं; और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है।

(c) यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है।

(d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (b) और (c) दोनों सही हैं।

उत्तर—(a)

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्यजीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची (I) में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची (I) के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा, तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है।

42. भारत में, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है-

(a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।

(b) विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार।

(c) न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनों के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार।

(d) न्यायपालिका का, समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार।

उत्तर—(a)

भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है, जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं।

43. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए-

1. रॉयल इंडियन नेवी में गदर

2. भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ

3. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?

(a) 1-2-3 (b) 2-1-3

(c) 3-2-1 (d) 3-1-2

उत्तर—(c)

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन - 7 सितंबर - 11 दिसंबर, 1931
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ - 8 अगस्त, 1942
रॉयल इंडियन नेवी में गदर - 18 फरवरी, 1946

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर-राजस्व में सतत वृद्धि हुई है।

2. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(d)

राजकोषीय घाटा GDP प्रतिशत के रूप में

वर्ष	2008-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	2017-18 BE
प्रतिशत	6.0%	6.5%	4.8%	5.8%	4.9%	4.4%	4.1%	3.9%	3.5%	3.2%

GDP प्रतिशत के रूप में कर राजस्व प्रतिशत में

वर्ष	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
प्रतिशत	11.9%	10.8%	9.6%	10.1%	9.9%	10.2%	10.2%	9.7%	10.2%

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में भारत के कर राजस्व तथा राजकोषीय घाटे दोनों में ही उतार-चढ़ाव जारी रहा। राजकोषीय घाटा जहां वर्ष 2008-09 में GDP के 6.0 प्रतिशत था वह बढ़कर वर्ष 2009-10 में 6.5 प्रतिशत हो गया, वहीं पुनः वर्ष 2010-11 में यह कम होकर 4.8 प्रतिशत रह गया। पुनः वर्ष 2011-12 में यह 1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5.8 प्रतिशत हो गया। लेकिन वर्ष 2012-13 से इसमें लगातार कमी जारी है। इसी प्रकार कर राजस्व भी जहां वर्ष 2007-08 में GDP का 11.9 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 कम होकर क्रमशः 10.8 प्रतिशत एवं 9.6 प्रतिशत रह गया। पुनः वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2015-16 तक इसमें लगातार, कमी तथा वृद्धि जारी है। अतः स्पष्ट है कि न तो कथन (1) और न ही कथन (2) सत्य है।

45. हाल ही में, कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था?

(a) कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

(b) कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य

(c) मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य

(d) सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान

उत्तर—(b)

एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर अभयारण्य में भेजने/स्थानांतरित किए जाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति मार्च, 2017 के प्रारंभ में दे दी। समिति के अनुसार, कुनो पालपुर अभयारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों के दूसरे घर हेतु उपयुक्त हैं।

46. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?

1. राज्य विधान सभा का विघटन

2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना

3. स्थानीय निकायों का विघटन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, राज्य विधान सभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है।

47. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं?

1. मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी (बेगारी) का निषेध

2. अस्पृश्यता का उन्मूलन

3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1, 2 और 4	(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4	(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर—(c)

भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अतः कथन 1 और 4 सही हैं। इस प्रकार विकल्प (c) सही उत्तर है।

48. निम्नलिखित में से कौन-सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है?

(a) सुमात्रा	(b) बोर्नियो
(c) जावा	(d) श्रीलंका

उत्तर—(a)

ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6°45' N से 7° 15' N अक्षांश एवं 93°37' E से 93° 56' E के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किमी. दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी (145 किमी.) पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है।

49. निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए, जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है-

(a) ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम-से-कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है।

(b) ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि, जिसके उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

(c) सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।

(d) उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है।

उत्तर—(c)

संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोक सभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं।

50. निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है?

(a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

(c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है।

उत्तर—(d)

भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों (इकाइयों) को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा (India that is Bharat, shall be Union of States)। अतः विकल्प (d) भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है।

51. 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था-

(a) केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना।

(b) भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना।

(c) राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर-व्यवस्था अधिरोपित करना।

(d) भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना।

उत्तर—(d)

भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में वर्ष 1927 में एक समिति का गठन किया, जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन परमसत्ता और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और वर्ष 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत में सर्वोच्च (ब्रिटिश) सत्ता और देशी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने दोनों के वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

- इसकी आधारभूत सिफारिश थी कि सर्वोच्च सत्ता और देशी राजाओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखा जाए।
- देशी राजाओं को उनकी सहमति के बिना भारतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नई सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए विवश न किया जाए।
- रिपोर्ट में देश राजाओं की ये आशंकाएं प्रतिलक्षित थीं कि भारत में लोकप्रिय शासन प्रचलित होने से वे अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।
- भारतीय लोकमत ने इस रिपोर्ट को एक प्रकार से प्रतिगामी माना।

52. कभी-कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले 'घरेलू अंश आवश्यकता' (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) पद का संबंध किससे है?

(a) हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से

(b) हमारे देश में विदेशी टी.वी. चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से

(c) हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से

(d) विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से

उत्तर—(a)

घरेलू अंश आवश्यकता (DCR) पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी, 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) नाम दिया गया था, लांच की गई। इसके अनुसार, घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार, भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे- प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कूकर पर 30 प्रतिशत का अनुदान देती है।

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. परमाणु सुरक्षा शिखर-सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं।

2. विखंडनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(d)

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (NSS) का प्रादुर्भाव तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वर्ष 2009 में दिए गए भाषण के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने परमाणु आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए परमाणु सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बात कही थी। परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा और परमाणु आतंकवाद से बचने के उद्देश्य के साथ पहला एनएसएस वाशिंगटन डीसी में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया (2012), तीसरा द हेग, नीदरलैंड्स (2014) एवं चौथा सम्मेलन वाशिंगटन डीसी (2016) में आयोजित किया गया था। विखडंनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM) जनवरी, 2006 में स्थापित किया गया। यह परमाणु शस्त्र और गैर-परमाणु शस्त्र राज्यों के शस्त्र-नियंत्रक एवं गैर-प्रचारक विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है।

54. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मिलित हो सकता है?

(a) केवल निवासी भारतीय नागरिक

(b) केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति

(c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं

(d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं

उत्तर—(c)

राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे 1 जनवरी, 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18-60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक (निवासी अथवा अनिवासी) शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) जो 1 जनवरी, 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, भी इस योजना के पात्र हैं। अतः केवल विकल्प (c) ही सत्य है।

55. तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. तीस्ता नदी का उद्गम वही है, जो ब्रह्मपुत्र का है लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है।

2. रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है।

3. तीस्ता नदी, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1,2 और 3

उत्तर—(b)

तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित चोलामु झील से होता है, जो लगभग सात हजार मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंग्सी हिमनद है। इस प्रकार कथन (1) गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के रथोंग हिमनद से हुआ है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन (2) सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस प्रकार कथन (3) गलत है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वाइरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है, जिससे डेंगू संचरित होता है।

2. जीका वाइरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1　　(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों　　(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(c)

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वाइरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति (मुख्यतः एडीज इजिप्टी) का मच्छर होता है। यह वही मच्छर है, जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर रोग के कारक विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। स्पष्ट है कि कथन (1) एवं (2) दोनों सत्य हैं।

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का मानक चिह्न अनिवार्य है।

2. AGMARK, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी एक गुणता प्रमाणन चिह्न है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1　　(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों　　(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(a)

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards : BIS) भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण तथा दैनिक जीवन में मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी, 1947 में 'भारतीय मानक संस्था' (Indian Standards Institution : ISI) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) 1 अप्रैल, 1987 को संसदीय अधिनियम, 1986 के द्वारा अस्तित्व में आया जिसने भारतीय मानक संस्था (ISI) के कर्मचारियों, संपत्तियों एवं देनदारियों तथा कार्यों को ग्रहण करते हुए विस्तृत कार्यक्षेत्र और अधिक शक्तियों के साथ अस्तित्व में आया। इस संस्था का उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, चिह्नीकरण और उन्हें गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना तथा इन कार्यों से संबद्ध तथा अनुषंगी मामलों से संबंधित गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए लगभग 14000 से अधिक लाइसेंस जारी किए हुए हैं। आई.एस.आई. (ISI) का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख मानक चिह्न है। यह अधिकांशतः सभी संसाधित (Process) किए गए खाद्य उत्पादों सहित आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं जैसे विद्युत उपकरण, सीमेंट, लोहे के पाइप आदि पर लगाया जाता है। 'AGMARK' (एगमार्क) खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI) द्वारा जारी एक गुणता प्रमाणन चिह्न है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन करता है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 1935 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।

58. 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?

1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।

2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1　　(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों　　(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(c)

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (e-NAM) का शुभारंभ 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) को एकीकृत कर कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसानों को उनके उपज की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी (बेहतर) मूल्य प्राप्त होता है।

59. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए, केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1　　(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों　　(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(c)

भारत सरकार द्वारा 12 मई, 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का नारा ''रचनात्मक भारत, अभिनव भारत'' है। इस नीति के कार्यान्वयन का दायित्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) का होगा। यह नीति एक ऐसे भारत के निर्माण के विजन से प्रेरित है, जहां ज्ञान विकास का मुख्य वाहक हो तथा बौद्धिक संपदा से सभी लाभान्वित होते हों। यह नीति भारत सरकार की दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स (TRIPS) समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

60. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा, विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय, निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता?

1. घड़ियाल

2. भारतीय जंगली गधा

3. जंगली भैंस

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(d)

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है।

61. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है/हैं?

1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है।

2. ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(d)

भारतीय संविधान के भाग 4 (क) के अंतर्गत अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं हैं अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। अतः कथन (1) गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य, विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। अतः कथन (2) भी गलत है। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

62. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

1. राधाकांत देब -
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष

2. गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी-
मद्रास महाजन सभा के संस्थापक

3. सुरेंद्रनाथ बनर्जी -
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर–(b)

राधाकांत देब	-	ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष
गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी	-	मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक
सुरेंद्रनाथ बनर्जी	-	इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक
एम. वीरराघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लू	-	मद्रास महाजन सभा के संस्थापक

63. निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है?

(a) विचार की स्वतंत्रता (b) आर्थिक स्वतंत्रता

(c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (d) विश्वास की स्वतंत्रता

उत्तर–(b)

भारत के संविधान की उद्देशिका (The Preamble) में सन्निविष्ट स्वतंत्रताओं में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, श्रद्धा और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्देशिका में आर्थिक न्याय सन्निहित है न कि आर्थिक स्वतंत्रता।

64. 'भारतीय गुणता परिषद' (QCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. QCI का गठन, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति, उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(c)

भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India : QCI) की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से की थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों जैसे- एसोचैम (ASSOCHAM), सीआईआई (CII) तथा फिक्की (FICCI) के द्वारा किया जाता है। इस संगठन की स्थापना 'अनुरूपता मूल्यांकन निकायों' (Conformity assessment bodies) के लिए 'राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचे' (National accreditation structure) की स्थापना करने एवं उनके प्रचालन करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन (Accreditation) उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। प्रत्यायन ढांचे के तौर पर भूमिका अदा

करने के अलावा यह एन.ए.बी.सी.बी. (National Accreditation Board for Certification Bodies) के द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिए गुणवत्ता प्रबंधन, प्रणालियों (ISO 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISO 22000 श्रृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वयं के संस्थापन (Memorandum of Association) के साथ एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है जिसमें सरकार उद्योग तथा उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। क्यूसीआई (QCI) के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2014 में की गई थी। आदिल जैनुल भाई मैकेंजी इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं।

65. भारत में लघु वित्त बैंकों (SFBs) को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है?

1. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना

2. लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना

3. युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2	(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3	(d) 1,2 और 3

उत्तर–(a)

वित्तीय समावेशन को देशभर में फैलाने के लिए निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों (Small Finance Banks) व भुगतान बैंकों (Payments Banks) की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई, 2014 में केंद्रीय बजट में की थी। इन बैंकों की स्थापना के लिए अंतिम दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 27 नवंबर, 2014 में जारी किए। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य (1) मुख्यतः जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना तथा (2) लघु कारोबार इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी, कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है।

66. 'आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' (APMCHUD), के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय 'उभरते शहरी रूप - नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना' था।

2. भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी, ADB,APEC और ASEAN की सहभागिता से करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों	(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(d)

आवास और शहरी विकास और एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD) का आयोजन 13-16 दिसंबर, 2006 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था, जिसका विषय (Theme) था- 'वर्ष 2020 तक एशिया-पैसिफिक में सतत शहरीकरण हेतु एक दृष्टि'। छठवें सम्मेलन का आयोजन 14-16 दिसंबर, 2016 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय 'उभरते शहरी रूप-नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना' था। भारत इसके सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी नहीं करता है क्योंकि दूसरा सम्मेलन 12-14 मई, 2008 के मध्य तेहरान, ईरान में संपन्न हुआ था।

67. लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है-

(a) साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को।

(b) कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को।

(c) गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को।

(d) समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को

उत्तर–(a)

लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक-दूसरे से बात करते हैं, एक-दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं।

68. 'एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ' (यूनिफाइड पेमेंट्स इन्टरफेस/UPI) को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है?

(a) ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे।

(b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।

(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।

(d) निर्धन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज) का प्रत्यक्ष अंतरण (डाइरेक्ट ट्रांसफर) बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

उत्तर—(a)

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, जिसे RBI विनियमित इकाई के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है। यह IMPS अवसंरचना के आधार पर बना हुआ और किसी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेन-देन को स्मार्टफोन के माध्यम से संपन्न करता है। यह ग्राहक को एक बैंक खाते से विभिन्न व्यापारियों (Merchants) को ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, वह भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड या नेट बैंकिंग/वॉलेट पासवर्ड की परेशानी के। UPI का मुख्य लाभ लेन-देन करना सरल और आसान बनाना है। इसे बैंक खाते से लिंक करने के बाद वॉलेट की तरह टॉपअप किए बिना निर्बाध भुगतान किया जा सकता है। वॉलेट में पैसे हैं या नहीं की चिंता किए बिना सीधे बैंक स्थानांतरण के लिए UPI का प्रयोग करना आसान होता है।

69. कभी-कभी समाचारों में 'इवेंट होराइजन', 'सिंगुलैरिटी, 'स्ट्रिंग थियरी' और 'स्टैण्डर्ड मॉडल' जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं?

(a) ब्रह्माण्ड का प्रेक्षण और बोध

(b) सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन

(c) पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन

(d) पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रमविकास

उत्तर—(a)

इवेंट होराइजन- यह एक ऐसी सीमा (Boundary) है, जो अंतरिक्ष में ब्लैक-होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है।

सिंगुलैरिटी- यह अंतरिक्ष-काल (Space-time) में एक ऐसा स्थल है, जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है।

स्ट्रिंग थियरी - इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है।

स्टैंडर्ड मॉडल- कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है, जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात चार मूल बलों में से तीन (विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल) की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है।

70. भारत में कृषि के संदर्भ में, प्रायः समाचारों में आने वाले 'जीनोम अनुक्रमण' (जीनोम सीक्वेंसिंग) की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?

1. विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है।

2. यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है।

3. इसका प्रयोग फसलों में पोषी-रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1	(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3	(d) 1,2 और 3

उत्तर—(d)

जीनोम अनुक्रमण की कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका प्रयोग आनुवांशिक सूचकों की पहचान करने में किया जा सकता है, जो फसलों में रोग प्रतिरोधकता एवं सूखा सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने हेतु आवश्यक है। इससे नई फसलों को विकसित करने में कम समय लगता है। साथ ही यह फसलों में पोषी-रोगाणु संबंधों को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

71. संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि-

(a) कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

(b) यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है।

(c) कार्यपालिका, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है।

(d) सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता।

उत्तर—(c)

संसदीय स्वरूप के शासन के प्रमुख लाभ सरकार अर्थात कार्यपालिका का विधानमंडल (विधायिका) के प्रति उत्तरदायी होना है। इस शासन पद्धति में एक उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

72. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है?

(a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

(b) अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं।

(c) नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं।

(d) राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य, न कि अधिकार, महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर—(a)

भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म-विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं, तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति के असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार, समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार, कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

73. भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है?

(a) उद्देशिका (b) मूल अधिकार
(c) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (d) मूल कर्तव्य

उत्तर—(a)

भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका (The Preamble) में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

74. यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम-से-कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा?

(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

उत्तर—(b)

कोहिमा से कोट्टयम तक यदि सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण किया जाय, तो वह मार्ग नगालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों से होकर गुजरेगा। अतः कोहिमा से कोट्टयम तक की सड़क यात्रा करने पर कम-से-कम 7 राज्यों से अवश्य गुजरना पड़ेगा।

75. भारत की संसद किसके/किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है?

1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल
3. अनुपूरक प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1,2 और 3

उत्तर—(d)

भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न काल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है-

स्थगन प्रस्ताव - स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाय। स्थगन प्रस्ताव के लिए लाए गए विषय में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए-
(1) मामला निश्चित स्वरूप का होना चाहिए
(2) लक्ष्यपरक होना चाहिए तथा
(3) अविलंबनीय लोक महत्व का होना चाहिए।

प्रश्न काल- प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्न काल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में एक घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं।

अनुपूरक प्रश्न - संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न तीन श्रेणियों के होते हैं- तारांकित, अतारांकित एवं अल्पसूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों पर तारांक लगा होता है, इसलिए इसे तारांक प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब मौखिक रूप से संबंधित मंत्री को देना पड़ता है। तत्पश्चात प्रश्नकर्ता दो पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। अतः उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) है।

76. भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गैर-सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है, जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है।
2. हाल ही में, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर-सरकारी विधेयक पारित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(d)

गैर-सरकारी विधेयक उसे कहते हैं, जिसे संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुरःस्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जिसे किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुरःस्थापित किए जाते हैं। गैर- सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत लाई जाती है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोक सभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं-

(i) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समय नियत करना तथा

(ii) संविधान में संशोधन करने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उनकी जांच करना।

गैर-सरकारी विधेयक स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगभग दर्जन भर गैर-सरकारी विधेयक सदन में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपर्युक्त कथन में से न तो (1) सही है और न ही कथन (2) सही है।

77. ऋग्वेद-कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. ऋग्वेद-कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण (हेलमेट) का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता।

2. ऋग्वेद-कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था।

3. ऋग्वेद-कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1,2 और 3

उत्तर—(a)

ऋग्वेद में कचव (वर्म) का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद-कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण (हेलमेट) का प्रयोग करते थे। जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद-कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ई.पू.- 600 ई.पू. के मध्य हुआ था। अतः कथन (2) गलत है। ऋग्वैदिक-कालीन आर्यो ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा- मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की तीन मृण्मूर्तियां तथा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। अतः कथन (3) भी गलत है। इस प्रकार कथन (1) ही सही है। अतः सही उत्तर विकल्प (a) होगा।

78. 'पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम' (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम) का कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है?

(a) निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन
(b) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना
(c) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना
(d) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन

उत्तर—(a)

पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम निर्माण कार्यों में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल को प्रमाणित करने के लिए है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत आरपीएल (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम) एक प्रमुख तत्व है। इस स्कीम के अंतर्गत 2016-20 के बीच एक करोड़ लोगों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है और आरपीएल 40 लाख ऐसे उम्मीदवारों के लिए है जिनके पूर्व के अनुभव और कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा।

79. पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है?

(a) सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र (सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व)
(b) नल्लामला वन
(c) नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
(d) शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व)

उत्तर—(a)

सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र (सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व) पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा (Hyena), तेंदुआ (Leopard) इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।

80. समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें-

(a) विशेषाधिकारों का अभाव है
(b) अवरोधों का अभाव है
(c) प्रतिस्पर्धा का अभाव है
(d) विचारधारा का अभाव है

उत्तर—(a)

समानता, बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को सभी सुविधाओं तथा संसाधनों पर समान रूप से पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक प्रकार से नकारात्मक रूप में 'विशेषाधिकारों का अभाव' तथा सकारात्मक रूप में 'अवसरों की समानता' है। हेराल्ड लास्की के अनुसार, समानता के लिए समाज में किसी को विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है।

81. 'वाणिज्य में प्राणिजात और वनस्पति-जात के व्यापार-संबंधी विश्लेषण' (ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स/TRAFFIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. TRAFFIC, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्गत एक ब्यूरो है।

2. TRAFFIC का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(b)

'वाणिज्य में प्राणिजात और वनस्पति-जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण' (ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स-TRAFFIC) एक गैर-सरकारी संगठन (Non-government Organization) है। यह सतत विकास एवं जैव-विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। TRAFFIC का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। TRAFFIC की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है।

82. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था?

(a) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन
(b) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता
(c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार
(d) श्रमिकों के लिए निर्वाह-योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना

उत्तर—(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43(क) अर्थात उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43(क) के अनुसार, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों (Undertakings), स्थापनों (Establishments) या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

83. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं।
(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं।
(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं।

उत्तर—(c)

अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। अधिकार से ही मूलाधिकार एवं मानवाधिकार का जन्म हुआ है। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही (State action) के विरुद्ध प्रत्याभूति (Guarantee) है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।

84. निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक' (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स) का श्रेणीकरण प्रदान करता है?

(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) UN मानव अधिकार परिषद
(c) UN वूमन
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर—(a)

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2016 में आइसलैंड को पहला जबकि यमन को अंतिम (144वां) स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूचकांक में 87वां स्थान प्राप्त हुआ।

85. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है।

2. यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों के अभिज्ञान

की एक पहल है।

3. **यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है।**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तर—(b)

9 नवंबर, 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'स्मार्ट इंडिया हैक्थॉन, 2017' का उद्‌घाटन किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी प्रौद्योगिकी संस्थानों तक पहुंच बनाना तथा देश के समक्ष विद्यमान जटिल समस्याओं के अभिनव समाधान हेतु छात्रों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना था। स्मार्ट इंडिया हैक्थॉन, 2017 अखिल भारतीय स्तर पर लगातार 36 घंटे तक संचालित एक डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता थी जिसमें छात्र टीमों के मध्य किसी दिए गए समस्या कथन के अभिनव समाधान हेतु प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई।

86. मौद्रिक नीति समिति (मोनेटरी पॉलिसी कमेटी/ MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. **यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का निर्धारण करती है।**
2. **यह एक 12 सदस्यीय निकाय है, जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है।**
3. **यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर—(a)

सरकार द्वारा मौद्रिक नीति (नीतिगत दरों यथा - रेपो, रिवर्स रेपो आदि) के निर्माण एवं समीक्षा के लिए गठित छः सदस्यीय समिति जिसे वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित RBI Act, 1934 की धारा 45ZB के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है। इस समिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित तीन प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा गया है। इस छः सदस्यीय समिति में अध्यक्ष डॉ. उर्जित पटेल (RBI Governer) के अलावा उपगवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य और कार्यकारी निदेशक डॉ. माइकल देवब्रत पात्र (रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि) जबकि प्रो. चेतन घाटे, प्रो. पामी दुआ एवं प्रो. रवींद्र ढोलकिया सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मनोनीत हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा तथा समिति की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम 4 बार आयोजित होगी।

87. मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. **यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है।**
2. **केवल करताल (सिंबल) ही वह एकमात्र वाद्ययंत्र है, जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है।**
3. **यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

उत्तर—(b)

संकीर्तन, विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक अवसरों और वैष्णव लोगों के जीवन में विभिन्न चरणों को चिह्नित करने के लिए मणिपुर के मैदानों में मंदिरों और घरेलू स्थानों पर प्रदर्शन की जाने वाली कलात्मक गायन, ड्रमिंग और नृत्य कला का एक रूप है। संकीर्तन का प्रदर्शन मंदिर के केंद्र में किया जाता है। इसमें दो मृदंग वादक और लगभग दस गायक तथा नर्तक गायन नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस नृत्य में पुंग चोलो (मृदंग) का प्रयोग होता है। अतः इसे मृदंग कीर्तन, पुंग चोलो या धूमल अथवा नाटक नृत्य भी कहा जाता है। संकीर्तन को वर्ष 2013 में भारत की ओर से यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में नामांकित 14 तत्वों में से एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। केवल करताल (सिंबल) नामक वाद्ययंत्र का प्रयोग नूपा नृत्य में किया जाता है।

88. निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था/थे?

1. **लॉर्ड कॉर्नवालिस**
2. **अलेक्जेंडर रीड**
3. **थॉमस मुनरो**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर—(c)

रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू-राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अजेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसीडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ई. में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। थॉमस मुनरो ने 1809 ई. में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ई. में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एलफिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसीडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51 प्रतिशत क्षेत्र (मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग) में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे

या व्यक्तिगत रूप से भू-राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ई. के बाद विगनेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1791 ई. में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जो कि प्रारंभ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दस वर्षीय बंदोबस्त था, जिसे 1793 ई. में 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी' की अनुमति से स्थायी कर दिया गया।

89. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में, जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक के कौन-सा/से लाभ है/हैं?

1. यह प्रकृति में घटित होने वाली जैवनिम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है।

2. कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है।

3. जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी (जेनेटिक इंजीनियरिंग) का उपयोग किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर—(c)

सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले (Toxic) प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैवोपचारण (Bio-remediation) कहलाती है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैवनिम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। परंतु कई प्रकार की भारी धातुओं से युक्त प्रदूषकों को जैवपचारण विधि द्वारा नहीं उपचारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित नहीं किया जा सकता है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी (जेनेटिक इंजीनियरिंग) का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणतया, सुपरबग Pseudomonas putida जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है। समुद्र में फैले तैलीय पंक (Oil Spill) को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

90. 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट) निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है?

(a) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी
(b) औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति
(c) व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप
(d) अधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक

उत्तर—(d)

वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर पांच वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड (Board of Conciliation) तथा जांच न्यायालय (Court of inquiry) के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया।

91. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है-

(a) संघवाद का
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर—(b)

स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत अधिक बल दिया था। विलंब से ही सही 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की स्थापना करके तथा उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करके एक सराहनीय कार्य किया गया है। संविधान का भाग-9, 73वें और भाग 9-क, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़े गए। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और 74 वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। उपर्युक्त संशोधन अनुच्छेद 40 के अनुसरण में किया गया है। पंचायती राज तथा नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण है।

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व

1. विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं।

2. कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर—(d)

नीति निदेशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित 'लोक हितकारी राज्य' एवं 'समाजवादी समाज' की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे। आज हम एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं, जिसका कर्तव्य जन साधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से नीति निदेशक सिद्धांतों में कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है, जिसका पालन राज्यों को करना अभीष्ट है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जनता के हित तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के

लिए इनको यथाशक्ति कार्यान्वित करने का प्रयास करें। अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन हैं और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन।

93. समाचारों में आने वाला 'डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति' (डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी) पद किसे निर्दिष्ट करता है?

(a) ASEAN को (b) BRICS को

(c) EU को (d) G20 को

उत्तर—**(c)**

डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति का संबंध यूरोपीय संघ (European Union) से है। इसे संघ के देशों के मध्य व्यापार में आने वाले अवरोधों को दूर करने तथा भावी व्यापार एवं रोजगार संभावनाओं के दोहन हेतु अपनाया गया है।

94. भारत में एक ऐसा स्थान है, जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि दिन में दो बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है और जब जल पीछे हटा होता है, तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहां देखी जाती है?

(a) भावनगर में

(b) भीमुनिपटनम में

(c) चांदीपुर में

(d) नागपट्टिनम में

उत्तर—**(c)**

उपर्युक्त परिघटना ओडिशा राज्य के चांदीपुर समुद्री तट पर घटित होती है। ऐसा दिन में दो बार ज्वार-भाटे के कारण होता है।

95. 'बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988' (PBPT अधिनियम) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा, यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है।

2. बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी।

3. यह अधिनियम जांच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर—**(b)**

बेनामी संपति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 वर्ष 2016 में संशोधित हो चुका है। इसे बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 कहा जाता है। कथन (1) इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई विधि का उल्लंघन करे और यह कहे कि मुझे विधि का ज्ञान नहीं था, यह क्षमायोग्य नहीं है। अतः कथन (1) असत्य है। कथन (2) सत्य है क्योंकि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार बिना प्रतिकर दिए जब्त कर सकती है। कथन (3) भी असत्य है, क्योंकि उक्त अधिनियम में अपील का प्रावधान है।

96. कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति (स्पीशीज) की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इसका/इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता/सकते है/हैं?

1. कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2. कुछ कृष्य पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है।

3. इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर—**(c)**

तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य (Lower Member) के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढ़क, सर्प इत्यादि का भोजन हैं। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

97. शैवाल आधारित जैव-ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा/सीमाएं है/हैं?

1. शैवाल आधारित जैव-ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं।

2. शैवाल आधारित जैव-ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरी करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता/प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है।

3. आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर–(b)

शैवाल आधारित जैव-ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। अतः कथन (1) असत्य है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है, साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

98. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन) के उद्देश्य हैं?

1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।
2. छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना।
3. बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।
4. मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

उत्तर–(a)

राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 200 गंभीर स्थिति वाले जिलों में बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना तथा छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना है। मोटे अनाजों तथा मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। बजट 2017-18 में इस मिशन हेतु 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन 175 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। यह सरकार की महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

99. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फैक्टरी एक्ट, 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था।
2. एन. एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(b)

प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में पारित किया गया था। परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे (Narayan Meghaji Lokhande) भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं। बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। अतः केवल कथन (2) सत्य है।

100. कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा/से संभावित स्थान हो सकता/सकते है/हैं?

1. परित्यक्त एवं गैर-लाभकारी कोयला संस्तर
2. निःशेष तेल एवं गैस भंडार
3. भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर–(d)

कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाईऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर-लाभकारी कोयला, संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं।

सामयिक प्रश्न-कोश

Q. 15 जून, 2017 को उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया?

A. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (भारत में जनहित याचिका के प्रणेता) का।

Q. 14 जून, 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने एक समझौते के तहत संयुक्त रूप से किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है?

A. महाराष्ट्र (रत्नागिरि जिला)।

Q. 15 जून, 2017 को जारी 'वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2017' में भारत का कौन-सा स्थान है?

A. 60वां।

Q. 14 जून, 2017 को घोषित वर्ष 2017 के 'मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज' के विजेता कौन हैं?

A. डेविड ग्रॉसमैन (इस्राइल) एवं जेसिका कोहेन।

Q. 11 जून, 2017 को संपन्न फ्रेंच ओपन, 2017 का खिताब किसने जीता?

A. राफेल नडाल (स्पेन) ने।

Q. जून, 2017 में किस चित्रकार की 'फॉलिंग फिगर' सीरीज की एक पेंटिंग की बिक्री 4.27 करोड़ रुपये में हुई?

A. तैयब मेहता की।

Q. 7 जून, 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, किसानों के लिए कौन-सी एक नई ऋण राहत योजना शुरू की जाएगी?

A. कृषि ऋण समाधान योजना।

Q. विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है?

A. 14 जून को।

Q. 7-11 अक्टूबर, 2017 के मध्य कोलोन, जर्मनी में आयोजित होने वाले खाद्य उद्योग से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच अनुगा (ANUGA) का भागीदार (Co-partner) देश कौन होगा?

A. भारत।

Q. 15-17 जून, 2017 के मध्य ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की सातवीं बैठक कहां आयोजित की गई?

A. नानजिंग, चीन में।

Q. 11 जून, 2017 को किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की गई?

A. महाराष्ट्र सरकार द्वारा।

Q. जून, 2017 में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी विवाह हेतु ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने की घोषणा की गई है?

A. केरल सरकार द्वारा।

Q. जून, 2017 में संपन्न फीफा U-20 विश्व कप, 2017 का खिताब किस देश ने जीता?

A. इंग्लैंड।

Q. 10 जून, 2017 को नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए कौन-से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है?

A. 'साथ' (SATH) अर्थात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल।

Q. 8-9 जून, 2017 के मध्य 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 17वीं शिखर बैठक का आयोजन कहां संपन्न हुआ?

A. अस्ताना, कजाख्स्तान में।

Q. जून, 2017 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2018 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है?

A. मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) को।

Q. 13 जून, 2017 को 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) ने राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के रेगिस्तान में कौन-सी स्वदेश निर्मित टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया?

A. नाग का।

Q. 7 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) का नया स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया?

A. के.जी. कर्माकर और गौरी शंकर को।

Q. 8 जून, 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा को किस कार्य हेतु डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

A. वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु।

Q. 7 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने नया रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स किसे नियुक्त किया?

A. होशियार सिंह को।

Q. 1 जून, 2017 को 'टी-वॉलेट' (T-Wallet) नामक अपनी आधिकारिक ई-वॉलेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा है?

A. तेलंगाना।

Q. 1 जून, 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस समझौते से अपने देश को अलग करने की घोषणा की?

A. पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से।

Q. 19 मई, 2017 को संपन्न ईरान के राष्ट्रपति चुनावों में कौन विजयी हुआ?

A. हसन रुहानी (द्वितीय कार्यकाल)।

A. 5 जून, 2017 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा इम्फाल (मणिपुर) में पूर्वोत्तर राज्यों हेतु किस कार्यक्रम को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की घोषणा की गई?

A. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (HADP) को।

Q. विश्व महासागर दिवस (8 जून), 2017 का मुख्य विषय (Theme) क्या है?

A. हमारे महासागर, हमारा भविष्य।

Q. 7 जून, 2017 को नॉर्वे की सरकार, ओस्लो विश्वविद्यालय और नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनीशिएटिव (NIPI) के सहयोग से नई दिल्ली स्थित 'लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज' (LHMC) में 'वात्सल्य-मातृ अमृत कोष' की स्थापना हुई है, यह क्या है?

A. एक राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र।

Q. 7 जून, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी (SEBI) और किस देश के प्रतिभूति एवं विनिमय संगठन (SEO) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी?

A. ईरान के।

Q. जून, 2017 में कौन-सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना?

A. मोंटेनेग्रो।

Q. 24 मई, 2017 को वर्ष 2016-17 के लिए किस खिलाड़ी को 'सिएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड प्रदान किया गया?

A. आर. अश्विन (भारत) को।

Q. 6-7 जून, 2017 के मध्य 'एसडीआरएफ' (State Disaster Response Forces) के क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 2017 का आयोजन कहां किया गया?

A. नई दिल्ली में।

Q. 5 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की है?

A. आंध्र प्रदेश में।

Q. 2 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) किसे नियुक्त किया?

A. शशि शेखर वेमपति को।

Q. 30 मई, 2017 को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए जारी द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी फसलों का उत्पादन कितना होने का अनुमान है?

A. 295 मिलियन टन से अधिक।

Q. वर्ष 2018 में जी-7 राष्ट्रों की 44वीं शिखर बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा?

A. कनाडा में।

Q. 5 जून, 2017 को इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III-डी1 द्वारा किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया?

A. जीसैट-19 का।

Q. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), 2017 का मुख्य विषय (Theme) क्या है?

A. लोगों को प्रकृति से जोड़ना।

Q. 1 जून, 2017 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ओडिशा में राज्य के पहले एमआईटीएस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का कहां पर उद्घाटन किया?

A. रायगढ़ में।

Q. 31 मई, 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया?

A. प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया को।

Q. 25 मई, 2017 को किसे जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय का नया चांसलर चुना गया?

A. डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला को।

Q. 29 मई, 2017 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने लीची प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया?

A. मुजफ्फरपुर, बिहार में।

Q. 29 मई, 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित किस ऐप का शुभारंभ किया?

A. एंटी-रैगिंग मोबाइल ऐप का।

Q. 26 मई, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में देश के सबसे लंबे नदी सेतु ढोला सदिया (9.15 किमी.) का उद्घाटन किया गया। इस सेतु का नामकरण किस संगीतकार एवं गीतकार के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है?

A. भूपेन हजारिका के।

Q. 14-17 मई, 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन हैं?

A. महमूद अब्बास।

Q. 11-12 मई, 2017 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा संपन्न की?

A. श्रीलंका की।

Q. 11 मई, 2017 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किस केंद्र का शुभारंभ किया गया?

A. राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (NCC)।

Q. 3 मई, 2017 को मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा एकदिवसीय विशेष सत्र के दौरान किस नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया?

A. नर्मदा नदी को।

Q. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 'स्वच्छ भारत मिशन' द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया जाएगा?

A. गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट।

Q. 25 मई, 2017 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जल संचयन एवं संरक्षण संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई?

A. उत्तराखंड के।

Q. मई, 2017 में भारतीय महिला बॉक्सरों के लिए प्रथम विदेशी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. स्टीफेन कोट्टालॉर्डा (फ्रांस) को।

Q. 26 मई, 2017 को 'कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण योजना-संपदा' की शुरुआत कहां की गई?

A. असम में।

Q. वर्ष 2018 में नाटो (NATO) के सदस्य देशों की बैठक कहां आयोजित होगी?

A. इस्तांबुल (तुर्की) में

Q. 23 मई, 2017 को केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए शुरू किए गए 'सेवा' (SEVA) ऐप का पूर्ण नाम क्या है?

A. सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन (SEVA)।

Q. 26 मई, 2017 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया?

A. सैयद गैरूल-हसन रिज़वी ने।

Q. मई, 2017 में जयपुर में आयोजित 19वें आर्केशिया फोरम, 2017 की मुख्य थीम क्या थी?

A. ऑर्किटेक्चर के माध्यम से खुशी।

Q. 22 मई, 2017 को टाटा संस ने टाटा समूह का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) किसे नियुक्त किया?

A. सौरभ अग्रवाल को।

Q. मई, 2017 में 'अंतरराष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम' (ISSF) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2016 में विश्व का शीर्ष स्टेनलेस स्टील उत्पादक देश चीन है। इस दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है?

A. भारत का।

Q. 24 मई, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (AIIMS) की स्थापना को मंजूरी कहां पर प्रदान की?

A. कामरूप (असम) में।

Q. 23 मई, 2017 को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) का नया महानिदेशक किसे चुना गया?

A. डॉ. टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस को।

Q. 2 मई, 2017 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा लक्जरी रेल महाराजा एक्सप्रेस के दो नए सर्किट शुरू करने का निर्णय किया गया। इन दोनों सर्किटों का नाम क्या है?

A. सदर्न सोजर्न एवं सदर्न ज्वेल्स।

Q. 22 मई, 2017 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई) से कर्माली (गोवा) स्टेशन के बीच देश की पहली उच्च गति की किस वातानुकूलित ट्रेन की शुरुआत हुई?

A. तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की।

Q. मई, 2017 में संपन्न हीरो फेडरेशन कप, 2017 का 38वें संस्करण का विजेता कौन रहा?

A. बंगलुरू एफसी।

Q. मई, 2017 में अरुणाचल प्रदेश (भारत) की किस महिला पर्वतारोही ने एक सप्ताह के अंदर दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?

A. अंशु जामसेनपा।

Q. 16 मई, 2017 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया?

A. प्रो. तारिक मंसूर ने।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी संतोष कुमार चौधरी द्वारा उन्हीं के लिए अमर मुद्रणालय 15/1/7 कटरा रोड माधो कुंज इलाहाबाद से मुद्रित
एवं 188A/128 एलनगंज, चर्चलेन, इलाहाबाद से प्रकाशित। संपादक-संतोष कुमार चौधरी।